हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 1993

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 11 मार्च, 1993

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)19
विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना	(12)20
क्लैरिफिकेटरी स्टेटमैंट–	(12)22
भानू इंडस्ट्रीज को हरियाणा फाइनैंि ायल कारपोरे ान द्वारा ऋण देने सम्बंधी	(12)
सदस्यों का नाम लेना	(12)24
विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना (पुनरारम्भ)	(12)30
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–	(12)36

(1) पलवल भाहर के मकानों में दरारें पडने संबंधी	
वक्तव्य– स्थानीय भाासन राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(12)36
(2) पानीपत थर्मल पावर प्रोजैक्ट द्वारा किये जा रहे प्रदूशण संबंधी	(12)40
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(12)40
बैठक का समय बढ़ाना	(12)72
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)72
बैठक का समय बढ़ाना	(12)84
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)84
बैठक का समय बढ़ाना	(12)93
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)93

बैठक का समय बढ़ाना	(12)99
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)99
बैठक का समय बढ़ाना	(12)106
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)106
बैठक का समय बढ़ाना	(12)112
वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)113

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 11 मार्च, 1993

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Providing Canal Water

***445. Sh. Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide canal water to the Janta College Campus, Charkhi Dadri; and

(b) if so, the time by which the canal water is likely to be provided ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Janta College Campus, Charkhi Dadri gets its share of canal water from out let RD 51000-R, Badhwana Distributary.

(b) Question does not arise.

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, यह चैनल कालेज ने अपने खर्च पर बनाया है और सरकार ने आ वासन दिया था कि हम पानी देंगे लेकिन वहां एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इसकी तहकीकात करेंगे कि वहां पर पानी गया है, अगर गया है हो कितना; यदि नहीं, तो कब तक जाने की सम्भावना है ?

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, यह चैनल आर0डी0 51000—आर0 आउटलेट है जो बदवाना डिस्ट्रीबयूअरी का है। उस पर चरखी दादरी का जो कालेज या कैम्पस है, उसकी बाराबन्दी हुई है और इसको 3 घण्टे 18 मिनट के हिसाब से पानी मिलता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कुछ वाटर कोर्स तो पक्का बना हुआ है और कुछ कच्चा है। जो कच्चा हिस्सा है, उसमें मिटटी पड जाती है, जिसके कारण कालेज या कैम्पस तक पानी नहीं जाता है। इनको एच0ई0 ने कहा है कि आप अपनी बारी के मुताबिक खाल खेद कर पानी ले जाएं, हमें कोई एतराज नही ंहे। क्योंकि आपकी बाराबन्दी कैनाल ड्रैनेज ऐक्ट 1968 के तहत बनी हुई है, उसके मुताबिक आप 3 घण्टे 18 मिनट पानी ले सकते हैं।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, यहे जो 3 घण्टे 18 मिनट पानी देने की बात है वह तो ठीक है क्योंकि जितनी जमीन होगी उसके मुताबिक पानी जाएगा। वह खाल जितना पक्का बना हुआ है और उसके बाद जितना कच्चा बना हुआ है, वह

कालेज ने ही तैयार करवाया है, लेकिन वहां पर पानी नहीं जा रहा है। इस बारे में हमने ग्रीवेसिंज कमेटी में भी बार बार सवाल उठाया है। कागजों में तो लिखा हुआ है कि पानी जा रहा है लेकिन वास्तव में पानी नहीं जा रहा है। तो क्या मंत्री जी हाऊस में आ वासन देंगें कि वहां पर पानी कैम्पस तक जाएगा ?

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि कालेज की 42 कनाल और कुछ मरले जमीन है। जो 1968 से बाराबन्दी बनी हुई है, उसके मुताबिक उनको 3 घण्टे 18 मिनट पानी दिया जाता है। खाल वहां से खोद रखी है तो उसमें पानी न जाने का कोई औचित्य नहीं है जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि खाल का जो कच्चा हिस्सा है, उसमें मिटटी गिर जाती है और वह कटिंग में है। उसमें मिटटी भरने की जवह से पानी नहीं जाता होगा। मिटटी की सफाई करने का काम तो ऐजुके ान सोसाइटी का है। ऐजुके ान सोसाईटी वाले ही उसमें से मिटटी निकालें और अपनी बाराबन्दी के हिसाब से पानी लें।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे कि कैनाल ऐक्ट 14968 के तहत बाराबन्दी बनने के बाद पानी देने की जिम्मेवारी महकमे की नहीं है। जब खाल बन गई तो क्या इन्होंने जांच की कि पानी खाल में जा रहा है या नहीं ? अगर पानी नहीं जा रहा है तो क्या अब मंत्री जी हाऊस में अ योंरेंस देंगे कि वहां पानी जल्दी ही जाने लग जाएगा।

श्री अध्यक्षः उस खाल को खुदवाना किसकी जिम्मेवारी है ?

श्री अमर सिंहः सर, खाल तो खोदा हुआ है, पक्का बना हुआ है, लेकिन चार पांच साल से वहां पानी नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिय है कि उस खाल में मिटटी गिर जाती है, जिसके कारण वह अन्ट जाती है और कैम्पस तक पानी नहीं पहुंच पाता। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि जब 1968 में पक्की बाराबन्दी हो गई है, तो उसके बाद, this is the duty of the Canal department to give water to the Campus.

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उसमें मिटटी गिर जाती है और ऐजुके ान सोसाईटी का काम है कि मिटटी निकाले और हर बार, अपनी बाराबन्दी के मुताबिक पानी ले। उस सोसाइटी ने अथोरिटीज को कहा है कि वे अलग से मौघे लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अलाइनमैंट बता दें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां जहां से अलाइनमैंट लेना है, हमें बता दें हम आपको अलग मौघें दे देंगें। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिन हिस्सेदारों की जमीन में से खाल ले जाना है, आप उनके नाम भी बता दें हम उनको भी पानी देने के लिए तैयार हैं खाल में जहां बार बार मिटटी गिर जाती है, उसको निकालने का काम तो एजुके ान सोसायटी का है, वे डिगिंग करके निकालें, यह काम सरकार का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सोसायटी

का काम है। हर बार जो मिटटी वाटर कोर्स में गिर जाती है, उसको निकाल कर वहां तक पानी पहुंचायें। मिटटी निकालने का काम हमारा नहीं है। अगर आप अलग से मौघे लेने की बात करते हैं तो हम देने के लिये तैयार हैं। इसके अलावा, यदि सोसायटीज उस वाटर कोर्स को पक्का करने के लिए कहेंगी तो सरकार पक्का करने की कोि ा ा करेगी।

चौधरी औम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्र न नम्बर 445 के पार्ट "ए" के जवाब में कहा है कि जनता कालेज चरखी दादरी को नहर का पानी, उसकी जमीन के मुताबिक ही मिला है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पानी मिल ही रहा है तो फिर प्र न के पार्ट "बी" के जवाब में, इन्होंने यह क्यों कह दिया कि Question does not arise ?

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, इन्हौंने आगे यह भी पूछा है कि "If so, the time by which the canal water is likely to be provided ?" When we have already provided water; then why we will say this ? (Interruptions). Mr. Speaker, Sir, whatever they have asked, I have given reply according to their quesiton.

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः ठीक है, उसके मुताबिक तो आपने जवाब दे दिया लेकिन वहां पर पानी नहीं जा रहा है। (ाोर)

Ch. Jagdish Nehra: When we have already provided the share of canal water according to varabandhi, then there is not quesiton of providing more canal water. That is why question does not arise (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में गन्नीकी, चिरवाडी, सूजवाडी, पेलक, सोहाल, चार, घोडी आदि गांवों में पीने का पानी नहीं जा रहा है जबकि वहां पर माईनर भी खुदे हुए हैं ?

श्री अध्यक्षः राम रतन जी, आपका यह प्र न इस प्र न से संबंधित नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर नाला अटा हुआ नहीं है बल्कि नाला बना हुआ है और उसमें मिटटी गिरने वाली बात भी नहीं है लेकिन वहांपर चार साल से पानी की एक बूंद भी नहीं गयी है। यह क्वै चन आने के बाद वहां पर पानी डिग्गी तक जरूर पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कम से कम आठ या दस हजार बच्चे स्कूल में पढते हैं, जिनको पीने कापानी नहीं मिलता। इसलिए मेरी आपके माध्यम से गुजारि ा है कि मंत्री जी हाउस में यह आ वासन दें कि वहां पर बाराबन्दी के हिसाब से पानी मिलेगा ? वहां पर खुदाई की भी कोई प्रौब्लम नहीं है।

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जब खुदाई की भी प्रौब्लम नहीं है और बाराबन्दी भी बनी हुई है तो फिर प्रौब्लम क्या है ? आप यह कहते हो कि बाराबन्दी है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता। जब बाराबन्दी चल रही है और खाल भी खुदी हुई है तो फिर प्रौब्लम क्या है ? यदि इनको खाल पर कोई दिक्कत है तो यह हमें बताएं। इनकी सोसायटी के मैम्बर श्री रामकि ान जी ने मुख्य मंत्री जी को चिटठी लिखी है। इस पर विभाग के एस0ई0 ने उनसे पूछा कि यदि आपको दूसरे वाटर कोर्सिज की जरूरत है तो वे देने के लिए तैयार हैं लेकिन जब बाराबन्दी चालू है तो पानी जरूर जाता होगा।

श्री अध्यक्ष: धर्मपाल जी, आप इसका कोई सौल्यू ान बताएं।

श्री धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका सोल्यू ान यही है कि अगर नेहरा साहब की नीयत ठीक हो जाए तो पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि चालीस ले लो, साठ ले लो। तो मैं चाहता हूं कि ये यहां पर वायदा करें कि वहां पानी पहुंच जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया है। ऐसा है कि वाटर कोर्सिज दो तरह के होते हैं। एक वाटर कोर्सिज तो वे होते हैं जिनके द्वारा नहर या माईनर से किसान के खेत में पानी जाता है और अगर किसान

उन्हें पक्का कराना चाहते हैं तो सरकार पक्का करती है लेकिर दूसरे कच्चे वाटर कोर्सिज को ठीक रखना या मिटटी निकालना, किसानों का काम है जो इनसे पानी लगाते हैं। इसके अलावा, जो हमारे जनरल वाटर कोर्सिज बने हुए हैं जिनसे पीने के पानी की सप्लाई करते हैं, उनकी देखभाल सरकार करती है। जो प्राईवेट वाटर कोसिर्ज हैं, जैसे आपने स्कूल के लिए पानी ले रखा है, उसकी बाराबन्दी बनी हुई है और वह वाटर कोर्स ठीक नहीं है, उसमें मिटटी गिर जाती है तो उसकी सफाई करने का काम उस स्कूल की एजूके ान सोसायटी का है, सरकार का नहीं है। सरकार का काम तो यह है कि उसकी बाराबन्दी ठीक चले, बाराबन्दी में कोई गडबड न हो। अगर बाराबन्दी में कोई गडबड नहीं है तो वह आप हमारे नोटिस में लाएं, हम उसको ठीक करेंगे लेकिन उस खाल के रख रखाव का काम उस कालेज की एजूके ान सोसायटी का है।

Construction of Bridge on Jamuna

***497. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bridge in Khadar area of Ballabgarh on the Jamuna; and

(b) if so, the time by which the afore said bridge is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, केवल यह प्रयोजना क्रियात्मक है या नहीं, इसका अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि खादर का जो इलाका है यह मैरे पलवल हल्के का नहीं है, यह बल्लभगढ का है और कई सालों से वहां के लोग मांग करते आए हैं कि उन्हें अलीगढ रोड से होते हुए दिल्ली से यू0पी0 जाना पडता है। वहां पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपको बता दिया गया है कि सर्वे करा रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सर्वे हुआ पडा है, सदन के नेता जिन्होंने वहां से चुनाव लडा था और जो 666 वायदे इन्होंने फरीदाबाद जिले के लोगों से किए हैं, उनमें सबसे प्रमुख यह भी था कि बल्लभगढ के खादर के इलाके में यह पुल बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह हल्का मेरा नहीं है बल्कि राजेन्द्र सिंह जी बिसला का इलाका है, इसलिए क्या मुख्यमंत्री जी कम से कम इस पुल को बनवाएंगे ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी, आप बैठिए। धीरपाल सिंह जी, आप भी बैठिए। you are not allowed to speak without permission. (Interruptions).

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई श्री कर्ण सिंह दलाल ने सै ान में बडा ही महत्वपूर्ण प्र न पूछा है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं जो इस एरिए का सर्वे करवा रहे हैं। इनका एक वायदा भी था और हमारे जिले के लोगों की एक बडी पुरानी डिमांड भी चली आ रही थी कि बदरपुर जहां से हरियाणा भाुरू होता है, से होडल तक, यमुना का एक मात्र पुल है और कई हजार एकड जमीन यमुना से परली तरफ हरियाणा की है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने वहां सर्वे टीम भेजी ओर फंडज भी अलोट किए। टीम सर्वे कर रही है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर फिजीब्लिटी बनती है तो क्या इसी साल में इस पुल को बनाने की कोि ा ा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, ये बडी भारी समस्या थी और मैंने वहां से लोकसभा चुनाव लडा था। मैंने उस समय कहा था कि जब राज हमारा बनेगा तो हम जरूर यह काम करेंगे। परमात्मा की दया से, जनता की कृपा से राज कांग्रेस का आ गया और मैं मुख्य मंत्री बन गया। उन लोगों की मांग जायज है, उसको पूरा करना चाहिए इसी बात को लेकर हमने सर्वे करा लिया और सर्वे हो चुका है। फंडज भी अलाट किए हैं। 14 गांव हैं जो सारे के सारे तीन महीने के लिए कट जाते हैं लोग

भाहर नहीं आ सकते, इसलिए पुल बनाना बहुत जरूरी है। मैं हाउस को वि वास दिलाना चहाता हूं कि फंडज की अवेलेब्लिटी भी जरूरी है लेकिन फिर भी हम कोि ा ा करेंगे कि अगला जो चालू साल है, यानी जो अप्रैल से भाुरू हो रहा है, उसमें कुछ फंडज देकर काम करना भाुरू कर देंगे।

Extension of Kansala Minor

***506. Ch. Balwant Singh Maina:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to extend Kansala minor upto village Kharanti; if so, the time by which it is likely to be extended ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): No Sir.

चौधरी जिले सिंह जाखडः स्पीकर साहब, इस माइनर की कैपेसिटी अच्छी है और माइनर भी ठीक चलती है। अगर इसको खंराती गांव तक बना दिया जाए तो लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी तथा चांद और भगवतीपुर गांवों की जमीन भी सिंचाई से अच्छी हो जाएगी। नम्बर दो, इस माइनर का विस्तार होने से इन तीनों गांवों की पानी की सप्लाई भी अच्छी हो जाएगी। क्या मंत्री महोदय इसका सर्वे कराकर इस पर काम भाुरू करवाएंगे ?

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, सर्वे कराया गया था, कन्साला भालोट डिस्ट्रीब्यूटरी पर कार्यवाही हो सकती है और

यहां का सवाल भी ठीक है। यह मामला अंडर इंवैस्टीगे ान है और भालोट डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी सप्लाई किया जाएगा।

Construction of a Road

***512. Sh. Ram Kumar Katwal:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a road from village Kharka gadian to Dhatrath, in District Jind; if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): जिला जीन्द में गांव सडक गोदियां से ढाटरथ तक सडक के निम्रण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, हाउस से बाहर निकल कर मंत्री महोदय कहते हं कि आपको यहां एक दो सडकें बनवाऊंगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि मेरे यहां वे कौन सी सडक बनवाएंगे ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, अगर कोई ऐसी सडक है। जो गांव से अटैचड नही ंहै, को हम जरूर बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस समय जिला जिन्द में खडक गोदियां से ढाटरथ तक सडक के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि यह सडक पहले ही दोहरी सडक है। मांगी हुई सडक साढे तीन किलोमीटर की है जिसके बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि यह पहले ही दोहरी सडक है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, नेहरा साहब, डांगी जी और बहिन भाान्ति जी हर सवाल का जवाब 'ना' में देते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पी0डब्ल्यू0डी0 ने पिछले दो साल में कितनी लम्बी सडक बनाई है और अगले फाइनैंि ायल ईयर में कितनी बनाने जा रहे हैं ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, पिछले साल 102 किलोमीटर सडक बनाई थी और अगले साल 110 किलोमीटर बनाने का विचर है।

श्रीमती भाान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, मैं कादियान जी को बताना चाहती हूं कि 181 स्कूल बनाए हैं और सडक तथा स्कूलों के बनोने की निरन्तर प्रक्रिया हैं

श्री कृश्ण लालः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक साल के दौरान हर डिस्ट्रिक्ट में कितना रूपया नई सडक बनाने पर खर्च किया और कितना पैसा रिपेयर पर खर्च किया है ?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंटरी मेन क्वै चन से कनैक्टिड नहीं है।

Support Price

***535. Ch. Birender Singh:** Will the Minister for Ariculture be pleased to state-

(a) whether the State Govt. has sent its recommendations to the Govt. of India for the enhancement of the minimum support price of wheat and other crops in coming procurement season; and

(b) whether the State Govt. also propose to give any bonus in the wheat procurement in the coming procurement season ?

Agricuture Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) Yes.

(b) No.

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि प्राईसिज बढाने के लिए हमने सरकार को लिखा है। स्पीकर साहब, प्राईसिज तो बहुत कम बढी हैं लेकिन सरसों और चने का बुरा हाल हैं जो सर्दी पिछले दिसम्बर में गिरी थी उसकी वजह से चने की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। एक चने के पौधे ऊपर 10–10, 12–12 टाट होती थीं, उनमें से 6–7 तो बिल्कुल सफेद हो गई हैं, जो सर्दी ने मार दी हैं। उसके अलावा, काफी तेज हवा चलने से जो फूल ऊपर आने थे, वे भी मर गए। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि चने की फसल को बरबाद हो गई, उसके लिए किसानों को कोई वि ोश राहत मिलनी चाहिये और गेहूं की फसल, जाहं एक एकड में 30–40 मन होती थी, वह केवल 5–7 मन ही रह गई है। इसलिए हमारी रिक्वैस्ट है कि चने व गेहूं की फसल के बारे में सैंटर सरकार से

अच्छे भाव दिलवाने के लिए सरकार रिकमैंडे ान करे और जहां किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां उनको मुआवजा दिलवाने की पूरी पूरी कोि ा ा की जाए। क्या सरकार की ऐसी कोई प्रोपोजल है ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने स्पोर्ट प्राईस के बारे में पूछा है। इस साल जो स्पोर्ट प्राईस अनाऊंस हुई है उसको भारत सरकार ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया है। हर साल वे स्टेट गवर्नमैंट से पूछते हैं कि आपकी कास्ट आफ प्रोडक ान कितनी बढी है ? जो हरियाणा ने रिकमैंडे ान की है वह पिछले साल 100 रूपया फालतू स्पोर्ट प्राईस के लिए मांगा गया है। गेहूं के लिए 375 रूपये प्रति क्विंटल स्पोर्ट प्राईस की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि यह प्राईस सारे प्रांतों में कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में इतनी ज्यादा स्पोर्ट प्राईस नहीं मांगी है। पंजाब सरकार ने भी 370 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से स्पोर्ट प्राईस की मांग की है। लेकिन स्पोर्ट प्राईस की मांग करने का भी एक बेस होता है, ऐसे ही यह प्राईस फिकस नहीं की जाती। सब तरह से वर्क आउट किया जाता है। कि किसान का ऐक्चुअल कितना खर्चा बढ गया हैं फिर आनरेबल मैम्बर्ज पूछेंगे कि कौन कौन सी चीज, आप काउंट करते हैं हर चीज वहां किसान को खर्चा ज्यादा करना पडा हो उसको कांउट किया जाता है जैसे जमीन का रैंट है, फर्टीलाईचर की प्राईस है, इनसैक्टीसाईडस की प्राईस है, उसकी लेबर है, ट्रैक्टर की प्राईस

है और बिल्डिंग की डैपरीि ऐसन है इन सभी बातों को देखा जाता है। फिर किसान जो लोन लेता है, उस पर इंट्रैस्ट भी देता है, उसको भी काउंट किया जाता है। उसके बाद इरीगे ान के लिए किसान का टयूबचैल लगाने का खर्चा भी होता है, मतलब यह है कि जितने भी किसान के खर्चे होते हैं सभी को हम काऊंट करते हैं, उसके बाद हम केन्द्र सरकार से स्पोर्ट प्राईस बढाने के लिए रिक्वैस्ट करते हैं सैंट्रल गवर्नमैंट में इसके लिए एक कमि ान बना हुआ है जो रिकमैन्डेटरी नेचर का है, जिसे कमि ान फार एग्रीकल्चर प्राईस एन्ड कास्ट कहते हैं। वह पहले इन सारी बातों को प्रोसैस करता है और फिर स्टेट गवर्नमैंट में जो हमारे अफसर हैं, वे जहां जाकर डिस्कस भी करते हैं। जब कोई सिफारि ा की जाती है तो प्रधान मंत्री की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला होता है कि स्पोर्ट प्राईस क्या अनाऊंस की जाए। चने के बारे में दूसरी स्टेटस से जो रिपोर्टस आ रही है, उन्हें कुछ साथियों ने हमारे नोटिस में लाया है और बताया है कि कुछ ऐसे क्लांइमैटिक हालात थे जिनकी वजह से चने की फसलों का काफी नुकसान हुआ है लेकिन मैं बताना चहाता हूं कि इसकी गिरदावरी रेवेन्यू विभाग वाले ही करेंगे। सबसे पहले उनको यह काम करना चाहिए कि वे इस बारे में जिला के डी0सीज0 को लिखें कि फलां फसल खराब हो गइ है उसकी गिरदावरी करवाई जाए। उससे अन्दाजा लग जाएगा कि कितने परसैन्ट नुकसान हुआ है। अगर 75 परसैन्ट नुकसान हुआ हो तो सरकार उसको नुकसान

मानती है और अगर 75 परसैन्ट से कम नुकसान हुआ हो तो उसको नुकसान नहीं मानती।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे ा का जो किसान है वह बडा मेहनती है और उत्पादन में भारत सरकार के जो भंडारन हैं, उसमें उसका काफी योगदान होता है। हमारी पडोसी स्टेट पंजाब में पिछले साल लोगों को गेहूं और दूसरी फसलों पर बोनस दिया गया था। क्या हरियाणा के किसानों को भी इस तरह का कोई बोनस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या सरकार सरसों, चने और दूसरी फसलों में होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए किसानों को कोई इंसैंटिव देने का विचार रखती है, और क्या सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर गौर करने का विचार रखती है ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, बोनस का तो व्हीट के साथ संबंध है। पिछले साल स्टेट गवर्नमैंट ने व्हीट पर बोनस पंजाब के बराबर दिया था। इस साल पंजाब गवर्नमैंट ने अभी कोई अनाऊंसमैंट नहीं की है। व्हीट के लिए स्पोर्ट प्राइस आई है, उसमें पिछले साल से 55 रूपए की बढौतरी की गई है। आज तक जो भी बढौतरी होती रही है, यह उसका एक रिकार्ड है। (विघ्न) पिछले साल का रेट 250 रूपए था और 25 रूपए क्विंटल के हिसाब से बोनस था। इस साल का रेट 305 है यानी इसमें 55 रूपए की बढौतरी हुई है। किसान को 330 रूपए मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे।

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि अगर पंजाब गवर्नमैंट बोनस देगी, तो क्या हरियाणा गवर्नमैंट भी देगी ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी यह बात विचाराधीन नहीं है। मैं यह बात भी इस मौके पर सारे सदन के नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारे अपोजी ान के साथी, जो किसान के चैम्पियन बनते हैं, इनकी दो बार सरकार आई। इन्होंने उस समय कितना रेट बढाया इसकी मेरे पास फिगर्ज हैं। पहली बार जब इनकी सरकार सैंटर में 1977–78 और 1978–79 में रही, तो पहले साल में अढाई रूपए बढाए थे और दूसरे साल मे ंभी अढाई रूपए बढाए थे यानी दो सालों में केवल पांच रूपए व्हीट की प्राईस बढाई थी। दूसरी बार जब इनकी सरकार आई तो पहले साल में 22 रूपए बढाए और दूसरे साल में 10 रूपए बढाएं। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई उसने पहले साल में 50 रूपए और दूसरे साले में 55 रूपए बढाए। कुल दो साल में 105 रूपए बढाए।

चौधरी अजमत खांः स्पीकर साहब, इन्होंने खुद माना है कि इन्होंने 375 रूपए रिकमैंड किए हैं। इन्होंने यह भी बताया कि वे किसान की कास्ट के हिसाब से रिकमैंड करते हैं। अब किसान को जो कीमत मिलेगी, वह 330 रूपए मिलेगी। इस हिसाब से ये खुद मानते हैं कि किसान का 45 रूपए क्विंटल का नुकसान है। तो क्या सरकार किसान को व्हीट पर बोनस देगी ? मेरी निवेदन

है कि सरकार को बोनस देना चाहिए क्योंकि खुद इन्होंने माना है कि उसको 45 रूपए का नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि इस बारे में सरकार जवाब दे और किसान को कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हम असैस करके भेजते हैं। उसमें किसान का जो मैकसीमम खर्चा होता है,वह काउंट करते हैं अब मैं यह समझता हूं कि जो स्पोर्ट प्राईस अनाउंस हुई है, वह रीजनेबल है, सैटिस्फैक्टरी है।

10.00 बजे।

अभी पिछले हफते एक चीफ मिनिस्टर्ज कांफ्रैंस हुई थी,उसमें एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के एट पार लाने के बारे में डिस्क ान हुई थी। एग्रीकल्चर पालिसी पर जो रैजोल्यू ान था उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने विचार रखे। वे विचार भाायद आपके नोटिस में भी आये होंगे। उन्होंनें सबसे बडी बात जो कही, वह यह कही कि हमें एग्रीकल्चर प्रौफे ान को केवल इतना मान कर ही नहीं चलनी चाहिए कि इससे गुजारा हो, यह प्रोफिटेबल भी होना चाहिए, यह बहुत बडी बात है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के एट पार माना जाना चाहिए। मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों की सरकार के समय में इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन हमारी सैंटर की सरकार एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के एट पार करने जा रही है।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि फसल की इन्‍ योरैंस स्कीम होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब सैंटर की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने फसल की इन्‍ योरेंस स्कीम के बारे में मामला इनीि ायट किया था। वह मामला आज सिरे चढ रहा है, जिसके तहत किसानों की फसलों में हुए नुकसान की जिम्मेदारी इन्‍ योरेंस कम्पनीज लेंगी और किसानों का नुकसान पूरा किया जाएगा।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात कृशि मंत्री जी की नालेज में होगी कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, दोनों की गेहूं पैदा करने में जो लागत आती है, वह बराबर आती है लेकिन हमारे प्रदे ा के किसानों को उतना पानी नहीं मिलता जितना पंजाब के किसानेां को मिलता है, हमारे यहां पानी का अभाव है, इसके बावजूद भी पंजाब सरकार अपने किसानों की गेहुं पर बोनस देगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार भी पंजाब सरकार के अनुसार हरियाणा के किसानों को गेहूं पर बोनस देने की सुविधा उपलब्ध कराएगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसानों को हम किसी भी कीमत पर पंजाब के किसानों से पीछे नहीं रहने देंगे। अगर पंजाब सरकार अपने किसानों को बोनस देगी तो हम भी देंगे।

***524. Sathi Lehri Singh:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-whether the work on Dadupur Nalvi and Dadupur Ladwa Canal was started inthe year 1986-87; if so, the present stage there of and the time by which the said canal is likely tobe completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Only part of land was acquired for Dadupur Nalvi Canal in 1987 but no work was starred. Regading Ladwa Canal, neither land was acquired not work was started. Neither of the Schemes has been approved by the Govt. of India.

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कल जवाब देते हुए कहा था कि यह स्कीम मंजूर है और यह काम जब फण्डज अवेलेबल होंगे भुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कल जो जवाब दिया था, उसमें और आज के जवाब में काफी डिफरैंस हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नहर के लिए 1987 में जमीन एक्वायर की गई थी, उसके बाद सरकार ने, इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम जमुना वाटर पर निर्भर करती है। जमुना नदी के पानी के बंटवारे के बाद अगर इसपर स्टोरेज बनाया जाए, उसके बाद ही गवर्नमैंट आफ इण्डिया इस स्कीम को मंजूर करेगी उसके बाद इस प्रोजैक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा। इसके अलावा, इन्होंने यह सवाल यह किया था कि यह स्कीम 1987 में मंजूर हुई थी, उसके

बाद इसका काम स्टार्ट किया या नहीं ? मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद इस स्कीम के लिए जमीन एक्वायर करने का काम स्टार्ट किया गया। इसके लिए 325 एकड जमीन एक्वायर की जानी थी, जिसमें से 180 एकड एक्वायर की गई थी और उस टाईम दादुपुर नलवी प्रौजैक्ट मंजूर किया गया था वह प्रोजैक्ट 13 करोड रूपये का था और अब वह कौस्ट बढ कर 48 करोड रूपये हो गई हें इसके लिए टोटल सी0सी0ए0 करीब 75350 हैक्टेयर है। यह जो नहर बनेगी, इसकी क्षमता 590 क्यूसिक पानी की होगी। हरियाणा सरकार ने ये दोनों स्कीमें लाडवा और दादुपुर नलवी मंजूर करके गवर्नमैंट आफ इण्डिया के पास भेजी भी हैं लेकिन गवर्नमैंट आफ इंडिया ने यह कहा है कि जब तक यमुना के पानी का डिस्ट्रीब्यू ान नहीं होता तब तक वह मंजूरी नहीं देगी। जब तक गवर्नमैंट आफ इण्डिया से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वल्ड बैंक से या गवर्नमैंट आफ इण्डिया से इन स्कीमों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। मैं साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि करनाल, अम्बाला और कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्टस की इरीगे ान के लिये यह स्कीम है इसके साथ ही यहां पर री–चार्जिंग की भी स्कीम बनाई जा रही है क्योंकि इस समय वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब तक गवर्नमैंट आफ इण्डिया से इस स्कीम की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक गवर्नमैंट आफ इण्डिया और वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा नहीं मिल सकता। जब उनसे मंजूरी मिल जायेगी तो इस पर कार्यवाही भुरू होगी।

श्री रामपाल सिंह कंवरः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस स्कीम के लिए 180 एकड जमीन एक्वायर की गई थी। साथ ही बताया है कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया से इनकी मंजूरी नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि 180 एकड जो जमीन एक्वायर की गई थी, क्या उसका कम्पनसे ान किसानों को दे दिया गया था क्योंकि अगर गवर्नमैंट आफ इण्डिया से यह स्कीम एप्रूवड ही नहीं हुई तो फिर लैण्ड एक्वायर करने का क्या औचित्य था ?

चौधरी जगदी ा नेहराः मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जमीन के पैसे भेज दिये गये थे लेकिन बहुत से लोगौं ने पैसे लिए नहीं और जमीन का पोजै ान भी नहीं दिया। आगे बताने की कार्यवाही तभी भाुरू होती जब जमीन का पोजै ान ले लिया जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 180 एकड जमीन एक्वायर की गई थी जबकि इसके लिए 325 एकड जमीन की जरूरत है। जब तक स्कीम ऐप्रूव नहीं हो जाती, तब तक इस पर खुदाई का काम भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत से लोग कोर्ट में चले गए और कम्पैनसैशन भी नहीं लिया। गवर्नमैंट आफ इण्डिया से इसके पैसे नहीं आए क्योंकि गवर्नमैंट आफ इण्डिया से यह स्कीम एप्रूव नहीं हुई।

श्री मोहम्मद असलम खांः क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस स्कीम के लिए जमीन एक्वायर करने के बाद किसानों को जो कम्पनसे ान दिया गया वह कितना दिया गया।

चौधरी जगदी ा नेहरा: मैं नहीं कह सकता कि कितना कम्पैनसे ान एक्वायर की गई जमीन का दिया गया क्योंकि बहुत से लोग कोर्ट में चले गए। दूसरे जब 1987 में यह स्कीम अनांउस हुई थी, तब से आज तक, कम्पनसे ान में भी काफी अंतर आ गया है, इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर्ज नहीं बता सकता कि कितने लोगों को कितना पैसा दिया गया।

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भााहबाद नलवी स्कीम की मंजूरी कमि नर इरीगे ान ने 30.4.85 को दी थी लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसी स्कीम के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए 19.6.87 को मंजूरी दी। इसके लिए एक करोड रूपया जमा करवाया गया था। फिर इंजीनियर इन चीफ के पत्र क्रमांक 7–4/8–4/लाइनिंगे/92, दिनांक 14.11.91 के द्वारा किसानों से पैसा वापिस लेने के लिए लिखा। क्या यह सच है कि इसके विरोध में लोग हाई कोर्ट में गए हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि लाडवा सिंचाई स्कीम की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कब तक लिखा और उसके उत्तर में केन्द्रीय सरकार का क्या उत्तर आया इसके अलावा, राज्य सरकार इस स्कीम की मंजूरी के लिए क्या पग उठाने जा रही है ?

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डेटवाईज तफसील पूछी है लेकिन इस समय डैटवाईज तफसील मेरे पास नहीं है। यमुना के वाटर भोयरिंग के लिए बराबर मीटिंगें

होती रही हैं और मुख्य मंत्री जी ने काफी कोि ाश की है। स्पीकर साहब, आपने देखा होगा, एम0ओ0यू0 भी कैबिनेट से एप्रूव करवा दिया था। हरियाणा सरकार इस बारे में पूरी प्रयत्न ील है कि यमुना के पानी का फैसला जल्दी हो। कल भी केन्द्रीय सरकार ने अफसरों की एक मीटिंग बुलाई है। हम यह कोि ा ा कर रहे हैं कि हथनी कुण्ड बैराज के लिए ही आपस में कोई समझौता हो जाए ताकि हम कोई ने कोई कार्यवाही तो कर सकें और हरियाणा को अधिक से अधिक पानी मिल सके।

मुख्य मंत्री (चौधरी भलन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें यमुना नगर, अम्बाला, कुरूक्षेत्र और करनाल चार जिले इन्वाल्वड हैं, इसलिए इन चारों जिलों के माननीय विधायकों का इस बारे में चिन्तित होना स्वाभाविक है। अध्यक्ष महोदय, दादुपुर नलवी स्कीम हम ने उस वक्त स्टार्ट करवाई थी, जब पहले हमारी सरकार थी। एस0वाई0एल0 की आधारि ाला श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने हाथों से रखी थी। हम यह सोचते हैं कि एस0वाई0एल0 जल्दी बन कर तैयार हो जाए, साथ ही साथ यह स्कीम भी बन जाए ताकि यमुना का पानी से जो सोनीपत, रोहतक और भिवानी यानी बहुत नीचे तक जाता है उसको रोक कर उस ऐरिया को एस0वाई0एल0 का पानी दिया जाये। इस प्रकार से यमुना काजो पानी रोका जाएगा वह एस0वाई0एल0 का पार्ट होगा। इसलिए एस0वाई0एल0 के लिए जमीन ऐक्वायर करने की कार्यवाही की गई ताकि ज्योंहि नहर बन जाए, हम काम आगे भाुरू कर सकें और

अगला काम पूरा करने के लिए कोई दिक्कत न आए। किसानों को मुआवजा देने के लए मन्त्री जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। कुछ लोगों ने मुआवजा का पैसा ले लिया, कुछ ने नहीं लिया। इसको वापिस देने की जो बात है, इसका कारण यह है कि जिस परपज के लिए जमीन ऐक्वायर की गई थी, वह परपज पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा होने में देर हो रही है, इसलिए उस जमीन को ऐकवायर करने का कोई फायदा नही हैं जमीन वापिस करने की बात ही उचित है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कह सकता हूं कि ज्यों ही एस0वाई0एल0 का काम पंजाब में स्टार्ट होगा, दादुपुर नलवी का काम साथ साथ ही करेंगे चाहे इसके लिए ऐमरजैंसी क्लाज रख कर ही जमीन एक्वायर करनी पडे, हम इसको करेंगे।

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वि वास दिलाया है कि इस काम को बहुत सीरियसली करेंगे। जो जमीन वापिस की जा रही है जब काम दोबारा भाुरू करेंगे तो उसके लिए फिर से जमीन ऐक्वायर करनी पडेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब जमीन की जरूरत पडती ही है तो फिर इसको वापिस क्यों किया जा रहा है। इसी वजह से यमुनानगर जिले के 8 गांवों के लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 10 साल पहले जब किसानों की जमीन ऐक्वायर की गई थी, उस वक्त जमीन की कीमत बहुत कम थी और आज कीमत बहुत ज्यादा है। जो जमीन

उस समय 10 हजार रूपये एकड के हिसाब से मिली थी, उसकी कीमत आज एक लाख रूपये के करीब हैं। हमने जो काम किया है, वह किसानों के हितों को ध्यान में रख कर ही किया है। हम किसान को नुकसान नहीं होने देंगे।

Grain Market at Jhajjar

***547. Sh. Daryao Singh Rajora:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-to state the time by which the grain market, Jhajjar, is likely to start functioning ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh): Efforts will be made to make the Grain Market, Jhajjar functional during the year 1994.

चौधरी जिले सिंह जाखड: स्पीकर सर, कल भी मन्त्री महोदय ने मार्किटिंग बोर्ड के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सोनीपत, बहादुरगढ, झज्जर और कोसली के लोग अपना अनाज दिल्ली की मण्डियों में बेचने के लिए ले जाते हैं, इसलिए इस ऐरिया में और मण्डियें की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि इस ऐरिया में ऐसे किसान भी हैं, जिनकी जमीन एक दो एकड है या इससे भी कम जमीन है, इसलिए उनकी पैदावार कम होती है। यह जरूरी नहीं है कि सारे किसान अपना अनाज बेचने के लिए दिल्ली ले जाएं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि झज्जर, बेरी और कोसली में ग्रेन मार्किट का 80 प्रति ात कार्य पूरा हो चुका है, इनके बाउण्डरी वालज और सीवरेज वगैरह बन चुके हैं,

सिर्फ मार्किटिंग बोर्ड का दफतर बनाया जाना हें छोटे फारमर्ज जिनकी आदमनी कम है, उनको लाभ देने के लिए जो मण्डियां ठप्प पडी हैं, क्या उनको जल्दी से जल्दी बनाने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस अनाज मण्डी को बनाने की कोि ा ा की जायेगी कुछ काम जैसे वाटर सप्लाई और सीवरेज का है, यह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने किया है। पहले यह मण्डी कोलोनाइजे ान डिपार्टमैंट के अण्डर थी, अब यह मार्किटिंग बोर्ड को ट्रांसफर हुई है। कोलोनाइजे ान डिपार्टमैंट इस पर 6 लाख रूपये खर्च कर चुका है, लेकिन यह बात दुरूस्त है कि जब तक इसकी बाउंडरी वाल ने बने, तब तक यह काम पूरा नहीं होता। जितना काम बाकी रहता है, वह अगले साल पूरा करेंगे।

Construction of Link Road from village Phula to Bharpur

***544. Sh. Pir Chand:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a link road from village Phula to Bharpur; if so, the time by which it si likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): गांव फूला से भरपूर तक एक योजक सडक के निम्रण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं सवाल करता हूं तो मंत्री जी हमे ाा यही जवाब देते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर बहुत बडे बडे जमींदार हैं, जो बहुत ज्यादा काटन पैदा करते हैं। उन्हें अपना अनाज मंडी में ले जाने के लिए 20 किलोमीटर का फासला तक करके आना पडता है। अगर यह सडक बना दी जाए तो हैफेड का कारखाना जो भरपूर के पास बनाया है, किसान लोग वहां पर अपना सामान बेच कर काफी फायदा कमा सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सडक बनाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, गांव फूला से लेकर गांव भरपूर तक कोई सडक बनाने का विचार नहीं है क्योंकि यह सडकें पहले से ही जुडी हुई है।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, सडकें तो सारी जुडी हुई हैं लेकिन क्या यह बीच की सडक को जोडेंगे ताकि किसान लोग माल सीधा ले जाएं और उनको आमदनी हो ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो सडक नई बनती हैं चाहे वह दो किलोमीटर, चार

किलोमीटर, आठ किलोमीटर या 10 किलोमीटर की सडक हों, वे किस तरह से बनती हैं ? क्या वे तब बनती हैं जब कोई मंत्री अनाउंस कर दे, जैसे चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में यह नारा था कि हर गांव में बिजली और हर गांव में सडक होगी ? कृपया यह बताएं कि किस आधार पर सडक का निर्माण होता है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, भार्मा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि सडक को किस आधार पर बनाते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जहां लोगों को ज्यादा जरूरत होती है या दो तीन किलोमीटर लिंक रोड बनने से 8–10 गांवों को फायदा होता हो, वे सडकें बनाई जाती हैं। साथ ही मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर पंचायत की तरफ से प्रस्ताव आ जाता है या हमारे माननीय सदस्य लिखकर भेजते हैं कि यह बहुत जरूरी सडक है, हम उसका सर्वे करवा कर उस सडक को बनवाते हैं।

श्री पीर चन्दः स्पीकर साहब, आप भी जमींदार हैं और जमींदार होने के नाते आपको भी पता है कि गांव फुला से भरपुर तक की सडक कितनी जरूरी है ? पता नहीं मंत्री जी को यह सडक बनाने में क्या तकलीफ है ? यह दो तीन किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सडक नहीं है। अगर यह बना दी गयी तो इससे उस गांव के दो हजार लोगों को कुछ फायदा होाग। यह सडक हैफेड के कारखाने के साथ लगती है। इसलिए मंत्री जी बतायें कि कब तक इसको बनवा देंगे ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने आज ही सदन के सामने यह बात कही है लेकिन फिर भी हम इसका सर्वे करवा लेंगे और अगर जरूरत होगी तो बनवा देंगे।

Construction of Dabalu Minor

***537. Ch. Zakir Hussain:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the foundation stone for the construction of Dabalu Minor and extension of Meerka Minor in Taoru Constituency was laid in the year 1987; and

(b) whether the works on the minors as referred to in part (a) above have been started; if so, the time by which these are likely to be completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Foundation stone of only Dabalu Minor was laid in 1985.

(b) The work will be taken up on availability of funds.

चौधरी जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि दुबालु माईनर के निर्माण का पत्थर 1985 में रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, सन 1987 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्री सुरजेवाला साहब इस प्रदे ा के आई0पी0एम0 थे, तो उन्होंने खुद वहां जाकर दुबालु मीरका तथा

लाडवा माईनर के निर्माण का पत्थर रखा था। उस समय मैं भी उनके साथ था। लाडवा माईनर का काम तो अब सिर्फ दो या तीन परसैंट ही बाकी रह गया है और बाकी काम कम्पलीट हो गया है। इसलिए क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह बात सही है या गलत है कि उन्होंने 1985 में इन तीनों माईनरों के पत्थर रखे थे? इसके अलावा, मेवात एरिया मे ंपानी की बहुत दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, जिन माईनरों का मैंने जिक्र किया है, अगर वे बना दिये गये तो उनसे काफी एरिया में सिंचाई का लाभ लोगों को मिलेगा। इसलिए क्या मंत्री जी इस साल के बजट में इन माईनरों को पूरा करवाने के लिए पैसे का प्रावधान करवायेंगे ?

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि तीनों माईनरों का पत्थर 1987 में रखा गया था लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1985 में तो केवल एक माईनर का ही पत्थर रखा गया था। इसके अलावा जो दो माईनर ये बता रहे हैं इनमें से तीसरे माईनर के बारे में तो इन्होंने सवाल पूछा ही नहीं है। दूसरे माईनर मीरका के बारे में पूछा है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस माईनर का भी पत्थर नहीं रखा गया। जैसा इनहोंने पूछा कि इस साल के बजट में यानी 1993–94 मैं क्या इनके लिए पैसे का प्रावधान किया जाएगा तो जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा था कि अगर हमें पानी नहीं मिलता और हम लगातार माईनर बनाते जाएंगें तो हमें बडी दिक्कत आएगी। इसलिए जब पानी का फैसला हो जाएगा और हमें माईनर बनाने की जरूरत

महसूस होगी तो हम बनायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने भी अभी कहा है कि जो माईनर अंडर कंसीड्रे ान हैं या मंजूर हो चुके हैं, और उन पर थोडा बहुत काम भोश रहता है, उनको हम जरूर बतायेंगे लेकिन इनको बनाने का फायदा तभी है जब हमें पानी मिल जाएगा।

चौधरी जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 1987 में सुरजेवाला साहब वहां पर गये थे और यह बात भी सच है या कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह चाहें तो इस बात को अपने महकमें से वैरीफाई कर लें कि वे 1987 में वहां पर गये थे या नहीं गये थे ?

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बात रिकार्ड पर है कि दुबालु माईनर 1985 के छठे महीने में सैक ान की गई थी। इसी तरह से मीरका माईनर 1987 के तीसरे महीने में सैंक ान की गई थी। इन तीनों माईनरों का पत्थर रखा है या नहीं रखा गया है, या कैसे रखा है, इसकी पूरी डिटेल इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक इन माईनरों के सैंक ान होने के बाद इनकी कौस्ट का सवाल है वह मैं इ नको बताना चाहूंगा ये दो माईनर जो हैं, ये गुडगांव कैनाल से निकलेगी दुबालु माईनर पर 36 लाख रूपये खर्च होंगे और मीरका माईनर पर 6 लाख रूपये खर्च होंगें। यह बात सही है कि इनसे काफी गांवों को फायदा होगा इसमें कोई दो राय नहीं

है। दुबालु माईनर से गंगोली, छेछरा आदि गांवों को और दूसरे माईनर से गोलीपुर, पुरथल, कोथल आदि गांवों को फायदा होगा। स्पीकर सर, हमें जैसे जैसे फण्डज अवेलेबल होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन माईनरों को बनायेंगे।

चौधरी अजमत खांः अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1985 में इसका पत्थर श्री भाकरूला खां ने रखा था उसके बाद 1987 में दोबारा इस दुबालु माइनर को चालू करने के लिए सुरजेवाला साहब गए थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1985 के बाद 1987 से लेकर 1991 तक आपकी सरकार रही उसमें खु र्शिद साहअ और तैयब साहब मंत्री रहे यह माइनर इनके हल्के से ताल्लुक रखती है लेकिन उस वक्त इसके लिए पैसा नहीं मिला। तो मंत्री जी से हम यह जरूर चाहते हैं कि हमने इसका पत्थर रखा है, अतः इसी साल इसे जरूर बनवा दिया जाए ताकि लोगों को फायदा हो।

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री अजमत खां जी ने कहा यह बात दुरूस्त है कि बाकायदा इसकी नोटिफिके ान हुई और दफा 4 और 6 के नोटिस भी लैप्प होते रहे हैं। पिछली सरकार ने इसी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको भी पैसे की दिक्कत थी क्योंकि फंडज अवेलेबल नहीं हुए, जिसके कारण दफा 4 और 6 के नोटिस होते रहे। जुलाई 1992 में हमने नोटीफिके ान किया है। जैसा मैंने पहले भी स्पीकर साहब के

माध्यम से सदन को आ वासन दिया है कि ज्यों ज्यों फ ंडज अवेलेबल होंगे, इसको जरूर कार्यान्वित करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार हमारे किसानों और ग्रामीणों के विकास का बहुल ढोल पीटती थी। हमारे गुडगांव और फरीदाबाद दोनों जिलों में पिदली सरकार की पार्टी के सदस्य बने लेकिन उनके समय में आज तक दोनों जिलों में सिंचाई विभाग की तरफ से दो परसैंट भी पैसा खर्च नहीं किया गया इसी बात पर मेवात और फरीदाबाद के इलाके के लोगों में रिजेंटमैंट है। इरीगे ान विभाग की तरफ से कैनाल बनाने के लिए इस क्षेत्र में पैसा खर्च क्यों नहीं किया जाता है। वह भी हरियाणा प्रदे ा का हिस्सा है बहुत सी स्कीमें मंजूर की हुई हैं, इनकी डीसिलटिंग नहीं की गई। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बजट के बाद हमारे दोनों जिलों में वि ोशकर मेवात और फरीदाबाद में जो हमारा हिस्सा है, उस पर अव य पैसा खर्च करें।

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, बिसला साहब ने जो बात कही है वह दुरूस्त है। इसका कारण यह है कि फरीदाबाद जिला आगरा कैनाल के नीचे आता है। आगरा कैनाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यू0पी0 गवर्नमैंट के पास है। जब यमुना वाटर के भोयर के बारे में मीटिंग हुई थी, तो हमने और मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय मन्त्रालय को यह कहा था कि आगरा कैनाल का एडमिनिट्रेटिव कंट्रोल हरियाणा को दिया जाए। जब से आगरा

कैनाल निकली है, तब से इस पर यू0पी0 सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है लेकिन जमीन हरियाणा की है। इसके लिए हम कोि ा ा कर रहे हैं। अगर इस कैनाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हरियाणा के पास आ जाता है तो इसकी सफाई और पानी के रख रखाव की कार्यवाही का कार्य हमारे पास आ जायेगा। अब रही गुडगांव जिले को पानी देने की बात। गुडगांव कैनाल, आगरा कैनाल से पानी लिफट करके उस एरिया को सिंचित करती है और राजस्थान को पानी देती है। इसके बारे में जो मेन दिक्कत आ रही है, वह यह है कि यमुना के पानी के भोयर्ज अभी नहीं बंटे, जब भोयर एक बांर बंट जाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि राजस्थान के पानी का कितना हिस्सा है। गुडगांव कैनाल आगरा कैनाल की मारफत अलवर तथा दूसरे डिस्ट्रिक्टस को पीने के पानी की सुविधा देती है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से चिन्तित है और हम चाहते हैं कि फरीदाबाद और गुडगांव डिस्ट्रिक्टस में पानी की व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाये।

Mr. Speaker: Hon. Members, the Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Setting up of new Industries at Bhiwani

***442. Sh. Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up new industries at Bhiwani during the current Financial Year 1992-93; and

(b) if so, the details thereof ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora):

(a) There is no proposal under the consideration of State Govt. at present to set up any new industry at Bhiwani in the state sector during the Financial Year 1992-93.

(b) Nil- The State Govt. has, however formulated a new Industrial Policy with effect from 1-4-92 under which industrial enterpreneurs are given various incentives for setting up new units, particulary, in the backward areas of the State including backward areas of Bhiwani District.

Construction of Stadium

***513. Sh. Ram Kumar Katwal:** Will the Minister for sports be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a stadium at village Rajound in District Kaithal. if so, the time by which the said stadium is likely to be constructed ?

State Minister for Sports (Sh. Rajesh Sharma): No.

66 K.V. Power House

***525. Sathi Lehri Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to setup 66 K.V. Power House at Berthali and Jathlana;

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Govt. to upgrade Power House at Babain; and

(c) if the reply to part (a) & (b) is in affirmative, the time by which the aforesaid proposals are likely to be materialized ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 8वीं योजना अवधि के दौरान दीर्घकालीन योजना के रूप में ग्राम बेरथाली में एक 66 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है। वैसे ग्राम जठलाना में एक उपकेन्द्र की स्थापना करना कुरूक्षेत्र जिला के सम्पूर्ण प्रणाली सुधार स्कीम के अन्तर्गत व्यवस्थित है।

(ख) वर्तमान 33 के0वी0 उपकेन्द्र बबैन का दर्जा 66 के0वी0 स्तर तक बढाया जा रहा है।

(ग) 66 के0वी0 उपकेन्द्र बबैन वर्श 1993–94 तथा 66 के0वी0 उपकेन्द्र बेरथाली वर्श 1996–97 के दौरान पूरा करना निर्धारित है। 66 के0वी0 उप केन्द्र जठलाना ओ0इ0सी0एफ0 के

ऋण सहायता के साथ जुडा हुआ है तथा इसके पूरा होने में उसे 4 वर्श तक का समय लग सकता है।

विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कल मैंने और मेरी पार्टी के सदस्यों ने एक कालिंगे अटैन्ा न नोटिस दिया था कि कुरूक्षेत्र में जब ठेकों की नीलामी हो रही थी तो महिलाओं ने प्रद र्ान किया। भाराब बन्दी का आन्दोलन वहां चल रहा है। पुलिस ने महिलाओं पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया और उनको ट्रैकों में डाल कर ले गई, उनका पता भी नहीं चला। एक अच्छे काज के लिए महिलाएं आन्दोलन कर रही हैं लेकिन सरकार उन पर ज्यादती कर रही है, वह बडी भार्मनाक बात है। हमने इस नोटिस के जरिए मांग की थी कि सरकार अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

Mr. Speaker: It is under consideration

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, दूसर कालिंग अटैन्ा न नोटिस जींद के अन्दर प्लांटों की नीलामी के बारे मे हैं। प्लाटों की नीलामी हो रही थी और यह नीलामी डिप्टी कमि नर की इजाजत से वह आदमी कर रहा था, लेकिन वहां के म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की तरफ से गोली चलाई गई .....
...

श्री अध्यक्षः यह आज 9.15 बजे मिला है। and it is under consideration.

प्रो0 सम्पत सिंहः वह प्लाट कैंसिल हुआ था। इस मामले में मिनिस्टर का एक रि तेदार भाामिल है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। This is under consideration. Sampat Singh Ji, now you please take your seat (Noise & Interruptions).

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इसी तरह से एक और कालिंग अटैन ान मो ान दिया था। स्पीकर साहब हरियाण फाइनैं ि ायल कारपोरे ान को इस सरकार ने एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बना दिया है। ये पब्लिक फण्डज है लेकिन इस कार्पोरे ान ने भानू इंडस्ट्रीज को नब्बे लाख रूपया दिया है जबकि इसके खिलाफ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्ज कोर्ट में चल रही है। पहले इसको सत्तर लाख या अस्सी लाख रूपया दे दिया और अब नब्बे लाख रूपया और दे दिया है .....

श्री अध्यक्षः यह नोटिस 9.15 बजे आया और अन्डर कंसीड्रे ान है।

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, इनको तो फोबिया हो गया है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सुनिए। सम्पत सिंह जी, आपकी तीनों बातें पूरी हो गई हैं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अभी मैंने पूरी बात नहीं की है। स्पीकर साहब, हरियाण फाइनैंि ायल कार्पोरे ान का पैसा पब्लिक मनी है।

(इस समय बहुत से सदस्य इकटठे बोलने लगे) (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, you please take your seat. This calling attention notice is under consideration. (Noise & Interruptions). I am on my legs, you all please be seated. Sampat Singh Ji, your call attention notice is under consideration. (Noise & Interruptions).

क्लैरिफिकेटरी स्टेटमैंट–

भानू इंडस्ट्रीज को हरियाणा फाइनैंि ायल कारपोरे ान द्वारा ऋण देने सम्बंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इनकी मुि कल यह हो गई है कि ये सब को अपने जेसा ही समझते हैं क्योंकि इन्होंने हमे ाा गलत काम किए हैं और आगे भी करते रहते हैं। मैंने हमे ाा इनको चैलेन्ज किया है। चार सल तक इनका राज रहा और जब इनका राज नहीं था, तब भी इनको मेरा और मेरे दामाद का फोबिया रहता था। चार साल इन्हौंने खूब

जोर लगा लिया। बाल मात्र भी कोई कमी ये लोग नहीं निकाल सके। वरना क्या ये लोग भजन लाल को बक ाने वाले थे ? एक पेपर ने कुछ लिख दिया कि नब्बे लाख का भजन लाल के दामाद को कर्जा दिया है। पेपर लिखता है –

"हरियाणा वित्त निगम ने राज्य में मुख्य मंत्री भजन लाल के दामद की कंपनी भानू इंडस्ट्रीज को 90 लाख रूपये का कर्ज देने का फैसला किया है। निगम के बोर्ड ने पिछले महीने की 22 तारीख को हुई बैठक में भानू इंडस्ट्रीज को 90 लाख रूपये के कर्ज देने की मंजूरी दी गई। जानकार सूत्रों के अनुसार बोर्ड की बैठक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि भानू इंडस्ट्रीज का जिन बैंकों से लेन देन है उन से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि अगर वित्त निगम इस कंपनी को 90 लाख रूपये का कर्ज देता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। इस पर निगम के प्रबन्धक निदे ाक अजीत एम0 ारण ने बोर्ड को बताया कि अगर निगम भानू स्टील इंडस्ट्रीज के नाम कुछ बैंकों की काफी रा ि ा बकाया है। भजन लाल के 1991 में दोबारा मुख्य मंत्री बनने के बाद उनके दामाद अनूप बि नोई को हिसार स्थित उद्योग समूहों को यह दूसरा बडा कर्ज मंजूर किया गया है। इससे पहले पिछले वर्श भानू स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड को 78 लाख 15 हजार रूपये का कर्ज दिया गया था। तब भी एक राश्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि ने कहा था कि उनके बैंक के इस कंपनी से बकाया रा ि ा की अदायगी करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं

मिला। प्रबन्ध निदे ाक अजीत एम0 भारण ने बोर्ड को इतलाह दी थी कि भानू स्टील्ज ने बैंक को हिसार भााखा को बकाया रा ि ा की अदायगी के बारे मे ंअपने प्रस्तावों की जानकारी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, सब बैंको ने उन्होंने पहले पूछा, फिर लोने लेने के लिए कहा। बैंकों ने कहा कि क्या कोई संस्था दुनिया में, हिन्दुस्तान में चाहे कोई टाटा हो, बिडला हो और चाहे गवर्नमैंट हो, बगैर कर्जा लिये काम चला सकते हैं ? वित्त निगम का काम कर्जा देना है ओर ज्यादा कर्जा अगर वह देता है तो हम उसको इनाम देते हैं कि उस निगम ने अच्छा काम किया है और इतना ज्यादा कर्जा लोगों को दिया है। अगर कोई ले के वापिस न दें और भजन लाल का दामाद कर्जा लेकर खा जाए, तो बहुत बुरी बात है। चाहे भजन लाल क्यों न हो, भजन लाल का अगर कोई दामाद है तो क्या वह चोरी करेगा, डाका डालेगा ? कोई काम करना गुनाह नहीं है। किसी किसान का बेटा अगर काम करे तो उसका तो इनको एतराज है लेकिन टाटा, बिडला, चाहे अरबों रूपया ले लें, उसका इनको कोई एतराज नहीं है ? किसी आदमी पर इलजाम लगाने से पहले आपको सोचना चाहिये था। इलजाम लगाने से पहले इनको अखबार अच्छी तरह से पढ लेनी चाहिये थी, लेकिन इन्होंने पढी नहीं। अगर ये ध्यान से पढते तो ऐसी बातें सदन में न कहते। 80–90 लाख रूपये की क्या बात है, लोग तो 100–100 व 200–200 करोड रूपये लोन लेते हैं। अगर कोई लेकर के वापिस न करे तो बुरी बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर

कोई आदमी स्टेट के अन्दर इंडस्ट्रीज लगाएगा तो उसको कर्जा लेना ही पडेगा। किसान टयूबवैल्ज के लिये कर्जा लेता है। छोआ से काम करता है, उसके लिए लोन लेता है, ट्रैक्टर के लिये लोन लेता है। किसानों के लिए भी कोई नीति है, पालिसी है, उसी के तहत निगम कर्जा देती है और वह भी सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद ही निगम कर्जा देता है। अगर एक पाइ की भी गलती मेरे दामाद में निकाल दोगे तो भजन लाल देगा। मैं उन लागों में से नहीं हूं जैसा कि इनके नेता चौधरी देवी लाल जी ने कह दिया था कि चौधरी औम प्रका ा मेरा बेटा ही नहीं है। (हंसी) बहुत से लोग इस तरह की जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि दामाद की मेरी क्या जिम्मेवारी है, लडके की मेरी क्या जिम्मेवारी है, लेकिन अनूप बि नोई मेरा दामाद है और मुझे उस खानदान पर फक्र है। मैं फिर कहता हूं कि अगर एक पाई की भी गलती ये लोग निकाल देंगे, निगम निकाल देगा तो भजन लाल देगा। उसको मांगने की इन लोगों को चिन्ता नहीं करनी चाहिये। (ाोर)

श्री अध्यक्षः No interuption, no discussion please.

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया है और आप ने भी सुना है। हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। (ाोर) उन्होंने उत्तर दिय है, हम पर ऐलीगे ान लगाए हैं, उसका तो हमें जवाब देना ही पडेगा। (ाोर)

श्री अध्यक्षः पहले आप अपने काल अटैन्न ान मो ान की बात सुनें। (ाोर) आपका पहला काल अटैं ान मो ान था regarding lathi charge on peaceful demonstration by women at Kurukshetra. That has been disallow now.

डा0 राम प्रका ाः स्पीकर साहब, मैंने कल दो ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिए थे ..... (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्षः मैंने आपको कह दिया है कि वह अंडर कंसिड्रे ान है, आप बैठिए। (ाोर)

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा ध्यानाकर्शण प्रस्ताव स्कूलों और कालेजों में ..... (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जब मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट दी है तो हमें भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः नहीं, बाप बैठें। (व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये फाइनैंि ायल कारर्पोरे ान को लूट कर खा गए हैं, इसलिए हमें भी बोलने दें। (ाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री अध्यक्षः जो आपने काल अटैं ान मो ान दिया था, वह पहले अंडर कंसिड्रे ान था लेकिन अब वह डिस अलाउ किया जाता है। वह डिस अलाउ हो गया है, इसलिए आप बैठें (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जो इन्होंने अपनी स्टेटमैंट दी है, उस पर मैं भी कुछ कलैरिफिके ान देना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः कोई जरूरत नहीं, वह डिस अलाउ हो गया है। (ाोर)

सदस्यों का नाम लेना

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

(इस समय जनता पार्टी के सदस्यों सर्व श्री सम्पत सिंह, कृश्ण लाल, अमर सिंह ढांडे तथा सूरजभान ने सदन के वैल में आकर धरना दे दिया और सरकार के विरूद्ध नारे लगाने भ्रारू कर दिए।)

श्री अध्यक्षः मेरी सभी जनता पार्टी के सदस्यों से रिकवैस्ट है कि वे कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (व्यवधान)

(इस समय भी जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन की वैल में धरना जारी रखा और श्री राम कुमार कटवाल वहां पर खडे होकर कुछ बोलते ही रहे।)

Mr. Speaker: I name Sh. Ram Kumar Katwal. He may leave the House. (Interruptions)

(The Hon'ble member did not leave the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House.

(At this stage Sergeant-at-Arms went to Sh. Ram Kumar Katwal and took him out of the House.)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह अन्याय है और सरासर गलत है। (ाोर)

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का मौका दें। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। (ाोर)

(At this stage Sh. Krishan Lal kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and reather kept on speaking without permission of the Speaker).

Mr. Speaker: I name Sh. Krishan Lal. He may withdraw from the House.

(At this stage the Hon'ble Member did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of theWatch & Ward staff.

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Krishan Lal and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Ramesh Kumar kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Ramesh Kumar. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Ramesh Kumar and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Sampat Singh kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Sampat Singh. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Sampat Singh and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Amar Singh Dhanday kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Amar Singh Dhanday. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Amar Singh Dhanday and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Dhir Pal Singh kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not

go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Amar Singh Dhanday. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Amar Singh Dhanday and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Dhir Pal Singh kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Dhir Pal Singh. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Dhir Pal Singh and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Suraj Bhan Kajal returned to his seat from the well of the House and started speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Suraj Bhan Kajal. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Suraj Bhan Kajal and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

(Sh. Jaswinder Singh kept on sitting in the well and inspite of asking by the Speaker to go to his seat, he did not go to his seat and rather kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Jaswinder Singh. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Jaswinder Singh and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान है। यह काल अटैं ान मो ान का मामला था जो हमने आपकी सेवा में दिया था। मुख्य मंत्री जी ने पवायंट आफ आर्डर के जरिए उसका जवाब दे दिया लेकिन जब आपने वह काल अटैं ान मो ान डिस अलाऊ ही कर दिया था और फिर मुख्य मंत्री को स्टेटमैंट देने के लिए टाईम भी दे दिया, लेकिन हमको नहीं दिया ..... । (ाोर)

श्री अध्यक्षः चीफ मिनिस्टर जब चाहें, इन्टरवीन कर सकते हैं। (ाोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, पहले उधर से माननीय सदस्य इधर आए थे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आप पहले इधर आए और इधर से कोई माननीय सदस्य नहीं आया। (ाोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, हम यह चाहते हैं कि हाउस का डेकोरम रहे और सै ान ठीक ढंग से चले। (ाोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। आपने हमारी काल अटैं ान मो ान डिस अलाऊ कर दी, उसके बावजूद भी आपने चीफ मिनिस्टर को स्टेटमैंट का समय दे दिया। जब हम बोलने के लिए खडे होत हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आपमें इनकी बात सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। (ाोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः हमने इनकी बत को सुन लिया है, अब ये उसका जवाब भी हम से सुन ले ?

श्री भरथ सिंहः स्पीकर साहब, आपने मुख्य मंत्री को स्टेटमैंट देने के लिए टाइम क्यों दिया ? (ाोर)

(At this stage Sh. Bharath Singh kept on speaking without permission of the Speaker.)

Mr. Speaker: I name Sh. Bharath Singh. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Bharath Singh and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, पहले आप हमें अपनी बात कहने का मौका तो दो। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी यह ट्रेनिंग दी गई है कि किसी तरह से हाउस की कार्यवाही को चलने न दिया जाये। ये चाहते हैं कि इनका अखबारों में नाम आ जाये।

इसलिए प्रेस वालों से मेरा हाथ जोड कर अनुरोध है कि इनकी कोई खबर अखबारों में न छापें और मेरा यह भी अनुरोध है कि इनको अनु ाासन में रहना सिखाने के लिए लिखें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, जो जो घपले हुए हैं जो कांड हुए हैं और बलात्कार हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्शित करना हमारा फर्ज है और हम उनकी चर्चा करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादयान जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

(At this stage Sh. Satbir Singh Kadian did not resume his seat.)

Mr. Speaker: I name Sh. Satbir Singh Kadian. He may withdraw form the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Satbir Singh Kadian and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

श्री जयपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमि ान है ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। जयपाल सिंह जी, क्या आप भी जाना चाहते हैं ? (व्यवधान) लेकिन मैं किसी को सदन से बाहर भेजना नहीं चाहता, आप ही मुझे मजबूर करते हैं। जब मैंने पहले ही कह दिया है कि नोटिस अभी अंडर कंसीड्रे ान है तो आपको बैठ जाना चाहिए लेकिन फिर इन्होंने मामला इनीि ाएट कर दिया और फिर वही सारी बातें दोबारा कहना चाहते हैं। इनका एक जनरल रवैया इस मामले में यही रहा है और वि ोशकर सम्पत सिंह जी का, but it cannot be allowed. मुझे मजबूरी में इनको नेम करना पडा है। श्री जयपाल सिंह जी और श्री मनीराम जी का भी यही रवैया है, ये भी जाना चाहते हैं, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनीराम रूपावासः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आपसे कुछ कहना है ..... (व्यवधान)

Mr. Speaker: Sh. Jaipal Singh and Sh. Mani Ram Rupawas are also named. They may please leave the House. (Interruptions).

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। (ाोर एवं व्यवधान) इस तरह हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। (ाोर)

Mr. Speaker: I name Sh. Zile Singh. He may please leave the House.

(The Hon'ble Members did not withdraw from the House and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch & Ward Staff.)

(At this state Sergeant at Arms went to Sh. Zile Singh and took him out of the House with the aid of the Watch & Ward staff.)

Mr. Speaker: Sh. Jai Pal Singh and Sh. Mani Ram Rupawas may please leave the House.

श्री जयपाल सिंह: स्पीकर साहब, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। (ाोर)

Mr. Speaker: You have already been named. Please leave the House.

श्री मनीराम रूपावास: स्पीकर साहब ..... (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: आप तो दोनों भले आदमी हैं, आप तो बैठिए। (ाोर)

श्री जयपाल सिंहः जो बात हम कहना चाहते हैं, वह कहने ही नहीं दी जा रही, इसलिए हम बाहर चले जाते हैं। (व्यवधान)

(Sh. Jai Pal Singh and Sh. Mani Ram Rupawas left the House.)

विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना (पुनरारम्भ)

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मैंने कल सदन में दो ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिये थें (विघ्न) मेरा एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव हरियाणा में राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले कई सालों से विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के खाली पदों को भरने के बारे में था। पिछली सरकार के समय से ही कई पद राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में खाली पडे हैं, जिसकी वजह से पढाई का बहुत नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि खाली पद कितने हैं, उनको भरने के लिए क्या पग उठाए गए हैं, जब तक ये पद भरे नहीं जाते, तक तब इन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढाई के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा ध्यानाकर्शण प्रस्ताव हरियाणा के भाहरों में अन अथोराईजड कालोनीज के बारे में था। उन अन अथोराईजड कालोनीज में डिवैल्पमैंट का कोई काम नहीं हुआ है, वहा ंपर गलियां कच्ची हैं, नालियां कच्ची हैं, बिजली का प्रबन्ध नहीं है। इसलिए ये

कालोनीज भाहरों में स्लमज बनती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रीजनेबल चार्जिज ले कर इन कालोनीज की दिक्कतों को दूर करते हुए अथोराईजड कालोनीज बनाने के बारे में विचार करेगी ? स्पीकर सर, मेरे ये दो ध्यानाकर्शण प्रस्ताव थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन ध्यानाकर्शण प्रस्तावों के बारे में आपने क्या फैसला किया है ?

Mr. Speaker; Both are disallowed.

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, ये दोनों नितान्त आव यक हैं।

Mr.Speaker: Dr. Ram Parkash Ji, no more discussion on these call attention motions. Please take your seat.

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, किन ग्राउण्डज पर ये डिस अलाउ की हैं ? (विघ्न)

Mr. Speaker: Your first Call Attention Motion was regarding a large number of vacant posts of teachers of different categories in Govt. College/Schools in Haryana State, which has been disallowed on the following grounds :-

"1. The matter is not of recent occurrence;

2. You will have ample oppurtunity to raise the matter during the discussion on relevant demand."

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, दोनों ही बहुत आव यक हैं ..... (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (ाोर)

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, ये दोनों नितान्त जरूरी हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। No more discussion please. जो कुछ मैंने आपको बताया है, यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। आपकी दूसरी काल अटैं ान मो ान Regarding unauthorised Colonies which are existing in the Various Cities of Haryana, has also been disallowed, on the following grounds :-

"(i) That you have not raised the matter at the earliest opportunity;

(ii) that the matter is not of recent occurrence;

(iii) that you will have ample opportunity to raise the matter during discussion on the relevant demand."

श्री अमर सिंह: स्पीकर सर, मेरा कालिंग अटैं ान मो ान आपने अण्डर कंसिड्रे ान रखा था। स्पीकर साहब, 4 हजार आदमियों को फरीदाबाद में रोड बनाने की गर्ज से अपरूट कर दिया है। ये 4 हजार हरिजन थे, जो झुग्गी झोंपडियां डाल कर 20—25 साल से रह रहे थे। विदाउट ऐनी राईम एण्ड रीजन, उनको उठा कर फैंक दिया गया। जैसे कि ने ानल पेपर्ज से

जाहिर हुआ है कि यह जमीन किसी कांग्रेसी लीडर की थी। एक तीर से दो ि ाकार हो गये यानि जलसे का भी प्रोग्राम हो गया और आनरेबल कांग्रेसी लीडर की जमीन भी खाली हो गई, लेकिर हरिजन लोग बेघर हो गये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। एक तरफ तो सरकार यह दम भरती है कि वह हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिाज का काम करती है और दूसरी तरफ 20 सालों से आबाद लोगों को उनकी झुग्गी झोंपडियों से अपरूट कर दिया। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि ए0आई0सी0सी0 का अधिवे ान हो रहा है, जिसके कारण 4 हजार आदमियों को अपरूट किया जा रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, किसी आदमी के साथ ज्यादती करके उसे धक्के से फैंकने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई आदमी गलत जगह पर सडके के बिल्कुल किनारे पर बैठा है, तो सरकार का धर्म है कि उनको दूसरी जगह पर बिठा दें, ताकि यातायात में दिक्कत न हो। ये लोग अन अथोराईजड बैठे हुए हैं। किसी ने अचानक झौंपडी डाल ली या अचानक आकर झुग्गी बना ली तो सरकार कैसे उसको उस जगह पर रखेगी ? ए0आई0सी0सी0 के सै ान की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सारा साल यह प्रोग्राम चलता है कि कौन आदमी कहां बैठा है, कहां पर किस आदमी ने नाजायज कब्जा कर रखा है। और किस को ठीक करना है। (विघ्न) अगर किसी को कहीं से उठाते हैं तो

दूसरी जगह देंगे। (विघ्न) उनको दूसरी जगह पर बाद में ि ाफट करते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं।

11.00 बजे।

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सब मि ान करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, क्या आपका भी कोई कालिंग अटैन्ा ान मो ान है ?

प्रो0 राम बिलास भार्माः जी हां, अध्यक्ष महोदय, अगर आप स0ज0पा0 के भाईयों को बुला लें तो मैं बीच बचाव कर सकता हूं। उनकी बात भी पूरी हो गई क्योंकि चौधरी भजन लाल जी ने अपना स्पश्टीकरण दे दिया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है तो उनको बुला लिया जाए। दूसरा मेरा सबमि ान यह है कि नगरपालिकायों में, जहां जहां पर कांग्रेस के विरोध में लोग जीत कर आ गए हैं, उनको काम करना आज दूभर हो गया है। जीन्द की नगरपालिका का प्रधान एक हरिजन बन गया। कल उसके दफतर में उस पर गोली चलाई गई। अखबारों में तो खबर यह है कि गोली चलाने वालों को वहां के राजनीतिज्ञ का संरक्षण प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, वह आदमी वहां पर डी0सी0 की इजाजत से बोली करवा रहा था। स्पीकर साहब, कांग्रेस हो, चाहे बी0जे0पी0 हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, जन प्रतिनिधियों का आदर

होना चाहिये। इसी तरह पहले यमुना नगर की नगरपालिका का हमारा कार्यकर्ता प्रधान बन गया, उसको इनके मन्त्रियों ने हटा दिया।

श्री अध्यक्षः राम बिलास जी, आपका मो ान 10.15 पर मिला है। यह अन्डर कंसीड्रै ान है। इसलिए आप सारी बात नहीं कह सकते।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा भार्मा जी ने कहा है, मैं उसके मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी आपने कहा कि काल अटैन्ा ान मो ान अंडर कंसीड्रे ान है, इसलिए आप इन्हें मत बोलने दें या पहले मुझे पूरी बात कहने दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये जीन्द से लेकर यमुनानगर तक तो चले गए हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी पूरी मो ान पढने के लिए अलाउ नहीं किया है और मुख्य मंत्री जी पूरी बात का जवाब दे रहे हैं .....

Mr. Speaker: The Chief Minister has the right to intervene on every matter.

Prof. Ram Bilas Sharma: If he has the right, we have also our rights. We have a right to submit our material

before you. अगर आप उनको इजाजत देंगे तो हम भी अपनी पूरी बात बोलेंगे लेकिन आपने फरमाया कि यह अन्डर कंसीड्रे ान है और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। अगर मुख्य मंत्री जी इस पर विस्तार से जवाब दे दें तो कल को यह डिस अलाऊ हो जाएगी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी, मैं विस्तार से जवाब नहीं दूंगा।

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, He is going to violate your observations. They have no right to violate you observations.

श्री अध्यक्षः आपने जो काल अटैन्ा ान मो ान दिया है, आप सिर्फ उस बारे ही बोलें। आपने तो पूरी कथा ही पढ डाली है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कल साढे चार बजे जीन्द में झगडा हुआ और गोली चली, लेकिन वहां पर न तो कोई मरा है और न ही कोई गोली से जख्मी हुआ है। फिर भी हमने दोशियों के खिलाफ दाफ 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा भागा हुआ है, उसको भी भााम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, वहां पर 'बोली' को लेकर कोई झगडा नहीं हुआ है। यह तो 'बोली' रोकने की बात करते हैं ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री राम बिलास भार्मा जी ने सुझाव दिया कि सजपा के साथियों को अन्दर बुला लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। धरने भी जो जाते हैं, भाोर भी मचता है। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में तो यह एक तरीका होता है तथा जीरो ओवर में तो ऐसी बातें हो ही जाया करती हैं। इसके अलावा जब भार्मा जी ने यह कहा कि वह बीच बचाव करने के लिए तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि यह सुझाव इनको मान लेना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौ0 बंसी लाल जी का हम बहुत मान सम्मान करते हैं, वे बहुत सीनियर मैम्बर हैं इसी तरह से राम बिलास भार्मा जी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है कि किस तरह का उनका रवैया है, किस तरह का उनका ढंग है, किस तरह से वे लोग हाउस को चलने नहीं देते हैं ? अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति इस बात को देखेगा तो वह पसन्द नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनकी तो यह प्री प्लान है कि किसी तरह से भी भजन लाल के दामाद को लेकर इन्हें परे ाान करो। ये सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया और पता नहीं क्या गडबडी कर रखी है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भजन लाल की छवि को धूमिल किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, एक पैसा भी उनकी तरफ बाकी नहीं है। मेरे पास सारा लिखा

हुआ है। अगर कोई भी आदमी लोन लेकर अपना काम चलाता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है ? हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा कौन सा आदमी है जो कहीं से भी लोन लेकर अपना काम न करता हो ? अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इनके बर्ताव को देखत हुए होना तो यह चाहिए कि इनको कल के लिए भी हाउस से निकाल देना चाहिये लेकिन हम यह नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हाउस का माहौल ठीक रहे, हाउस का काम ठीक तरह से चले। लेकिन ये लोग हाउस को ठीक तरह से नहीं चलने देना चाहते। अध्यक्ष महोदय, इनके पास कहने को कोई बात तो है नहीं इसलिए ये लोग दूसरों की बातें भी सुनना नहीं चाहते। ये अपनी बात को तो कह लेते हैं, लेकिन इनमें हमारी बात को सुनने की भाक्ति भी नहीं है। अगर ये यहां पर बैठे तो कम से कम हमें भी कहने का मजा आये कि जो इन्होंने कहा था उसका सवा सेर जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये लोग बगैर सिर पांच की बातें करते हैं। अगर कोई आदमी अपनी बात कहे तो उसकी बात का कोई आधर भी तो होना चाहिए ? अगर किसी आदमी पर बगैर मतलब के इलजाम लगायें जायें तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब ने जो फैसला किया है, वह ठीक है और वह फैसला लागू रहना चाहिए।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कह दिया और इन्होंने जवाब दे दिया, ये कहते हैं कि इन्होंने उनको सेर से सवा सेर तौल दिया। अध्यक्ष महोदय,

डैमोक्रेसी में तो यह होता ही है यह इन्होंने भी देखा है और मैंने भी देखा है। लोकसभा में तो इससे भी ज्यादा भाोर होता है। पूरे पूरे दिन हाउस ऐडजर्न हो जाता है। यहां तक कि तीन तीन चार चार दिन तक हाउस लगातार ऐडजर्न रहता है। मैं समझता हूं कि पार्लियामैंटरी डेमोक्रेसी का यह एक हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, अगर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा तो वे लोग भााम तक ऐसे ही बैठें रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको हाउस के अन्दर बुलाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपने उनको नेम कर दिया, वे हाउस से चले भी गए और यह ठीक भी हैं लेकिन जब इन्हौंने उनको सवा सेर तौल दिया है तो अब उनको हाउस में बुला लेना चाहिए। इसमें इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वह इनको सवा सेर तौलते हैं तो उनको इन्हें डैढ सेर तोल देना चाहिए।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हामरे संरक्षक हैं, इसलिए अब आप उनको हाउस में बुला लीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो आ ाा कर रहा था कि आप इस पर कुछ निर्णय लेंगे। मेरी आपसे गुजारि ा है कि जब उन्होंने आपकी भाान में गडबडी की थी, बात की थी, तो भी उस बात का फैसला हो गया था और वह हाउस में भी आ गये थे। स्पीकर सर, सरकार से तो हम रोज झगडते ही रहते हैं, इसमें कोई वि ोश बात नहीं है। इसलिए उनको आप हाउस में

बुला लें। सरकार नें सवा सेर तो उनको तौल ही दिया है, इसलिए अब कुछ भी नहीं रह गया। अब तो आपको उन्हें बुला लेना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, मैं इन सबके बिहाफ पर कहता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, we are all here to serve our masters, the electorates, and they are very closely watching our conduct and deliberations. I owe it to the House that the discussions are held in a free and frank manner and are not interrupted on trivial and irrelevant grounds. This I wish to ensure to the best of my ability. I am open to suggestions from the senior legislators and even from other friends to ensure the achievement of this object. But I do expect the members also to observe the high standard of conduct which helps to maintain the highest tradition of this House and raise its dignity.

I, therefore, appeal, especially the leaders of all the parties and various groups in this House, that they should ensure that our deliberations are conducted in accordance with the spirit of the rules and the Members of their parties or groups, remain within limit an maintain decorum, decency and deiscipline in the House. I am also under obligation to maintain order in the House.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, आज के इस आधुनिक युग में जहां हम रहते हैं, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आपकी कोई काल अटैं ान मो ान है ?

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरी काल अटैं ान मो ान एडमिटिड है। मैंने कोई और बात कहनी है और मैं जीरो आवर में बोल रहा हूं।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

(1) पलवल भाहर के मकानों में दरारें पडने संबंधी

श्री अध्यक्षः आप अपनी सिर्फ वही काल अटैं न मो ान पढेंगे।

Hon'ble Members, I have reccieved a Calling Attention Notice No. 15, given notice of by Sh. Karan Singh Dalal M.L.A. regarding the crakcs developed in the house of Palwal city. I admit it. Sh. Karan Singh Dalal may please read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पलवल भाहर की आबादी एक लाख से अधिक है और यह टेक पर बसा हुआ है। अभी हाल ही में भाहर के मकानों में दरारें पड गई हैं तथा कई मकान जमीन में धंस गए हैं नव निर्मित मकानों में बडी बडी दरारे आ गई हैं जिसके परिणामस्वस्प लोगों की जान तथा माल का खतरा बना हुआ है।

इस संबंध में सरकार की ओर से कोई भी राहत कार्य नहीं किया जा रहा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस भयंकर समस्या के बारे में वह सदन में एक वक्तव्य दें।

Mr. Speaker: Now I will request the Minister of State for Local Govt. to make a statement.

वक्तव्य–

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Minister of State for Local Govt. (Ch. Dharmbir Gauba): Speaker, Sir, Palwal City has a population of 59168 as per 1991 census and not one lac as mentioned in the Call Attention Notice. In the town there is a Thain Mohalla which is located on mound about 20-25 meters high. On this mound there are about 80 houses with a population of about 375 persons. Cracks in some houses in this locality were noticed in the year 1981-82. In all 26 houses had been found to have been affected. The Geological Survey of India was conducted for investigating the matter and they conducted detailed surveys. In the report submitted by them in 1981-82, it was mentioned that the cracks had developed on account of settlement of soil under neath the houses. The reasons given for this settlement were :-

(i) Elastic compression of the foundation soil,

(ii) Slow creep in foundation soil due to saturation,

(iii) Underground erosion, compaction settlement due to sub surface flow.

(iv) Filled up nature of the ground,

(v) Change in water regime below the foundation,

(vi) Improper foundation design and poor quality of construction.

The Geological Survey report also advised the Municipal Committee to take speacial care regarding leakages from drains, water pipe lines and sewerage lines in the area.

2. Recdently, about 1½ months back similar cracks were noticed in 2 other houses in the same part of the mohalla. The Municipal Committee Palwan looked into the matter and repaired afresh, all leakages from the drains in the affected area. Since such leakages also take place on account of use of water inside the houses, the house owners have also been advised to repair the leakages etc. if any, inside the houses.

3. No new houses are being constructed in this locality. Almost all houses in the locality are provided with water and sewerage connections. In 1981-82, 26 houses, of which reference has been made above, were declared unfit for further deterioration in the situation after 1982. In 1982-82 the Municipal Committee also removed the upper storeys of the houses in the affected area, so as to reduce the possibility of further subsidence.

4. No house in the area has collapsed and there has been no loss of life. All the houses in this locality are very

very old and some of them may be about 100 years old. the municipal authorities are alive to the situation and are taking all possible remedial measures.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार ने किस तरीके से इतने अति आव यक लोक महत्व की बात को किस तरह से पे ा किया, यह पढकर बडा अजीब लगता है। मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में खुद माना है कि पलवल में थाई मौहल्ला लगभग बीस पच्चीस मीटर ऊंचे टीले पर स्थित है। स्पीकर साहब, वहां पर अढाई सै या तीन सौ घर हैं लेकिन इन्होंने कहा कि वहां पर लगभग अस्सी मकान हैं। स्पीकर साहब, ये लोग पिछले पचास साल से वहां पर बसे हुए हैं और पिछले एक डेढ साल से वहां पर मकानों में क्रेक आ रहे हैं। कई पुराने मकान हैं जो जमीन में धंस गए हैं जो कारण इन्होंने बताए है वे हैं नींव की मिटटी के दबाव में लचीलापन, नींव की मिटटी में पानी के समावे ान के कारण नींव का हिलना, जमीन के नीचे पानी के बहाव के कारण मिटटी की सतह का कटना, जमीन की भरपाई का त्रुटिपूर्ण तरीका, नींव के नीचे पानी की सतह में परिवर्तन, नींव की त्रुटिपूर्ण भरती तथा घटिया किस्म का निर्माण।

स्पीकर साहब, यह रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई है और उसमें कहा है कि जो मिटटी उन मकानों के नीचे है, उसमे ंपानी होने से वहां पर लचीलापन आता है इसलिए मकान की दीवारें धंसनी भ्ाुरू हो जाती हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर

समस्या के बारे में इनके महकमें ने क्या कार्यवाही की ? दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने उन लोगौं को वारनिंग दी कि यह जगह रहने के लायक नहीं है तो क्या इन्होंने उनको जगह वगैरह दी जहां वे लोग अपने मकान बना सकें ? स्पीकर साहब, वे लोग कहां जाए ? क्या सरकार ने उनको रहने की दूसरी सुविधा दी है ?त्र वहां पर काफी मकानों में दरार आ चुकी है, कई मकान धंस गए हैं। जब मैं वहां से चला थ तो कई मकानों की बुरी हालत थी और कल परसों फिर टेलीफोन आया कि मकानों में दरारें आ रही हैं और नीचे धंस रहे हैं।

चौधरी धर्मबीर गाबाः जैसा कि मैंने बताया है कि नींव की मिटटी में पानी चले जाने के कारण नींव हिल जाती है और वह नीचे चली जाती है। स्पीकर सहअ, ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा हमने एक सर्वे कराया था। यह विभाग गवर्नमैंट आफ इण्डिया का है। उन्हौंने बताया कि अगर कहीं भी पानी की लीकेज हो जाती है तो पानी मिटटी में नीचे चला जाता है इसी कारण मकान की दीवारों में दरारें पैदा हो जाती हैं। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी को भी यह कहा कि वह सीवरेज का पानी, ड्रेनेज का पानी और वाटर वर्कस का पानी किसी तरीके से लीक न होने दें। यही बात वे मालिक मकानों के लिये भी एडवाईस करते हैं कि अगर उनके मकानों के अन्दर पानी की सप्लाई के कारण लीकेज है, तो जल्दी ही उसको पलग किया जाए ताकि पानी मिटटी के अंदर न आने पाए और क्रैक भी न बढें। इसके अलावा दूसरा उन्होंने एक

सुजे ान यह भी दिया है कि बारि ा के वक्त कहीं भी दरार या मिटटी जमीन के अन्दर नहीं होनी चाहिये ताकि पानी घुलकर मकानों की नींवों तक न पहुंचे। ऐसे पानी की लीकेज को एकदम ही बन्द कर देना चाहिये इस तरह की एडवाईस हमने जारी भी कर दी है। एक और बात भी है सीवरेज के जो सर्फेस टैन्कस वहां पर लगे हुए हैं, उनकी भी लीकेज नहीं होनी चाहिये इसलिये म्यूनिसिपल कमेटी ने यह कोि ा ा की है कि हरेक को सीवरेज का कनैक ान दे दिया जाए। ये टैक्स अलग न रहें और पानी के जितने भी कनैक ांज हमने दे दिये हैं उन सब की रिपेयर कर दी जाए। इसके अलावा जितनी भी ड्रैनेज खराब थीं नालियां खराब थीं उन की भी हमने रिपेयर कर दी है। माननीय सदस्य ने कहा है कि पलवल भाहर की एक लाख की आबादी है। सैंसज से बडी चीज कोई नहीं होती, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वहां की आबादी 59168 है न कि 1 लाख। इन सभी बातों के बारे में हमने ज्योलीकल सर्वे आफ इण्डिया वालों को दोबारा लिख दिया है और हमने दोबारा सर्वे करने के लिये रिकवैस्ट की है और जैसा मैंने पहले बताया कि आज से डेढ महीने पहले 2 हाउसिज में क्रैक आए हैं। हमने तभी कहा कि सर्वे दोबारा करवा दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम सर्वे के द्वारा किसी को ठीक करवा सकते हैं, तो दोबारा सर्वे जरूर करवा लेना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वह मौहल्ला जिसका मेरे भाई जिकर कर रहे हैं, मेरा भी देखा हुआ है। कर्ण

सिंह जी जितना आपका भाहर पलवल है, उतना मेरा भी है। उस मौहल्ले में आपसे ज्यादा मेरे रि तेदार रहते हैं, सलूजाज रहते हैं, मेरी सिस्टर वहां पर रहती है। मुझे उस मौहल्ले का ज्यादा पता है। लेकिन इसके बावजूद दलाल साहब ने मेरी रिकवैस्ट है कि आपके पास, अगर कोई प्रैक्टीकल सुझाव हैं जिससे यह सिलसिला रूक सकता हो तो उन सुझावों को हम वैलकम करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सुझाव दें और हम वैलकम न करें। अगर सौलिड सुझाव होंगे तो हम वैलकम करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल भाहर के बारे में एक मिसाल म ाहूर है कि पलवल की सडकों पर घोडा दौड ही दौडा जाए। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री महोदय ने वहां से चुनाव लडा था तो उनको घोडा उन सडकों पर दौडा ही था। उन्होंने उस भाहर का जो दौरा किया था वह एक बडी ही महत्वपूर्ण बात है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मैम्बर्ज से सुझाव मांगें हैं। मैंने पलवल के संबंध में एक काल अटैन्- ान मो ान भी दिया था लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेवारी को सदन में मानने वाले नहीं हैं। असलियत जो है, वह सीवरेज की बीमारी है। जो सीवरेज के पाईपस थे हम मानते हैं कि वे इन्हों डल्वाए हैं और ये यह भी मानते हैं कि वहां पर जो पीने के पानी के पाईपस हैं उनमें लीकेज है। बार बार हमारे कहने के बावजूद लीकेज बन्द नहीं की। अभी सैं ान भाुरू होने से पहले जब क्रैक्स आने भाुरू हुए ता`उनको देखने के लिये कोई नहीं गया। जो पीने के पानी का

पाईप फटा था, उसका पानी बह बह कर मकानों की नींवों तक पहुंच रहा है। काफी दिनों तक भाोर मचाने के बावजूद भी कमेटी का कोई मुलाजिम देखने के लिए नहीं गया जब दोबारा हमने एस0डी0एम0 को कहा तो पब्लिक हैल्थ के कुछ मुलाजिमों ने वहां जाकर उसकी देखरेख की। कमेटी वालों ने साइकिल की एक टयूब को इस तरह से उस पाईप पर बांध दिया ताकि पानी रूक जाए। स्पीकर साहब, साईकिल की टयूब से ये पानी रोकने की कोि ा ा करते हैं। पानी के पुराने पाईपस जो बहुत सालों से डले हुए हैं जब तक उनको बदला नहीं जाएगा तब तक इस भयंकर समस्या से पीछा नहीं छूटेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गलियों में जो मकान हैं, वे 60 के ऐगंल पर झुके हुए हैं। और मन्त्री जी ने उन्हें देखा भी होगा पर पता नहीं मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है या नहीं और पता नहीं वे किस तरह से कहते हैं कि वह मौहल्ला मेरा देखा हुआ है। उन्हें भाायद यह आभास नहीं होगा कि वे मकान बिल्कुल गिरने की हो रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां से फौरन ही लोगौं को निकाला जाए और उस इलाके को खाली करवाया जाए और उन लोगों को वह जमीन दी जाए जो म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पलवल भाहर में पडी हुई है और जिस जमीन पर ये आपसी डिपार्टमैंटल अधिकारियों की मिली भगत से दूसरों का कब्जा करवाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, पैसे ले लेकर कब्जा करवा रहे हैं। ऐसे नाजायज कब्जों को तुडवा कर उन लोगों को वह जमीन दी जाए ताकि वे अपने रहने के लिये मकान बना कर सकें, जिनके मकान

बिल्कुल गिरने को हैं जो लीकेज चाहे पाईपों में है, चाहे कहीं और है या सीवरेज में है या पीने के पानी के पाईपों में है, वे पाईपस न केवल ठीक करवाएं जाए बल्कि उनकी तुरन्त लोगों की भलाई के लिये बदला जाए क्योंकि वे बहुत पुरान पाईप हैं। चाहे सीवरेज के हैं या पानी के हैं सारे गले हुए हैं। यही समस्या हमारे पलवल भाहर की है। वहां न सिर्फ मकान गिरने को हैं बल्कि जो पीने का पानी गन्दा आता है, उसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग गई हैं, इसके बारे में मैंने कल ध्यानाकर्शण प्रस्ताव भी दिया था।

चौधरी धर्मबीर गाबाः स्पीकर साहब, ये क्रेकस जो आए हैं, ये 1981–82 से यानी आज से 10–11 साल पहले के आए हुए हैं, अब नहीं आए। इनकी रिपेयर करवा दी गई है इसी वजह से ये क्रैकस रूके हुए हैं। इस वक्त कमेटी की कोई भी पाइप लाइन ऐसी नहीं है जो उस मुहल्ले से गुजरती है और वह टूटी हुई हो। इसके बावजूद भी हम यह चाहते हैं कि जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि हमने गवर्नमैंट आफ इण्डिया को इस बारे में एक लैटर लिखा है। हम वहां पर दोबारा सर्वे करवाना चाहते हैं ताकि अगर उनसे हमें कोई सुझाव मिले तो हम उन पर अमल कर सकें। वहां पर जो स्ट्रकचर्ज हैं वे इतने पुराने हैं कि कई मकान तो करीबन सौ साल पुराने हैं। उन पर जो डबल मंजिल बनी हुई थीं, उनको हटा दिया है ताकि जमीन पर ज्यादा जोर न पडे। उसके बाद आप देखें और मानेंगे कि उन मकानों में से आज तक कोई

ि ाफट करने नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि इतना तो कमेटी ने कर दिया है कि फर्दर उनमें दरारें न पडें और उनकी रिपेयर करवा दी जाए।

(2) पानीपत थर्मल पावर प्रोजैक्ट द्वारा किये जा रहे प्रदूशण संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice No. 23 given notice of by Sarvhsri Sabir Singh Kadian and Krishan Lal, M.L.As. regarding the pollution created by the Panipat Thermal Power Project. I admit it. Sh. Satbir Singh Kadian may please read his notice.

(Since neither Sh. Satbir Singh Kadian nor Sh. Krishan Lal, members, were present in the Hose, the notice was not read out.)

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for grants on Budget for the year 1993-94 will take place.

As pere the past practice and in order to save the time of the House all the demands for grants on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon. Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion. The notices of cut motions given by Sh. Bansi Lal, M.L.A. on demand Nos. 2 & 3 Sh. Ram Bhajan Aggarwal, M.L.A. on demand No. 5, Sarvshri Bansi Lal, Amar Singh &

Sh. Chhatter Singh Chauhan, M.L.A. on demand No. 9, Sh. Chhatter Singh Chauhan M.L.A. on demand No. 10, Sh. Amar Singh M.L.A. on demand No. 13, Sh. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. on demand No. 15 and Sh. Amar Singh, M.L.A. on demand No. 17, will also be deemed to have been read and moved.

That a sum not exceeding Rs. 22588000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 523465000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 2- General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1521798000 for revenue expenditure and Rs. 40000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 3- Home.

That a sum not exceeding Rs. 400438000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 4- Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 134096000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1993-94 in respect of charges under Demand No. 5- Excise & Taxation

That a sum not exceeding Rs. 1098652000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 6- Finance.

That a sum not exceeding Rs. 2047584000 for revenue expenditure and Rs. 800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 735452000 for revenue expenditure and Rs. 753718000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 8- buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 467545000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 9- Education.

That a sum not exceeding Rs. 2009310000 for revenue expenditure and Rs. 426200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 10- Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 132697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 11- Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 289969000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 12- Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1922615000 for revenue expenditure and Rs. 35431000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 66902000 for revenue expenditure and Rs. 1965166000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 14- Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 3022060000 for revenue expenditure and Rs. 886840000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 265901000 for revenue expenditure and Rs. 93240000 for capital expenditure

be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 16- Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1062710000 for revenue expenditure and Rs. 2000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 17- Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 346402000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 48497000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 19- Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 537524000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 20- Forest.

That a sum not exceeding Rs. 763476000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 21- Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 129182000 for revenue expenditure and Rs. 89187000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 22- Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 2304828000 for revenue expenditure and Rs. 355400000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 23- Transport.

That a sum not exceeding Rs. 8423000 for revenue expenditure and Rs. 24000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 24- Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2765836000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 25- Loans & Advances of State Government.

DEMAND NO. 2 (GENERAL ADMINISTRATIONS)

SHRI BANSI LAL:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 3 (Home)

SHRI BANSI LAL:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 5 (Excise & Taxation)

SHRI RAM BHAJAN AGGARWAL:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 9 (Education)

SHRI BANSI LAL,

SHRI AMAR SINGH,

SHRI CHATTAR SINGH CHAUHAN:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 10 (Medical & Public Health)

SHRI CHHATTAR SINGH CHAUHAN:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 13 (Social Welfare & Rehabilitaiton)

SHRI AMAR SINGH:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 15 (Irrigation)

SHRI CHHATTAR SINGH CHAUHAN:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

DEMAND NO. 17 (Agriculture)

SHRI AMAR SINGH:

That the Demand be reduced by Re. 1/-

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैंने भी डिमांड नं0 7 और 8 पर कट मो ांज दी थीं, उनका क्या बना ?

श्री अध्यक्षः वे डिस अलाउ हो गई हैं। आपको कारण भेज दिए हैं कि वे इन आर्डर नहीं थीं।

श्री बंसी लाल (तो ाम): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 2, 3 और 4 पर बोल रहा हूं। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रे ान का सवाल है, मैं समझता हूं कि हरियाणा में जनरल एडमिनिस्ट्रे ान तो है ही नहीं, यहां पर इतने फाईनैंि ायल कमि नर्ज बैठे हैं और इतने कमि नर्ज बैठे हैं इनके काम का सही वितरण नहीं है, यानि एक जूनियर औफिसर को होल टाईम, एक की बजाये दो पोस्टें दे दी जाएं .....

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, ऐसा है कि ग्रुपवाईज जितने भी माननीय सदस्यों ने कट मो ांज दी हैं, उनको बोलने के लिए टाईम देना है इसलिए आप टाईम का ध्यान रखना।

श्री बंसी लालः ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं टाईम का ध्यान रखूंगा। मुझे इस बारे में पता है कि आपने सभी उन सदस्यों को बोलने के लिए टाईम देना है जिन्होंने आपको कट मो ांज दी हैं मैं केवल 2, 3 और 4 नम्बर डिमांड पर ही बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान की डिमांड नं0 2 है। जैसे मैंने पहले कहा है, हरियाणा में जनरल एडमिनिस्ट्रे ान नाम की कोई

चीज है ही नहीं। वह क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे इतने फाईनैंि ायल कमि ानर्ज और इतने कमि ानर्ज बैठे हैं जिनके पास महीने या दो महीने में कोई एकाध फाईल आती है, और कुछ आफिसर्ज तो ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग यहां चण्डीगढ में भी है और दिल्ली में भी है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जिस आफिसर को जहां चाहे वहां लगा देते हैं और उनके काम का वितरण ठीक ढंग से नहीं करते, जिसके कारण औफिसर्ज का आपस में तालमेल ठीक नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, खास तौर पर सीनियर औफिसर्ज की हालत तो यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की बात तक कहूं न,ख जब हरियाणा में जनरल एडमिनिस्ट्रै ान हो। जनरल एडमिनिस्ट्रे ान हो तो कहूं, याहं तो कुछ है ही नहीं। एक औफिसर आज यहां, कल वहां, परसों वहां और तरसों वहां यानि एकदम एक आफिसर को महीने महीने दो दो महीने और तीन तीन महीने में बदल दिया जाता है। कोई फाईल चलती नहीं है। ला एंड आर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि ला एंड आर्डर सेफ नहीं है। श्री राम बिलास भार्मा बता रहे थे कि जींद में क्या हुआ ? मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी खुद अपने डिस्ट्रिक्ट हिसार में देखें कि यहां पर ला एंड आर्डर का क्या हाल है। उस डिस्ट्रिक्ट में कितने आदमी मर्डर हुए हैं, कितनी डकैतियां हुई हैं और कितना क्या कुछ हुआ है। मुख्य मंत्री जी खुद अपने डिस्ट्रिक्ट को देखें कि यहां पर ला एंड आर्डर की क्या हालत है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत दिन हो गए, जब से ये मुख्य मंत्री बने मैं तब से आज तक, ये और

इनकी सारी म ीनरी– क्या पुलिस कप्तान, क्या वहां का डी0सी0, सब हिसार ट्रक यूनियन पर लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप अब तो कम से कम हिसार ट्रक यूनियन का पीछा छोड दें और अपने जनरल एडमिनिस्ट्रे ान को चलाएं, उसमें ज्यादा फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक होम डिपार्टमैंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि होम और ला एंड आर्डर, एक ही हैं लेकन उनमें इस बात की कमजोरी है कि उनको आपस में मेलजोल नहीं हैं, उन पर आपस में कोई कंट्रोल नहीं है और उनका आपस में तालमेल नहीं है। उनका आपस में तालमेल क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि डी0जी0पी0 पर पुलिस फोर्स का वि वास नहीं है। वह डी0जी0पी0 किस चीज का, जो फोर्स पर अपना कांफीडैंस मैनटेन नहीं कर पाता। यह किस महकमें का अधिकारी है जो अपनी फोर्स का वि वास नहीं जीत सकता ? यह सबसे बडी बीमारी है कि किसी आफिसर पर उनकी फोर्स का वि वास न हो, तो मैं इस बारे में मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि जो पुलिस रूल्ज हैं वह 1836 के बने हुए हैं और आज तक लागू हैं। उन रूल्ज के हिसाब से पुलिस फोर्स को यूनियन बनाने की इजाजत दी जाए ताकि इस महकमें का और सरकार का आपस में तालमेल ठीक तरह से बना रहे। पुलिस वालों को एक ि ाकायत है कि एस0पी0, डी0आई0जी0, डी0जी0पी0 और आई0जी0 को जो अरदली दिए जाते हैं, उनको नम्बर दे देते हैं। एस0पी0 के अरदली को 1 नम्बर, डी0आई0जी0 के अरदली को 2 नम्बर, डी0जी0पी0 के अरदली को 3 नम्बर और वही आदमी ट्रेनिंग

के लिए चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नम्बर देकर उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है जो आदमी 24 घंटें अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है, उस आदमी को इस तरह डिस अप्वायंटमैंट होती है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार को दिल्ली की सरकार से 35 करोड रूपये मिले। लेकिन उसमें क्या हुआ ? न तो इन्होंने आतंकवादियों के लिए सैल बनाया हुआ है, न उनके पास गाडियां हैं और न ही प्रौपर हथियार उनको दिए गए हैं। जब उनके पास गाडियां नहीं होंगी तो वे जायेंगे काहं ? अगर उनके पास प्रौपर असला नहीं होगा, प्रौपर व्हीक्लज नहीं होंगे तो उनसे कोई एक्टिवीटिज नहीं हो सकतीं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भिवानी जिले के निमली गांव की एक लडकी और उसकी एक साल की लडकी को सालहावास गांव में मार कर कुएं में डाल दिया गया। इस मामले पर कई गांवों की पंचायत हुई। मगर वहां के एस0एच0ओ0 ने सारा मामला ही रफा दफा कर दिया। इसी प्रकार से भिवानी जिले में रिवासा गांव में एक 12 साल की हरिजन लडकी का रेप किया गया। पुलिस 3–4 दिन तक हरकत में नहीं आई। बाद में जब भिवानी जिले के एम0ए0लए0 ने उसमें दखल दिया तो इस बारे में कुछ कार्यवाही हुई। इसी प्रकार नीसिंग कांड हुआ। उसे नीसिंग कांड क्यों कहें बल्कि यह तो निसिंग मर्डर केस है। जहां पर मुख्य मंत्री जी की स्टेज थी, उससे डेढ किलोमीटर के फासले पर लोगों पर गोलियां चलाई गईं। अगर कोई हजूम तोड कर मुख्य मंत्री जी की स्टेज पर आता या पुलिस पर हमला

करता तो मैं यह मान लेता कि पुलिस ने गोली चलाई। मगर डेढ किलोमीटर के फासले पर जाकर गोली चलाना तो कोल्ड ब्लड मर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी उन गांवों में होकर आया हूं। वहां पर दो आदमी तो मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं लखपति राम, माम चन्द, गुनी प्रसाद, राम कि ान, मेहर सिंह, चौधरी ई वर सिंह और उधम सिंह की गोलियां लगी और वे घायल हुए। इसके अलावा, बहुत से आदमी लाठियों से जख्मी हुए। इसके लिए जुडीि ायल इन्कवायरी सरकार को करवानी चाहिए। जो लोग वहां पर मारे गए हैं, वे आपके कोई दु मन नहीं हैं, उनको हरियाणा सरकार मुआवजा दे, कम्पनसे ान दे, यानी उनके जख्मों को भरने की तरफ कोई कदम उठाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में कल परसों एक सवाल के जवाब में बताया कि 4218 भर्ती हुए हैं। जब बडे पैमाने पर भर्ती हो तो उस समय डिस्ट्रिक्ट लैवल पर मेले लगा लगा कर भर्ती होनी चाहिए, न कि बैक डोर से। पिछले सै ान में भी यह बात आई थी और आज भी यह बात चलती है कि भर्ती मुख्य मंत्री जी के भााहबजादे ही कर देते हैं। तो मैं मुख्य मंत्री जी को आपके जरिए कहूंगा कि वे इस कलंक को हटा लें और मैले करके भर्ती किया करें। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बाला में एक ताराचन्द हैड कांस्टेबल था। जब आतंकवादी अदालत से उस एक आतंकवादी को छुडाने आए तो उसने उस आतंकवादी को ए0के0 47 रायफल सहित जफफी भर ली और उसको दूसरे आतंकवादी ने गाली से मार दिया। अगर इस स्टेट में पुलिस वाले किसी एवार्ड के हकदार

हैं तो सबसे ज्यादा वह था लेकिन उसके डिपेन्डैंट को आज तक नौकरी नहीं दी गई, कोई एवार्ड नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि उसको एवार्ड दिया जाना चाहिए। ऐसे आदमियों को हौंसला अफजाई न करने से क्या होता है कि फोर्स में डिमोरेलाईजे ान आती है। फिर वह सोचेगा कि कितनी ही बडी कुर्बानी कर दो, होना तो कुछ है नहीं। तो यह टेडैंसी बनी रहेगी और काम ठीक नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, भिवानी में एक एस0डी0 हाई स्कूल है। कलकत्ता में एक ट्रस्ट है, ज्ञान राम चिडी राम का उसने वह बनाया था। उस पर भिवानी के एक एक्स एम0एल0ए0 ने चाहे उसको एक्स एम0एल0ए0 कहो या एक्स मिनिस्टर कहो, कब्जा कर रखा है। उसने 1980 में हरियाणा सरकार को यह लिख दिया कि इन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है कि इनको ग्रान्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा साहूकार स्कूल तो मैंने यही देखा जिसको ग्रान्ट की कोई आव यकता नहीं। ग्रान्ट की आव यकता क्यों नहीं ? जो पुराने टीचर थे जिनको 2500–2500 और 3000–3000 रूपए तनख्वाह मिलती थीं उनको तो निकाल दिया और अपने आदमी 500–500 और 700–700 रूपए पर रख लिए। अध्यक्ष महोदय, उस स्कूल में 1300 या 1350 के करीब बच्चे हैं। उनसे फीस ली जाती है, उस फीस में से आधी फीस जमा होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह भाख्स एक लाख रूपया महीने के करीब उस स्कूल से बनाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी पूरी जांच करवाए और कायदे कानून की रूह से उस स्कूल की कार्यवाही करे। जो अदालत ने हुकम दिया है उसकी तामील कर

दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि हर चीज में राजनीति न लाएं। इसमे ंभी राजनीति है। यह बनिये का बनाया हुआ स्कूल है। कलकत्ता का ट्रस्ट है और ट्रस्ट के मालिक वहां रहते हैं तथा गवर्निंग बौडी यहां बना रखी है। दीवानी अदालत ने उस गवर्निंग बॉडी को जो यहां मैनेजमैंट कमेटी है, उसको पार्वज दे दी। अब जिले के अधिकारी कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा विधान सभा का सै ान खत्म होने के बाद ही कोई कार्यवाही करना, पहले कोई कार्यवाही न करना। अब सै ान भी कल खत्म हो जाएगा तो मुख्य मंत्री जी परसों कोई कार्यवाही कर लें।

फरीदाबाद जिले में माईन्जल में टैक्स की चोरी को हटाने के लिए, वहां अच्छी तगडी फोर्स का प्रबन्ध किया जाए। जब तक वह नहीं किया जायेगा, हरियाणा सरकार को 4—5 लाख रूपये रोज का घाटा होता रहेगा। मांगेराम गुप्ता जी एक दो दिन वहां खुद जाकर बैठें, तो भाायद खजाने में कुछ आ जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बातें तो बहुत कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के आदमी अभी बोलने बाकी हैं, इसलिए मैं यह बात कह कर आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टैक्से ान के बारे में सरकार का वि ोश ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि प्रदे ा के अन्दर व्यापारी बहुत दुखी हैं। यह विभाग करप ान का

इतना बडा अडडा है कि सरकार के खजाने में पैसा न आकर दूसरी जगह जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्स के सरलीकरण का सवाल है, वह नहीं हो पा रहा है कि कोई साधारण व्यापारी भी उसके अंदर फंसे बिना नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चुंगी का मामला है। चुंगी के मामले में आदरणीय मांगे राम गुप्ता जी से सदन में स्पश्टीकरण चाहूंगा, वे हां या ना में बताएं कि क्या चुंगी को हटाया जा रहा है या उसको उसी तरह बरकरार रखा जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स और बैरियर्ज का सवाल है, हमारी स्टेट के अन्दर जो बैरियर्ज हैं, वहां पर इनती करप्ान है कि बैरियर्ज के अधिकारी बिना कुछ लिये दिये किसी ट्रक या व्हीकल को पास नहीं होने देते। ट्रकों और व्हीकल्ज को पास करवाने के लिए या तो उनकी खुाामद करनी पडती है या एडजस्टमैंट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स, मार्कीट कमेटीज और दूसरी चीजों का सवाल है, उस बारे मैंने पहले भी कहा था। मुख्य मंत्री जी एक व्यापारी सम्मेलन में आने वाले भी थे, लेकिन किसी वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या व्यापारी वर्ग को कोई रिलीफ देने का सरकार का विचार है ? मैं चाहूंगा कि व्यापारियेां को जो रिलीफ देने की बात है, उसके बारे में हाउस के अंदर आ वासन दिया जाए कि महसूल चुंगी को हटाया जाएगा या नहीं, सेल्ज टैक्स का सरलीरकरण किया जाएगा या नहीं ? अगर सरलीकरण किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, टैक्स को ठीक करने के लिए

मेरा सुझाव है कि एक कमेटी बना दी जाए जो आपको सुझाव दे। मैं चाहता हूं कि टैक्स सरकार को आए। टैक्स आना तो जरूरी है, टैक्स आता तो है लेकिर सरकारी खजाने में न आकर, दूसरी जगह जाता है। इस तरह से सरकार को बहुत बडा घाटा पड रहा है। इस घाटे को रोकने के लिए यह अत्याव यक है कि इसका निदान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहूंगा कि मन्त्री जी आ वासन दें कि सरलीकरण कब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, 25 के लगभग डिमाण्डों पर इस सदन में विचार होना है। मैं वि ोश तौर पर डिमाण्ड नं0 17 जो एग्रीकल्चर के बारे में है, 5–7 मिनट कुछ बात कहूंगा। आजकल डंकल रैजोल्यू ान का बहुत भारी चर्चा हो रहा है। स्पीकर सर, मैं यह तो क्लेम नहीं करता कि डंकल प्रस्ताव के बारे में मुझे बहुत नौलेज हैं, परन्तु जो कुछ अख्बारात में पढा है या 1–2 दोस्तों से जो जानकारी मिली है, मैं उसके बारे में ही कहूंगा। पार्लियामैंट में भी इसके बारे में बहुत कहा सुनी होने के बाद गवर्नमैंट ने कहा है कि इस पर पूरी डिबेट होगी। पिछले दिनों दिल्ली में लाल किले पर हजारों फार्मर्ज ने इकटठे होकर एक रैली की थी, बडा भयानक वातावरण पैदा हो गया था और वह भय वि ोश तौर पर किसानों में इस डंकल प्रस्ताव को लेकर हुआ था। अगर इस डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत हो जाएंगे जैसे किसानों के नेताओं का कहना है कि इससे भयंकर बात भारत के

किसानों के लिए और कोई नहीं होगी। यह प्रस्ताव भारत की कृशि और भारत के किसानों को तबाह करके, बर्बाद करके रख देगा। इसलिए इस प्रस्ताव पर इस सदन में गंभीरता से बहस होनी चाहिये। क्योंकि हमारे सामने ट्रेजरी बैंचिज पर कांग्रेस की सरकार है और सैंटर में भी कांग्रेस सरकार है। मुख्य मंत्री जी अपने नेताओं पर दबाव डाल सकते हैं कि क्या इन हालात में डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत करने चाहिएं या नहीं करने चाहिएं ? हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि इससे हमें क्या नुकसान होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, डंकल जे0ए0प्री0टो0 आर्गेनाईजे ान के प्रधान हैं, यह उन्हीं का प्रस्ताव हैं इन्होंने जो डंकल प्रस्ताव रखा है, वह यह है कि चाहे ड्रग्ज का मामला हो, चाहे दवाईयों का मामला हो, चाहे इनसैक्टीसाईडज या पैस्टीसाईडज का मामला हों, चाहे बढिया बीज की बात हो यह चीजें डंकल प्रस्ताव के तहत लेनी होंगी। अगर आज सारी दुनिया में बढिया बीज या बढिया दवाईयां उपलबध करवानी हों तो उसके लिए यू0एस0ए0 में रिसर्च होता है या किसी विकास ील दे ा में रिसर्च करना पडता है या जो दे ा रिसर्च में एडवांसड हैं, उसको रिसर्च पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पडता है। इस विशय में वि ोशज्ञों की काल है जो बढिया बीज हमारे पास उपलब्ध है, या दुनिया में उपलब्ध है, अगर यों ही आबादी बढती गई और बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया गया तो आज जितनी हमारी पैदावार है, उससे आने वाली पापुले ान का गुजर बसर नहीं होगा। डंकल जी यह कहते हैं कि हमें और रिसर्च करना पडेगा लेकिन उस पर बहुत पैसा

खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, डिवैल्पिंग कंट्रीज यह अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय फर्ज करो टमाटर का बीज 100 रूपए किलो मिलता है और उसको वे और बेहतरीन करना चाहते हैं। अगर वे बेहतरीन कर पाते हैं तो भाायद इसका रेट एक हजार रूपए या अढाई हजार रूपए किलो उपलब्ध हो।। इसकी बनिस्बत जो किसानों की पैदावार होगी, उसका उचित भाव उसे मिलेगा नहीं, इसलिए किसानों को घाटा हो जाएगा, दूसरे मनोपली हो जाएगी और यू0एस0ए0 से हमारे रिले ान खराब हो जाएंगे। वह बीज हमें उपलब्ध होता है या नहीं, इस बात की कोई गारन्टी नहीं है। इसके अलावा, किसानों का यह भी कहना है कि अगर वह बीज हमें उपलबध हो भी गया तो भी हम अकेले ही उसकी भारी कीमत को क्यों बर्दा त करें ? जब हम सारे दे ा के लिए अनाज पैदा करते हैं तो हम क्यों उसकी कीमत भरैंगे ? उसकी कीमत या तो कंज्यूमर को भरनी चाहिये या फिर गवर्नमैंट आफ इण्डिया, कोई स्पै ाल टैक्स लगाये तथा उसको उसी भाक्ल में सबसिडाईज करके किसान को बीज सप्लाई करे ताकि किसान की कमर न टूटे और किसान बढिया बीज लेकर सारे दे ा का पेट भर सके। स्पीकर सर, मुझे खद ाा यही है कि जो बीज आ रहा है, वह हमारी बढती हुई पापुले ान को ससटेन नहीं कर सकेगा, इसलिए मुख्य मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा चौ0 वीरेन्द्र सिंह डंकल प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेन मुददा है, उस पर तो इन्होंने कहा ही नहीं है। जिस बात का विरोध हो रहा है, वह इन्होंने नहीं कही। विरोध इस बात का हो रहा है कि डंकल प्रस्ताव में इंटरने ानल मार्किट के मुताबिक, दवाईयों की पैटेन्ट और बीज की पैटेन्ट को सर्टिफाई करके फ्री ट्रेड किया जाए। यह बात इन्होंने नहीं कही। किसान यह कहता है और दवाई बेचने वाले भी कहते हैं कि इंटरने ानल स्टैंडर्ड का जो पैटर्न है, वह हाई है और इंडियन स्टैंडर्ड उस स्तर का नहीं है। दूसरी बात किसानों के लिए यह आएगी कि यदि पैटेन्ट उस पैटेन्ट वहां का रहेगा और स्टेंडर्ड भी वहीं का रहेगा तो हमारे जो किसान हैं, उनको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी और हमार जो खादय पदार्थ या प्रोसैस बाहर जाता है, उसकी इंटरने ानल मार्किट में कमी हो जाएगी और हमारे किसानों पर इसका एडवर्स इफैक्ट होगा। इसलिए यह पैंटेंट, जो इंटरने ानल लैवल पर लागू होगा, इसको अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, यह मेन मुददा है। यदि यह अनिवार्य कर दिया जाएगा तो हिन्दुस्तान में डंकल प्रस्ताव पर दिक्कत होगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः चलो कोई बात नहीं, आपने ही यह ऐड कर दिया।

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब, साथ ही यह भी बतायें कि जो लोन मिलता है तो क्या यू0एस0ए0 का उससे कनैक ान होता है ?

चौधरी जगदी ा नेहराः जी नहीं, यू0एस0ए0 का इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च यू0एस0ए0 कर रहा है, खर्चा भी वही कर रहा है तथा पैटेंट का स्टैंडर्ड भी वही कर रहा है। जैसे मान लीजिये, टमाटर का बीज सौ रूपये किलो है और अगर उस पर पैटेंट यू0एस0ए0 का है तो वह कहता है कि टमाटर का बीच पांच सौ रूपये किलो है, चूंकि पैटैंट उसका है इसलिए वह इसकी कीमत पांच सौ रूपये किलो लेगा। दिक्कत यही है कि अगर फ्री ट्रेड के साथ डंकल प्रस्ताव मंजूर हो गया तो परे ाानी आएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपकी भांका ठीक थी कि क्या इसमें यू0एस0ए0 का ताल्लुक है ? डंकल जो है, वह जी0ए0टी0आई0 का प्रधान है। स्पीकर साहब, आपका कहना ठीक था कि कहीं यू0एस0ए0, यू0एन0ओ0 की आड लेकर, इस रैजोल्यू ान को यू0एन0ए0 में पास न करवा ले। यह तो आप भी जानते हैं कि यू0एन0ओ0 में भी आज यू0एस0ए0 का दबदबा है। आज वह एक अकेली भाक्ति रूस के टूटने के बाद रह गयी है। आज जैसा अमरीका चाहे, वैसा यू0एन0ओ0 में कर सकता है, किसी दे ा की उसको रोकने की मजाल नहीं है, इसलिए यू0एन0ओ0 भी इससे मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ठीक किया कि वह सब कह दिया जो मुझे पता नहीं था। मुझमें जितना

ज्ञान है उसीके हिसाब से मैं कहता हूं। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है जितना इनके पास है। लेकिन आज सभी इस बारे में चिन्ता कर रहे हैं और इस विशय पर पार्लियामैंट में भी डिबेट होनी है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया इस पर मोहर लगाने से पहले सभी मुख्य मंत्रियों से विचार विम र्ा जरूर करेगी। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि इसको पूरी गंभीरता से स्टडी करवाएं और देखें कि इसके मैरिटस और डीमैरिटस क्या हैं ? इस बारे यदि आप कोई लिटरेचर उपलब्ध करवा सकते हैं तो वह सारे सदन के मैम्बरों को भी भिजवा दें ताकि हम लोग पढकर सुझाव दे सकें क्योंकि यह पूरे दे ा का मामला है। आने वाली पीढी का मामला है हमारे भविश्य से जुडा हुआ है। केवल कृशि में ही नहीं, बल्कि मेडीसन में, जैसे ऐस्प्रो की गोली जो आज 10 पैसे में मिलती है, वह 25 रूपये में मिले तो कौन एफोर्ड करेगा, कैसे हम गुजारा कर सकेंगे ? मैं डिमांड नं0 17 पर चर्चा करते हुए आपसे गुजारि ा करूंगा कि डंकल प्रस्ताव को यहां न आने दिया जाए। ताकि जब कोई दस्तख्त करने का या न करने का समय आए, तो हरियाणा गवर्नमैंट की तरफ से हरियाणा का पक्ष पूरी मजबूती से, किसानों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, ग्रेने मार्केट नारनौंद में 1988 से पत्थर लगा हुआ है, वहां चार दिवारी भी मुकम्मल हो चुकी है, दुकानें नीलाम होनी थी लेकिन उनकी नीलामी रूकी पडी है। वह जगह बहुत इम्पौरटेन्ट बन चुकी हैं। उस गांव के चारों तरफ लगभग

50–60 गांवों का निकास होता है। यह ग्रेन मार्किट बहुत बडी सक्सैसफुल मार्किट होगी। उस पर 40–50 लाख रूपया तो खर्च हो चुका है और 40–50 लाख का काम बाकी रहता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रेन मार्किट का काम टोप प्रायोरिटी पर पूरा किया जाए। इसी के साथ 6–7 सडकें मंजूर हुई हैं और 7–8 साल से उन पर कोई काम भुरू नहीं किया गया। लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारि ा करूंगा कि इन सडकों को प्राथमिकता पर बनवाएं ऐसी जो रोडज हैं जिनसे लोगों का सफर कम होता है, उनको लिंक करवायें ताकि गांव में पहुंचने के लिए 20 किलो मीटर के सफर की बचत हो सके। मैं उन 5–6 सडकों के नाम भी बता देता हूं मंत्री जी लिखने की कृपा करें :–

मोड़ा से डाटा,

डाटा से भियाना खेड़ा,

पेटवाड़ से बास तथा

पेटवाड़ से बदाला।

एक सडक जिस पर रोडियां पडी हैं जिसकी लैंथ एक कि0मी0 है वह है बखलाना से उपाड। ये 4–5 सडकें बहुत जरूरी हैं और इनसे 20–20 कि0मी0 का सफर बचेगा और लोगों को बहुत सुविधा होगी। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री राम रतन (हसनपुर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं तो आज बहुत दिन के बाद बोला हूं।

12.00 बजे।

मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर 8 पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर साहक, मेरे हल्के के आठ दस गांव हैं जहां की सडकें बहुत ही खराब हैं और उनका बनाना बहुत जरूरी है। वास्तव में वहां सडक बनी ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान अपने इलाके की सडकों की तरफ दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, एक सडक प्रहलादपुर से घोडी तक, एक जटोली से अतर चटटा और तीसर मीरपुर करारी से घासेडा। ये सडकें बहुत ही जरूरी हैं (**इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**) उपाध्यक्ष महोदय, 6 मार्च 1992 करो मुख्य मंत्री महोदय हसनपुर गए थे और वहां एक बहुत बडी जनसभा हुई थी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हसनपुर की जो सडकें टूटी फूटी हैं और जो नहीं बनी हैं, उनको बनाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हसनपुर के पास जमुना पर ड्रमों का पुल बना है। मुख्य मंत्री जी घोशणा करके आए थे कि यह पुल बरसात से पहले बन जाएगा। एक बरसात तो निकल गई और अब दूसरी बरसात आने वाली है। मेरी प्रार्थना है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया है और ट्रेजरी बैंचिज के माननीय सदस्यों ने बजट की सराहना की है। अध्यक्ष महोदय, बजट से पहले इस सदन में गवर्नर महोदय के अभिभाशण पर चर्चा हुई। विरोधी पक्ष के भाईयों ने गवर्नर महोदय के अभिभाशण पर जो कुछ कहा, वही बातें इनहोंने इस बजट पर कहीं हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप अपने मैम्बर्ज को डिसिप्लिन में रखें। ऐसी कोई बात नहीं सुनी जायेगी।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जो बात आप कर रहे हैं वही होगी। ये लोग आपसे रिकवैस्ट कर रहे हैं कि आज हमारी पार्टी का मैम्बर नहीं बोला।

श्री दरियाओं सिंह रजोराः आप हाउस को एक्सटैंड कर दें। मैं तो बोला ही नहीं हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आज टाईम ऐक्सटैंड नहीं होगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने वर्श 1993–94 के बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट नीरस है और दि ााहीन है। इन सदस्यों ने कहा कि यह बजट दि ााहीन है इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है और हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए भी

कुछ नहीं किया गया है। स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने अपने मन के गुबार निकालने के लिए और अपने हल्के के लोगों को खु ा करने के लिए कुछ बातें यहां पर रखी हैं। (ाोर एवं व्यवधान) । स्पीकर साहब, मैं एक बात आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। मैं फाइनैंस के मामले में कोई बहंत बडा अर्थ ाास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। इन नब्बे के हाउस में आप पहले भी आते रहे हैं और अब की बारे भी बन कर आए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आप हाउस का समय बढा दीजिए और हरेक मैम्बर को पांच पांच मिनट दे दीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठ जाएं।

श्री सतबीर सिंह कादियानः हमारा कहना तो यह है कि आप थोडा सा टाईम बढा दें जिससे कि सभी मैम्बर्ज अपनी समस्याएं सदन में रख सकें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं इसलिए आप लोग बैठ जाएं। अब किसी और को टाईम नहीं मिलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि यह हाउस 90 का है। इस हाउस में दो मुख्यमंत्री इस समय ऐसे हैं जो दो तीन बार पहले भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं और कई

ऐसे सदस्य भी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कई ऐसे सदस्य भी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह जो उठकर गए हैं वे भी काफी सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी जो चले गए हैं वे भी बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। स्पीकर साहब मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस 90 के हाउस में मुख्य मंत्री तो दूसरी बार और तीसर बार बनकर आए हैं और कई विधायक जो पहले मंत्री थी वे भी दूसरी और तीसरी बार बन कर आए हैं लेकिन हरियाणा में जो फाइनैंस मिनिस्टर रहा है, वह दूसरी बार बनकर नहीं आया। चौधरी बंसी लाल जब मुख्य मंत्री थी तो इन्हौंने बहुत सारे महकमे सम्भाले हुए थे और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल के पास भी काफी विभाग रहे हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह बहुत सीनियर मंत्री रहे और वकील भी रहे यह सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर चले। उन्होंने महकमें छांटे पावर एण्ड इरीगे ान, होम डिपार्टमैंट और ऐजुके ान लेकिन फाइनैंस के वे बिल्कुल नजदीक नहीं लगे। इसी तरह से चौधरी सम्पत सिंह जी ने जितने इम्पोर्टैंट विभाग थे, होम, पावर एण्ड इरीगे ान, वे संभाले। जिन विभागों पर बजट का 50 प्रति ात खर्चा होता है वे विभाग चौधरी सम्पत सिंह जी ने अपने पास रखे लेकिन फाइनैंस का विभाग किसी ने भी अपने पास नहीं रखा क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसको संभालने में बहुत बडी कठिनाई आती है और जिससे हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने हर बार नाराजगी जाहिर करनी ही है। मैं तो यह सब कुछ प्रैक्टीकल बता रहा हूं कि फाईनैंस मिनिस्टर से तो सभी नाराज

रहते हैं। सारे अधिकारी नाराज, सभी कर्मचारी नाराज, और जनता भी नाराज फिर जनता को ये लोग खु ा करने के लिये कहते हैं कि फलां फलां स्कीमज हमने मनवा ली हैं। अब की बार तो हमने यह स्कीमें मनवा ली हैं लेकिन फाइनैंस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं मानते। काम बन जाए तो साथियों को खु ा कर लो और अगर न बने तो लोगों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की कोई नाराजगी हो तो वह फाइनैंस मिनिस्टर के जिम्मे लगा दो। ये तो मेरे इन विरोधी पक्ष के भाईयों का कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्होंने यहां पर बोलते हुए जीभ की बात कही। इनको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो जीभ है, यह बहुत बडी कीमती चीज है। इसी जीभ के कारण ही सम्पत सिंह जी ने एक बात हाउस में कही थी कि मेरी गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। लेकिन आपको पता ही है कि वह गर्दन झुकी भी ओर उन्होंने हाउस के अंदर माफी भी मांगी। (ाोर) यह फैक्टस की बात है सबके सामने की बात है। मैं फैक्टस पर आधारित बातें हाउस में कह रहा हूं, किसी पर ऐलीगे ान नहीं लगा रहा। न ही मैं किसी के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरफीरैंस ही करना चाहता हूं। मैं तो फैक्टस बता रहा था। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मांगे राम जी, यह तो चिढाने वाली बातें हैं जिनका सबको पता है कि उसको बार बार कुरेदने की कोि ा ा न की जाए। (ाोर)

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फाइनैंस विभाग ऐसा विभाग है जिसके पास स्टेट के सारे रिसोर्सिज होते हैं और उन्हीं रिसोर्सिज के अनुसार वह हर विभाग को फण्डज ऐलोकेट करता है और उन फण्डज को विभाग अपने लैवल पर अलग अलग खर्चा करता है। फाइनैंस विभाग के पास कोई जादू की छडी नहीं है कि चाहे कोई डिपार्टमैंट जितना पैसा मांगे, वह उतना ही उसे दे दे। कोई भी मांग जो एम0एल0एज0 उठाएं वह फाइनैंस डिपार्टमैंट दे दे और बजट में प्रावधान कर दे, यह बात फाइनैंस विभाग के बस की नहीं है। जो कुछ ये लोग बोलते हैं कहते हैं मैं उनकी हर बात नोट करता हूं और उनका सही सही उत्तर भी देता हूं। मैं इनको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि स्टेट के अपने निि चत रिसोर्सिज होते हं लेकिन मेरे जितने भी बैठने वाले माननीय व आदरणीय तजुर्बेकार सदस्य हैं, उनमें से किसी ने भी यहां पर यह नहीं कहा कि स्टेट के अंदर विकास के कार्यों के लिये फलां फलां रिसोर्सिज पैदा किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मांग की कि बिजली के रेट न बढाए जाएं, सेल्ज टैक्स और मार्किट फीस नहीं लगनी चाहिए, वह खत्म कर दी जाए। माननीय सदस्यों ने कहा कि भाराब के ठेके नहीं बिकने चाहिए, दवाईयों मुफ्त मिलनी चाहिए। और ि ाक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए तथा खाद तथा बीज पर भारी सबसिडी रखनी चाहिए। हर गांव में स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं कोई स्कूल बगैर टीचर के नहीं रहन चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी होनी चाहिएं, सडकें बढिया

बढिया होनी चाहिए। हस्पताल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। पीने का पानी इतना चाहिए कि भााम तक टूटियां चलती रहें और कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। किसान के खेत में जितना पानी चाहिए उतना देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जितने काम लोगौं के हित के हैं, इनके लिए साधन जुटाने पडेंगे। सभी कामों के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी पडेगी। अगर सरकार सभी माननीय सदस्यों की एक भी मांग पूरी मान लें जैसे ि ाक्षा के संबंध में कोई मांग है, तो अगर उस पर वर्श 1993–94 का पूरा बजट भी खर्च कर दे तो भी वह मांग सारी स्टेट में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए माननीय सदस्यों को सोच समझ कर ही सुझाव देने चाहिए। सभी साथी सरकार की नुक्ताचीनी अकेले चौधरी भजन लाल की ही नहीं है और न ही फाइनैंस मिनिस्टर की है। लोगों ने यहां पर 90 प्रतिनिधि चुन कर भेजे हैं, इन सबकी बराबर जिम्मेदारी है। बजट पर तो लोगौं की भलाई के बारे में बोला जाता है, इसीलिए लोगों ने आपको यहां पर चुन कर भेजा है। आप अपने हल्के के लोगों की और प्रदे ा के लोगौं की मांग के लिए सुझाव देते लेकिन इन्होंने कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। फायनैंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने कोई सुझाव नहीं दिए। यहां पर बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। खुद फाईनैंस मिनिस्टर ने सुझाव दिया था और अपोजी ान के मैंबरों

ने उसकी ताइद की थी कि कैबिनेट के साईज को कम कर लो तो खजाने पर अपने आप भार कम पडेगा। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कोई खास वजह हो या किसी ने कोई खास बात कह दी हो तब तो माननीय सदस्यों को बीच में उठ कर प्वायंट आफ आर्डर करना चाहिए लेकिन अब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही ये तो अपना जवाब दे रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके माननीय सदस्य बीच में टोकने की कृपा न करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमनें जो 1993–94 का बजट पे ा किया है इस बारे में मेरे साथी कादयान साहब ने कहा कि इस बजट का प्लान बहुत कम है इन्होंने इस बारे में कोई आंकडे तो बताए नहीं, वैसे ही नुक्ताचीनी के नाते कह दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्लान है उसके अनुसार हमने पिछले साल 820 करोड रूपए खर्च किए जबकि इस साल यानि 1993–94 में हम 910 करोड रूपए खर्च करेंगे यानि 90 करोड रूपए ज्यादा खर्च करेंगे। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों के समय में प्लान 529 करोड रूपए के लगभग था। हमने 15 परसैंट के करीब बढौतरी की है। हमारे पास प्रदे ा के विकास के लिए जितने रिसोर्सिज थे उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा करके खर्च किए हैं। पिछले साल 1991–92 के बजट में 87.34 करोड रूपए का घाटा था। हमने उस घाटे को अपने खर्च कम करके रिडयूस किया है और यह बजट ईयर 7.16 करोड रूपऐ के घाटे में समाप्त हुआ।

पिछले साल 119.84 करोए का घाटा था लेकिन हमने अपने खर्चे कम करके पिछले बजट ईयर को 79.87 करोड रूपऐ के घाटे के साथ समाप्त किया और जो 40 करोड रूपया हमने बचाया, वह हरियाणा प्रदे ा के लोगों के विकास के लिए खर्च किया। इस तरह हमने अपने खर्चे में कमी की है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय हमारे माननीय सदस्य सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि बिजली में लाईन लौसिज 39 परसैंट हो गए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके राज में वर्श 1990–91 में बिजली में 26.4 परसैंट लाइन लौसिज थे, 1991–92 में 24.2 परसैंट थे, 1992–93 में 23.2 परसैंट रह गए और 1993–94 में 22.5 परसैंट रह जाएंगे। आपने कैसे कह दिया कि 39 परसैंट बिजली में लाइन लौसिज हैं ? अध्यक्ष महोदय बिजली तैयार करने का जो खर्चा है वह 1 रूपया 25 पैसे या 30 पैसे प्रति यूनिट है। इन्होंने एक बात यह कही कि किसानों के साथ बहुत भारी अन्याय किया गया है। सरकार ने बिजली का रेट 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया, सारे दे ा में बिजली का इतना रेट कहीं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सारे दे ा में हरियाणा प्रदे ा एक ऐसा प्रदे ा है जो किसानों को एग्रीकल्चर सैक्टर में 59.2 परसैंट यानि 60 परसैंट बिजली दे रहा है जिस पर 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से नुक्सान होने की वजह से हर साल बिजली बोर्ड को 300 करोड रूपए का नुकसान हो जाता है। दूसरे किसी भी प्रदे ा में एग्रीकल्चर सैक्टर में इतनी बिजली नहीं दी जा रही। मेरे विरोधी पक्ष के भाई इस बात को ले कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि आप बिजली के

बिल न भरो। अगर किसान बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो आज बिजली की जो मांग बढ रही है, यह अगले पांच साल में भी पूरी नहीं होगी। आज बिजली जिस रेट के हिसाब से मिल रही है वह दो रूपए यूनिट के हिसाब से भी नहीं मिल सकेगी और बिजली के नए प्रोजेक्ट नहीं लगेंगें। मैं यह कहूंगा कि इन भाईयें को चाहिए कि वे प्रदे ा के लोगौं को, किसानों को सही स्थिति की जानकारी दें, गुमराह न करें। मैं फिर कहूंगा कि यदि ये प्रदे ा के सच्चे हितैशी हैं तो इनको सही बात कहनी चाहिए। अरग ये गलत जानकारी दैंगे तो प्रदे ा का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए इनको लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कादियान जी ने उद्योग कुंज के बारे में कहा है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कीम पर चार जिलों में काम हो रहा है। सोनीपत, रोहतक, गुडगांव में तो साईट ले ली गई जबकि हिसार जिले में साईट की तला ा की जा रही है। ज्योंही जमीन मिल जायेगी हिसार में भी इस स्कीम पर काम भाुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कादियान जी ने यह कही कि पानीपत की एच0एफ0सी0 में किसी अधिकारी/कर्मचारी ने 3 लाख रूपए का गबन किया है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने यह गबन किया था उनको सस्पैंड कर दिया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कानून के अनुसार उनके खिलाफ पूरी

कार्यवाही की जाएगी, चाहे कोई कितना ही बडा अधिकारी क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय एक बात चन्द्रावती जी ने जे0पी0 गुप्ता जी के बारे में कही। इस बात की इंकवायरी हुई है। उन दिनों गुन्ता जी छुटटी पर थे पूरी इंकवायरी हुई। आपको भी पता है कि जो इंकवायरी में दोशी पाया जाता है उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाती है और उसको परमोट नहीं किया जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी दोशी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कादियान साहब ने यह कही कि पानीपत के थर्मल प्लांट में प्रदूशण बहुत अधिक है। यह बात सही है इसे मैं मानता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदूशण को कम करने के लिए काफी पग सरकार उठा रही है। इस पर भारी खर्च होने की संभावना है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है, जल्दी ही इसको कोई न कोई समाधान ढूंढ लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह इन्होंने यह कहा कि स्टेट वाटर एंड एयर पोल्यू ान बोर्ड के जो पहले चेयरमैन मि0 आर0ए0 गोयल थे, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एस0पी0 ग्रोवर को चेयरमैन लगा दिया गया। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सैंट्रल एन्वायरमैंट बोर्ड की सलाह पर ही हरियाणा स्टेट पोल्यू ान बोर्ड

को खत्म किया गया है और दोबारा गठन किया गया है। चेयरमैन मि0 आर0 ए0 गोंचल ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट की है। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया है। अब श्री आर0ए0गोयल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पे ान याचिका डाली है। यह मामला अब सब जूडिस है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता।

श्री सतबीर सिंह कादियानः पहले बोर्ड को तोड दिया, फिर बना दिया और आर0ए0 गोयल से कम क्वालिफिके ान के आदमी को चेयरमैंन लगा दिया गया।

श्री अध्यक्षः गवर्नमैंट की अपनी कम्पीटैंसी है, जिसको वह चाहे, चेयरमैन लगाये।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने पानी के बारे में चर्चा की और यह भी कहा कि एस0वाई0एल0 पानी की नहर की तरफ सरकार का वि ोश ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं हाउस में एक बात कहना चाहता हूं ..... (विघ्न)

एस0वाई0एल0 पानी के बारे में हर विधायक और सरकार बहुत ही चिन्तित हैं कोई भी व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, हर विधायक यह मांग करता है कि जिन माईनरों के फाउन्डे ान स्टोन रखे गये हैं उनका काम जल्दी पूरा किया जाए और यह कहा गया है कि माईनरज के लिए पैसा

नहीं रखा गया हैं अध्यक्ष महोदय, अगर पानी नहीं आया तो नई माईनरज बना कर क्या करेंगे ? माईनरज बन जाएं और उनमें पानी न आए तो उनको कोई फायदा नहीं है। टेल पर पानी पहुंचाने के लिए एक करोड रूपया खर्च किया गया। हरियाणा के 75–80 प्रति ात लोग यह मानते हैं कि टेल पर पानी पहुंच रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में नहीं आएगा, तब तक माईनरज पर ज्यादा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। एस0वाई0एल0 के बारे में विरोधी पक्ष के भाई चाहे कुछ भी कहें, सरदार बेअन्त सिंह की पंजाब की जनता को खु ा करने के लिए चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन हरियाणा की यह वर्तमान सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा के किसानों को देगी, जिससे किसान के खेत को पानी मिलेगा, हरियाणा की एक एक एकड जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय वित्त मंत्री जी फरमा रहे हैं कि यह सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा को देगी। बजट में इसके लिए इन्होंने कोई खास पैसे का प्रावधान नहीं रखा है। यह एस0वाई0एल0 का पानी कब और कैसे लाएंगे, यह भी जरा बताने की कृपा करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने अभी 18 महीने का अर्सा ही हुआ है। 4 साल इनकी सरकार

रही जिसमें भार्मा जी खुद मंत्री रहे और बाद में मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए थे। (विघ्न) अमर सिंह जी भी कह रहे थे कि चौधरी बंसी लाल जी ला सके और नही यह लोग ला सके। हालांकि हर कोई इस पानी को हरियाणा में लाना चाहता है। लेकिन केवल चाहने से ही तो कोई काम नहीं हो जाता है। एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में लाना केवल हमारे हथ की ही बात नहीं है, आज हम ही चिन्तित नहीं हैं केन्द्रीय सरकार भी चिन्ि'तत है। पंजाब में उग्रवाद हावी होने के कारण जब भी इस नहर को बनाने का काम भ्ाुय होता था तो उग्रवादियों ने कभी इंजीनियरों को मार दिया, कभी वर्करज को मार दिया कभी लेबर को मार दिया और भारत सरकार जो भी फैसला करती थी वह सिरे नहीं चढ पाता था। लेकिन अब दे ा के प्रधानमंत्री, इरीगे ान मंत्री और हरियाणा सरकार इस बारे में कई मीटिंगे कर चुके हैं। इस काम में कुछ टाईम तो लगैगा ही एक दो दिन में यह काम होने वाला नहीं है। मुझे पूरा वि वास है कि हरियाणा की जनता ने जिस वि वास के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, यह सरकार अपने कार्यकाल में ही हरियाणा की जनता को एस0वाई0एल0 का पानी उपलब्ध करवाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अभी वे माईनरज के लिए ज्यादा पैसे की तरफ ध्यान न दें। जहां तक एस0वाई0एल0 के लिए 20 करोड रूपये का ताल्लुक है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही इस बारे में कोई फैसला हो जाएगा, नहर खुदनी भ्ाुरू हो जाएगी हम

सप्लीमैंटरी बजट मंजूर करवा सकते हैं और इस सप्लीमैंटरी डिमांड के लिए कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। 20 करोड रूपया हमने इसलिए रखा है कि कभी भी एमरजैंसी में एस0वाई0एल0 का काम भुरू करना पड सकता है तो पैसा कम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, हमैं चाहे कितना ही पैसा क्यों न रखना पडे हम एस0वाई0एल0 का काम करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, यह पैसा तो सैंटर से आता है ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है गुप्ता जी अभी जिक्र कर रहे थे कि माईनर्ज तब खुदवायेंगे जब एस0वाई0एल0 का पानी आएगा गुडगांव में एस0वाई0एल0 का पानी नहीं पडेगा तो क्या वहों पर अटवाल माईनर को खुदवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्षः यह क्वे चन आवर नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अभी रामबिलास भार्मा जी कह रहे थे कि बजट में एस0वाई0एल0 के लिए पैसा नहीं रखा है। हम यह कहते हैं कि जब भी एस0वाई0एल0 का काम भुरू होगा तो उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी और न ही हम आने देंगे।।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ये इररेलवेन्ट बात कर रहे हैं कि पैसा हम लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह पैसा तो पंजाब गवर्नमैंट ने खर्च करना है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा इन्होंने लगाना है। इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाना है लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि बेअन्त सिंह कुछ भी कहें। .....

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी यह बात तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही क्लीयर कर दी है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, नहर को बनाना तो पंजाब सरकार के हाथ में है। साथ ही पंजाब सरकार कह रही है कि वे पानी के ई ाुज को रीओपन करके फिर काम भाुरू करेंगे। तो मुख्य मंत्री जी इस बारे मं हाउस को ऐ योर करें कि इसका निर्माण बी0आर0ओ0 करेगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात हाउस मं बार बार आई है और केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में चितिंत है। मैं हाऊस को ऐ योर करता हूं कि बी0आर0ओ0 ही इस नहर को बनाएगी। जहां तक पैसे का सवाल है इस बारे में विरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि पैसा भारत सरकार से आता है। तो इन्हें याद होगा जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा स्टेट के मुख्य मंत्री थी तो उस वक्त दो करोड रूपया पंजाब सरकार को दिया गया था। लेकिन जब बाद में हम आए तो हमने यह फैसला किया कि भारत सरकार ही एस0वाई0एल0 के लिए पैसा देगी और इसको सैंट्रल

गवर्नमैंट ही कम्पलीट करवाएगी। यह फैसला हमारा है इनका नहीं है और इसको भारत सरकार ही पूरा करेगी।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि आपने कितना पैसा रखा हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 495 लग चुका है और यह पहले का है।

श्री अमर सिंहः यह तो चौ0 बंसी लाल जी के टाईम का है।

श्री अध्यक्षः लेकिन बाद में 150 करोड रूपए और भी दिए थे।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस नहर को हम कम्पलीट करवाने की जल्दी से जल्दी कोि ा ा करेंगे।

श्री अध्यक्षः हरियाणा का जो पैसा इस पर खर्च हुआ था, उस समय श्री राजीव गांधी ने भी यह कहा था कि यह पैसा हरियाणा को वापिस दे दिया जाएगा। इसलिए आप यह बता दें कि यह पैसा कौन सी सरकार को मिला है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह पैसा नहीं आया है। गलत बात कहने में कोई फायदा नहीं है लेकिन उसके बाद टोटल पैसा भारत सरकार ने इस पर लगाया है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ऐजुके ान की तरफ ध्यान दिलाया है कि इस सरकार ने स्कूलों की अपग्रेडिंग में ज्यादती की है और बहुत से स्कूली टीचर्ज के बगैर चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पहली बार छः साल के बाद स्कूलों में कालेजों में टीचर्ज और लैक्चर्ज की जो पोस्टें खाली थीं हमने तकरीबन उन सभी को भरने का पूरा प्रयास किया है। सभी पोस्टों की सैंक ान दे दी है और इनके लिए अब इन्टरव्यू भी हो गये हैं। भाायद अब कोई स्कूल ही ऐसा बचा होगा जहां टीचर्ज की कमी होगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कुछ भी इस बारे में नहीं सोचा था। हमने 181 स्कूलों की अपग्रेडिंग की बात एक साल मैं करने के बारे में कहा है। इनके समय में तो 20 या 25 स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुए थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ि ाक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो लोगों को खु ा करने के लिए 350 स्कूलों को अपग्रेड करने की लिस्ट ही बनायी थी किन्तु स्कूल अपग्रेड नहीं किये थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ि ाक्षा के मामले में तहेदिल से यह चाहती है कि हमारे हरियाणा का कोई भी बच्चा अनपढ न रहे। इसलिए हमारी सरकार ने ि ाक्षा के लिए हर सुविधा जुटाने की कोि ा ा की है। गरीब और बैकवर्ड क्लासिज के बच्चे जो फीस नहीं सकते, वर्दी नहीं ले सकते, किताबें नहीं ले सकते हैं, ऐसे बच्चों की हमारी सरकार ने फीस मुफ्त कर दी है और वर्दी का इंतजाम किया है, किताबों का इंतजाम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमारी

सरकार ने लडकियों की ि ाक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने पहले ही लडकियों की ि ाक्षा को बी0ए0 तक मुफ्त कर दिया था लेकिन अब सरकार ने महसूस किया है कि लडकियों को टैक्नीकल ऐजुके ान भी फ्री दी जाये। हमने लडकियों के लिए टैक्नीकल ऐजुके ान को अब फ्री कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमने यह भी फैसला किया है कि पहले जो लोग अपने बच्चों को पढाया नहीं करते थे लेकिन अब साक्षरता अभियान के तहत हमने यह फैसला किया है कि हरियाणा का कोई भी नागरिक अनपढ नहीं रहेगा। जो अंगूठा टेक लोग पहले हुआ करते थे अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। अब हरियाणा का हर व्यक्ति पढा हुआ होगा ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई व्यक्ति धोखा न कर सके। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने ला एंड आर्डर की बात भी की। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ला एण्ड आर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पिछली सरकार के समय में लोग बहुत ही दुखी थे, यह हम ही नहीं कहते हैं बल्कि सारे हरियाणे के लोग कहते हैं। अगर हम यह बात कहें कि उस समय विकास के कार्य नहीं हुए थे तो भाायद लोग बर्दा त भी कर लें लेकिन इनके समय में तो लोगों का जीना ही दूभर हो गया था, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिये गये थे, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाता था। इस तरह इनके समय में लोग बहुत दुखी हो गये थे और कहते थे कि उनसे कौन सा ऐसा जुल्म हो गया है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। वे कहते थे कि

जल्दी से जल्दी उन्हें इस सरकार से छुटकारा मिलना चाहिए। इस तरह से उन सभी गरीब लोगों की आवाजें भगवान के घर गयीं और लगभग साढे तीन साल के बाद ही प्रदे ा में इलैक ान हुआ और उस इलैक ान में हरियाणा की जनता ने इनके खिलाफ फतवा दिया। स्पीकर साहब, यह फतवा ला एंड आर्डर खराब होने की वजह से प्रदे ा की जनता ने दिया था हो सकता था कोई छोटी मोटी घटना घट जाती और वह इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रदे ा में बडे बडे डैकैत पैदा कर दिये थे, बडे बडे चारे पैदा कर दिये थे, बडे बडे ग्रीन बिग्रेड के सिपाही पैदा कर दिये थे। अब सरकार इन सभी को तला ा कर रही है। आज कोई नहीं कह सकता कि जमीनों पर कब्जे होते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला जाता है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी सौदा खरीद कर ताऊ के खाते में डाले।

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री जी बजट परी न बोलकर पर्सनल ऐलीगे ान लगा रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जे का जिक्र कर रहे हैं। एक भी कब्जा ऐसा नहीं जो इन्होंने छुडाया हो। मौजूदा सरकार ने पलवल में म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर कब्जा किया है। होडल में जमीन पर कब्जा किया है। इस तरह के जो ऐलीगे ान लगाए गए हैं इन्हें एक्सपंज किया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रयास से हरियाणा मैं आज लोग अमन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे

हैं। कोई आदमी किसी के सहारे तो नहीं बैठ सकता। श्री कृश्ण लाल ने दो तीन घटनाओं का जिक्र किया। इसी तरह से करनाल जिले में सालवना गांव का भी जिक्र किया और साथ में मेरे हल्के में भााहपुर एक गांव है उसमें हरिजन बाल्मिकी के कत्ल का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों केसों में पूरी कार्यवही हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाल्मिकी का कत्ल हुआ लेकिन किसने किया, कैसे किया इसका इन्होंनें जिक्र करने की कोि ा ा नहीं की। कत्ल करने वाले लोगों के बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह कत्ल किया है वे इन्हीं के आदमी थे। वे यह समझते थे कि अब भी देवी लाल जी जैसा ही राज है वे इन्हीं के आदमी थे। वे यह समझते थे कि अब भी देवी लाल जी जैसा ही राह है किसी को कोई परवाह नहीं। अब वो पकडे गए हैं, एक मुलजिम को तो हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किय है, दो फरार होकर दूसरी स्टेट में भाग गए। उनमें से एक भी मुलजिम आज बाकी नहीं है सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं।

चौधरी भजन लालः भार्मा जी ने कुछ बातें और भी कहीं हैं। भार्मा जी बहुत बढिया आदमी हैं। कल मेरी समझ में नहीं आया कि इनके एक हाथ में पटटी बंधी थी और आज दूसरे हाथ में है। पता नहीं कौन सा हाथ ठीक है, कौन सा गलत है।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, ये मेरे जख्मों का मजाक न करैं। यह गुमानी, लाला लाजपत राय पर लाठियां

बरसा कर ब्रिटि ार्स ने भी की थी। मैंने कभी अपने जख्मों का कंपनसे ान नहीं मांगा और न ही मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। भगवान करे, आपको इस तरह का मौका न आए। वैसे तो आप इस तरह की बात की नौबत हीं नहीं आने देंगे, भगवान आप पर राजी रहें, ये लाठियां हमको ही मुबारक हों। न मैंने आपसे सर्टिफिकेट मांगा न आपकी कांग्रेस से सर्टिफिकेट मांगा। (ाोर एवं व्यवधान) यह जो बात है उसकी आपने कारगुजारी की, उसकी हमने कभी सदन में चर्चा नहीं की। स्पीकर सर, मैंने इनसे प्रमाण नहीं मांगा था। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी, आप मजाक की बात को सीरियस न लें।

प्रो0 राम बिलास भार्माः यह मजाक की बात नहीं है, क्या इसको भी आप मजाक कहते हैं ? मजाक के लिए और विशय बहुत हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप बैठिए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, दिल्ली की जो वारदात हुई है, इस पर हिन्दुस्तान के लोगों का सर झुका है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी, आप इतने सीरियस क्यों हो गए ? (ाोर) मैंने तो थोडा सा माहौल ठीक करने के लिए कहा था। आप लाठियों की बात कहते हैं, लाठियां खाकर,

गोलियां खाकर, फांसी के फंदे को जिन लोगों ने चूमा था, उन्होंने दे ा को आजाद कराने के लिए चूमा था, दे ा को बरबाद करने के लिए नहीं चूमा था। वे दे ा के बरबाद नहीं करना चाहते थे। मैंने इस नजरिए से बात कही थी कि आप टैंस न हों। अगर आपको मेरी बात महसूस हुई है तो मैं वापिस ले लेता हूं, लेकिन थोडी बहुत बात तो हंसी की भी कहनी चाहिए।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: आप मार का मजाब उडा लें, आप हमारे ऊपर लाठियों का मजाब उडा लें और आप हमारे जख्मों का मजाक उठा लें, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

चौधरी भजन लाल: ये जख्म दे ा को बचाने के लिए नहीं हुए हैं, ये तो दे ा को तोडने के लिए हुए हैं। सरदार भगत सिंह ने जो लाठियां खाईं थीं, या लाला लाजपत राय ने लाठिया खाईं थीं, वे दे ा की आजादी के लिए खाईं थी। स्पीकर साहब, अमर सिंह ने हरिजनों का बैकलोग पूरा करने के लिए कहा है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी बैकलोग पूरा करेंगे। एक बात इन्होंने प्लाटों के बारे में कही। हम इस बारे में दुबारा सर्वे करवा रहे हैं और जिनको प्लाट नहीं मिले हैं, उनको प्लाट देंगे। स्पीकर साहब, पास बुक की बात इन्होंने कही। एग्रीकल्चर पालिसी पर दिल्ली में मीटिंग हुई थी। श्री हरपाल सिंह ने वहां पर बहुत जोरदार भाब्दों में इस बात की वकालत की। स्पीकर साहब, जब मैं सैंटर में ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने यह बात चलाई थी और उस समय एक कमेटी बनाई

गई थी उस कमेटी के तीन मैम्बर थे। एक मैं था, एक प्राईम मिनिस्टर और तीसरे फाईनैंस मिनिस्टर थे। फसल बीमा योजना के बारे में भी प्राईम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जिक्र किया और कहा कि चौधरी भजनलाल के समय यह स्कीम चालू की गई थी। हमने इसके लिए जिले को यूनिट नहीं माना, ब्लौक को भी यूनिट नहीं माना। मैंने कहा था कि गांव यूनिट होना चाहिए। पासबुक का भी वहां पर जिक्र आया था। उस पास बुक में जमीनों का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें जमीनों के खरीदने बेचने, कर्जा लेने और कर्जा उतारने आदि का जिक्र होगा ताकि लोगों को बार बार पटवार के दरवाजे पर न जाना पड़े।

स्पीकर साहब, चौधरी पीर चन्द ने रतिया का जिक्र किया। इनको रतिया की बहुत चिन्ता है। ठीक है यइ इनका हल्का है, लेकिन रतिया मेरी ससुराल भी है। इन्होंने फतेहाबाद के एस0एच0ओ0 का जिक्र किया। पीरचन्द जी, हमने उसको बदल दिया है। रतिया के एस0एच0ओ0 के बारे में कहा कि वह करप्ट है। हम जांच करवा लेंगे, इस बात में कोई सच्चाई मिलेगी तो उसको लाइन हाजिर कर देंगे, उसके खिलाफ ऐक ान लेंगे और कार्यवाही करेंगे।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक क्वै चन था कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाट्र पर एस0पी0 और डी0सी0 हरिजन नहीं लगाए हुए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः हरिजन मैम्बर हैं, इनको तो दूसरों की बात करनी चाहिए। आप लोग केवल हरिजनों की वोट से बनकर नहीं आते, सब लोगों को साथ लेकर चलना पडेगा।

साथी लहरी सिंहः हरियाणा के अन्दर एक भी हरिजन एस0पी0 नहीं है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, गरीब आदमी के साथ और हरिजन के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। आपको जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, यह कहना चाहिए कि अच्छे आदमी लगने चाहिए। सारे हरिजन भी अच्छे नहीं हैं और नौन हरिजन भी सब बुरे नहीं हैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले बजट पर चर्चा हुई और हमारे सारे विरोधी पक्ष और ट्रेजरी बैंचिज के भाईयों ने उस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट पर चर्चा भाुरू हुई थी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने खुल कर तथा विस्तार से अपने अपने विचार रखे। बहुत सारी बातों के संबंध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए उनकी तसल्ली करवाने की पूरी पूरी कोि ा ा की है। जब से हमारी कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनी है, उसके बनने के बाद हरियाणा के हर व्यक्ति को राहत महसूस होने लगी है। हर व्यक्ति आजादी और सुख का सांस लेने लगा है। चाहे ला एण्ड आर्डर का मसला हो,

चाहे प्रदे ा के विकास का मसला हो, चाहे टैक्स का मसला हो, वैसे हमने कोई नया टैक्स तो लगाया ही नहीं बल्कि घटाया ही है।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। 30 अक्तूबर को उसका कत्ल हुआ था और 20 दिसंबर 1992 को पूरे प्रान्त की तरफ से बाल्मिकी समुदाय की तरफ से जींद के अंदर मांगे राम गुप्ता जी की कोठी के सामने प्रद र्न किया था। अगर उस टाईम कातिल गिरफ्तार होते तो बाल्मीकी समुदाय की तरफ से धरना क्यों दिया जाता ?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, श्री कृश्ण लाल ने फिर वही बात कह दी। वे मुलजिम उसी रात को फरार हो गए, रात का वाकया था। (ाोर)

श्री कृश्ण लालः हां, अध्यक्ष महोदय, वे इनके लोग थे उनको पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इन्होंनें उन लोगों के नाम नहीं बताए। मैं नाम भी बता देता हूं। राहमेर, फूल सिंह एव चतरू ये तीनों जाट क्म्यूनिटी से संबंध रखते हैं और मैं पूरे एफीडेविट के साथ सदन में कह रहा हूं जो बाल्मीकी मरा है वह मेरा इलैक ानों में सपोर्टर और वोटर रहा जबकि यह तीनों मुलजिम हमे ाा मेरे खिलाफ रहे, कभी मेरे हक में नहीं रहे और मैंने अपने हल्के में कभी किसी बदमा ा चोर को पनाह नहीं दी

और आज मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे हल्के में किसी की कब्जा करने की हिम्मत नहीं है न किसी बहू बेटी की इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत पड सकती है। मैं वो गुप्ता नहीं हूं जिसका हरियाणा भवन में पीट कर इस्तीफा ले लिया था।

सम्पत सिंह जी, मैं वह गुप्ता नहीं हूं जिससे नोट भी लेते हैं और वोट भी लेते हैं और फिर पीटकर उससे इस्तीफा ले लेते हैं। मैं वह गुप्ता हूं जिसकी रगों मैं भोरे पंजाब लाला लाजपतराय का खून दौडता है, जिसके भारीर के अंदर महात्मा गांधी का खून है। मैं आपके दबाव से चलने वाला नहीं हूं। मैने तो हमे ाा आपका मुकाबला किया है और आगे भी जैसा चाहूं कर सकता हूं। स्पीकर साहब, अमर सिंह ने हरिजनों की चर्चा की। उन्होंने चौपालों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार ने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों का वि ोश ध्यान रखा है। सर्विसिज के अंदर इनकी सरकार ने जो बैकलोग छोड दिया था उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। यह बैकलोग चाहे पुलिस में था, चाहे किसी नौकरियों में था, हमने उस बैकलोग को पूरा किया है। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लडकों को नौकरी दी जा रही हैं। इनके राज में जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया जा रहा है। चौपालों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चौपालों के लिए पचास हजार रूपया कर दिया है जो पहले पच्चीस हजार होता था और मुरम्मत के लिए हमारी सरकार ने पच्चीस हजार रूपए किया

है। हरियाणा सरकार सभी चौपालों को, चाहे वह धानकों की है चाहे चमारों की है और चाहे वह खटीकों की चौपाल है सबको पूरा करेगी। कोई चौपाल अधूरी नहीं रहेगी सबको पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गांवों में सेनीटे ान के लिए एक नई स्कीम के द्वारा एक लाख भौचालय हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। मल उठाने की जो पुरानी प्रथा थी, उसको जल्दी ही खत्म किया जा रहा है। बाल्मीकी जो पहले मैला उठाते थे, अब भविश्य में मैला नहीं उठाएंगे।

श्री राम कुमार कटवालः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने कहा है कि जींद में किसी प्लाट पर कब्जा नहीं है और न ही वहां पर कोई गुण्डागर्दी है। मैंने इस हाउस में वित्त मंत्री के बारे में एक फाईल रखी थी जिसमें प्लाटों के कब्जे का जिक्र था। प्लाटों का जो घपला था उसमें इस बात का जिक्र है। दूसरी बात यह है कि जींद के एस0पी0 श्री सिन्हा ने एक छापा मारा था जिसमें इनका लडका भी भाामिल था और उस लडको को थाने में बिठाया गया था। ये आज कैसे कहते हैं कि जींद में कोई गुण्डागर्दी नहीं है। आप इनके लडके के बारे में मिस्टर सिन्हा से पूछ सकते हैं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हो गई जैसे आपने भी यह मिसाल सुनी होगी "तेली ए तेली तेरे सिर पर कोल्हू।" तेली ने कहा कि तेल तो मिला नहीं तो जाट ने कहा कि बोझ से तो मरेगा। इसी तरह से इन्होंने अपने मुंह से बात निकाल दी। स्पीकर साहब, मेरा हाउस के अंदर चैलेंज है कि कोई

भी ऐलीगै न चरित्रहीनता का या बेईमानी का लगा दें, अगर वह साबित हो जाए तो हमें इस कुर्सी से कोई प्यार नहीं है, हम इस कुर्सी को छोड कर चले जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि हरियाणा के किसान को खेत में पूरा पानी मिले, लोगों को पूरा पीने का पानी मिले, हरियाणा के अस्पतालों में दवाईयां अच्छी मिलें, लोगों के लिए अच्छे साधन जुटाए जाएं जिससे कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे और जनता के हित के जितने काम हैं उनको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार पूरा प्रयास कर रही हे। हमारी पूरी कोि ा ा है कि आय के साधन बढाएं जाएं जिनसे जनता की भलाई के जितने काम हैं उनको पूरा किया जा सके। स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता ने हरियाणा सरकार और कांग्रेस पार्टी में जो वि वास व्यक्त किया है, उसको यह सरकार पूरा करेगी और अगले चुनाव में इन लोगों की जमानत जब्त होगी। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में सिविल वार की तरह सिचुऐ ान हो जाएगी, लोग सडकों पर आ जाएंगे और इनकी नींद हराम कर देंगे। इसलिए ऐसे हालत इनको नहीं करने चाहिएं। अगर ऐसा हो गया तो इनका दफतरों से निकलना बन्द हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए इनको लोगौं की नब्ज को समझना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बंसी लाल (तो ाम): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी मानते हैं और सरकार भी मानती है कि स्टेट में सूखे की स्थिति है। उससे निपटने के लिए सुझाव चाहिएं ताकि फौरी तौर

पर सरकार जो सहायता कर सकती है, करे। सहायता यह कर सकती है कि भाखडा नहर का कुछ पानी, कुरूक्षेत्र जिले की तरफ, करनाल और पानीपत तथा नरवाना सब डिवीजन को छोडकर जीन्द, सोनीपत, रोहतक और हिसार जिले का हांसी सब डिवीजन और फरीदाबाद, गुडगांव, भिवानी, रिवाडी, महेन्द्रगढ के इलाकों को, जहां सूखे की बहुत भयंकर स्थिति है, तथा जहां पर चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है और मवेि ायों के मरने के पूरे आसार हैं, पहले प ाु बाढ से मारे गये थे और अब भी सूखे के कारण मरेंगे, के लिए फौरी तौर से कुछ पानी भेजा जाना चाहिए ताकि लोग चारा पैदा कर सकें और रबी की फसल ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज तूडा का भाव 150 रूपये है। कल भी मैंने इसका भाव 150 रूपये बताया था लेकिन जब कल भााम को एक आदमी मुझसे मिला तो उसने कहा कि आपने तूडा का भाव 150 रूपये क्यों कह दिया ? इसका भाव तो 165 रूपये है। उपाध्यक्ष महोदय, एक रूपये 65 पैसे किलो के हिसाब से प ाुओं को चारा खिलाना किसानों के लिए गरीब आदमी के लिए कोई आसान बात नहीं है। सरकार को फौरी तौर से सबसिडी देकर चारे का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके अलावा, दूसरी चीज यह है कि किसानों को जो कर्जा दिया हुआ है और जिसकी वसूली तेजी से चल रही है, उस वसूली को रोका जाये। जब किसान की अगली फसल यानी रबी की फसल अच्छी हो जाए तो यह वसूली आप कर सकते हैं। अगर रबी की फसल भी अच्छी नह हो तो उससे अगली खरीफ की फसल अच्छी होने पर इसकी वसूली कर सकते हैं, उससे पहले

इसकी वसूली न की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा किसानों को अच्छी बिजली देनी चाहिए, चाहे इसके लिए इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बन्द क्यों ने करना पडे। स्टेट में आज भी कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं, भाायद मुख्य मंत्रजी को भी इसका पता होगा और आपको भी इसका अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए उन सब इंडस्ट्रीज की बिजली बन्द करके एग्रीकल्चर सैक्टर को देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा लीडर आफ अपोजी ान ने बताया कि चौधरी अतर सिंह के पास ऐफेडैविट भी है लेनिक वह इस समय सदन में नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई ऐफेडेविट ऐसे हैं जिनमें बिजली के महकमें के लोग बगैर रि वत लिए बिजली के कनैक ान नहीं देते। हमारे जिले में आज बिजली की हालत यह है कि अगर कोई आदमी बिजली के कनैक ान के लिए आता है, तो उससे कहा जाता है कि पहले कमि नर के पिता के पास जाकर पैसा दो, तब जाकर उसको बिजली का कनैक ान दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। इसके अलावा पीने के पानी की सब जगह दिक्कत है, कमी है। मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था कि सूखे के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए नारनौल, गुडगांव, भिवानी और फरीदाबाद आदि सब जगहों पर सरकार को पीने का पानी भेजना चाहिए तथा बाढ की वजह से जितने वाटर वर्क्स खराब हो गये हैं, जितने बैड खराब हो गये हैं, जो पानी के फिल्टर बैड ठीक नहीं हैं उनको सरकार को ठीक करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि जो लौंग

टर्म पोलिसी है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो स्टेट में वाटर लेवल नीचे चला गया उसको ठीक किया जाये। मेरा ख्याल है कि 50–60 फुट से 100 फुट तक वाटर टेबल नीचे चला गया है, उसे ठीक करने का एक रास्ता यह है, सरकार को फौरी तौर से यह काम करना चाहिए कि वेस्टर्न यमुना कैनाल की कैपेसिटी बढाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, माईनर्ज, सब माईनर्ज की कैपेसिटी बढाएं और उनकी मुरम्मत कराएं। मानसून के दिनों मं करीब ढाई पौने तीन महीने यमुना नदी में खास पानी चलता है, वह पानी उन इलाकों में दिया जाये। इससे लोगों की फसल ठीक होगी, वाटर टेबल भी ऊपर आएगा और पानी भी री चार्ज होगा। इसके साथ साथ एक काम जो सरकार अगले साल तक पूरा कर सकती है, वह यह है कि दादुपुर नलवी नहर चलाई जाए इससे खरीब की फसल भी अच्छी होगी। आने वाली रबी की फसल का त करवा देने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसके साथ साथ भााहबाद मारकंडा, टांगडी दरिया है, इनको भी टेम करना चाहिए। ि ावालिक पहाडियों से आने वाले नदी नालों को टेम करना चाहिए। जिस समय मैं मुख्य मंत्री था उस समय राजस्थान में बरकतुल्ला खां साहब मुख्यमंत्री थे। हरीके से पानी पाकिस्तान को जाता है। मेरे और राजस्थान के मुख्य मंत्री के और दोनों स्टेटों के सिंचाई मंत्रियों के दस्तखत हो गए थे कि पाकिस्तान को जो पानी जाता है वह हम हरीके के स्थान पर राजस्थान कैनाल में डाल देंगे। राजस्थान कैनाल से वह पानी हम सिरसा जिले में ले लें और सिरसा जिले में, जितने दिन वह

पानी सरप्लस हो, उसे वैस्टर्न यमुना कैनाल के इलाकों को दे दें इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सिरसा जिले की ओटू झील के ऊपर दस या पन्द्रह करोड रूपये खर्च करके, रेलवे लाइन से ऊपर ले जाकर, पूरी तरह से डीसिल्ट किया जाए तो उसमें से काफी इलाकों को पानी दिया जा सकता है। अब उसमें सिल्ट भर गई है, बाढ आई है, जिससे सिरसा जिले का बडा नुकसान हुआ है, भाहर को नुक्सान हुआ है, रतिया के इलाकों को नुक्सान हुआ है। मेरा सुझाव है कि ओटू झील के बारे में पूरा प्रोग्राम बनाकर 10–20 करोड रूपया खर्च करके उन इलाकों को सैराब किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि मैंने हरिद्वार से आगे गंगा नदी के पास भीमगौडा से करनाल तक, की नहर बनाने के लिए प्रौजेक्ट बनाकर भेजा था। इससे यह होगा कि जो पानी करनाल से नीचे जाता है, वह अम्बाला में, कुरूक्षेत्र के इलाकों में, यमुनानगर के इलाकों में इस्तेमाल हो सकता है, गंगा का पानी उसके नीचे के इलाकों में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से एस0वाई0एल0 के बारे में मुख्य मंत्री जी का स्टैंड कुछ और है, पंजाब के मुख्य मंत्री जी कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि एस0वाई0एल0 बनने का सवाल ही नहीं है। लीडर आफ दि अपोजी ान अभी इसके बारे में कह रहे थे। मुझे नहीं मालूम है कि सही स्थिति क्या है ? लेकिन किसी ने किसी तरह से कोि ा ा करके एस0वाई0एल0 बनवाई जानी चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें 2 मिलियन एकड फुट पानी हमारा है। स्पीकर सर, पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ है, मुख्य मंत्री जी पता कर लें कि

यह बात कहां तक सही है ? यू0पी0 में एक भारदा रिवर है, उस रिवर से भारत सरकार एक प्रोजैक्ट बना रही है, जिसका पानी भारदा नदी से लेकर पानीपत और सोनीपत के बीच यमुना नहीं में डालेंगे। दिल्ली को पीने का पानी देने के लिये मथुरा और आगरा जिलों की आबपा ी के लिये वह प्रोजैक्ट बनेगा। मैं हरियाणा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप भारत सरकार को चिटठी लिखें कि अगर ऐसा कोई प्रोजैक्अ हो तो उस प्रोजैक्ट में सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांवा जिलों को भी भामिल कर लिया जाये। उस प्रोजैक्ट के खर्चे में जो भी हिस्सा हमारा आता हो, वह हम दे दें या फिर उसको सैंट्रल प्रोजैक्ट बनवा दें। उससे क्या होगा, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांवा जिलों का काम चल जायेगा। इसके अलावा, वैस्टर्न यमुना कैनाल के पूरे सिस्टम की कैपेसिटी हम जितनी जल्दी बढा लेंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। इससे पानी रिचार्ज होगा और वाटर टेबल भी ऊपर आयेगा। इससे लोगों को फायदा होगा। जवाहर लाल नेहरू कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बी0एन0 चक्रवर्ती कैनाल, जुई लिफट स्कीम तथा झज्जर लिफट स्कीम्ज ऐसी हैं जिनकी बहुत सी डिस्ट्रिब्यूटरीज, माईनर्ज और सब माईनर्ज बननी अभी बाकी हैं। वे हमे ाा सूखाग्रस्त इलाके होते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में जहां डिस्ट्रिब्यूटरीज माईनर्ज और सब माईनर्ज बननी बाकी हैं, उनको बनायें ताकि लोगों को पानी का फायदा हो। मैं समझता हूं बारि ा के दिनों में अकेली वैस्टर्न यमुना से ही पूरी स्टेट को दो अढाई महीने तक आराम से पानी

दिया जा सकता है। इसलिए जो लिफट इरीगे ान स्कीम्ज हैं, इन सब के लिये डिस्ट्रिब्यूटरीज बनायें। जवाहर लाल नेहरू कैनाल इरीगे ान की सबसे बडी लिफट स्कीम है। इसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल और बी0एन0 चक्रवर्ती कैनाल है। जुई लिफट स्कीम सबसे छोटी लिफट स्कीम है। इनके अलावा एक बात का मैंने मुख्य मंत्री जी से पहले भी अनुरोध किया था और अब भी करूंगा। कम से कम आजकल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम तो ठीक नहीं चल रहा है। मैं चेयरमैन को पर्सनली नहीं जानता नाम से तो जानता हूं लेकिन मैं उसको भाक्ल से नहीं जानता। मैं अभी इस बारे में आपसे यह अनुरोध करूंगा कि किसी फाइनैंि ायल कमि नर को उस बोर्ड का चेयरमैन बना दें ताकि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम ठीक तरीके से चलने लगे। इस ढंग से चलने से क्या फायदा है ? इस बार तो ऐसे हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, राईस सूटस भी लोगों को अब तक नहीं दिये गये हैं। धान कटन पर आ गया है लेकिन स्अेट में लोगौं को राईस सूटस अभी तक नहीं दिये गये। इसलिये मेरा इस बारे में एक सुझाव है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इरीगे ान के जो प्रोजैक्अस मैंने बताये हैं जैसे भीमगोडा, करनाल, हरीके से पानी लाना, एस0वाई0एल0 वाला, भाारदा रिवर वाला और ओटू झील वाले प्रोजैक्अस की तरफ सरकार ध्यान दे और सरकार को चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कोि ा ा करके प्रोजैक्ट बनाये। प ाुओं के लिये जितनी जल्दी चारे का प्रबन्ध कर देंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर चारे का प्रबन्ध नहीं होगा तो मवे ाी मरने भाुरू हो

जायेंगे। मवे ाी धन एक बहुत बडा धन होता है। इन भाब्दों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): यह जो इ ा आज हमारे सामने है मैंने इसके बारे में काल अटैं ान मो ान भी दियाथा। इस साल एक विचित्र बात यह हुई है कि बाढ भी आ गई और सूखा भी आया। वैसे तो यह सूखा सारे हरियाणा मे ंहै लेकिन हमारी तरफ ज्यादा है। जहां चावल बोया है, वहां पर भी सूखा पडा हुआ है। कहत की वजह से पानी की कमी है। मेरा लोहारू हलका थोडा सा तो भिवानी जिलें में है और कुछ महेन्द्रगढ जिले मे ंभी पडता है। मैं अभी 50–60 गांवों में जाकर आयी हूं। इन गांवों में एक ही बात सब जगह सामने आती है कि बिजली और पानी की कमी है। जब मैं बोल रही थी तो मैंने डिगवा पावर हाउस के ट्रांसफारमर के जलने की बात कही थी। मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि पहले जो ट्रांसफारमर जल गया था, वह अब लग गया है लेकिन अब दूसरा एक और जल गया है। इस तरह बात तो वहीं की वहीं खडी रह गयी है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह हाउस की सैंस है कि हाउस का समय आधे घंटे के लिये और बढा दिया जाये ?

आवाजें: जी हां। बढा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः बैठक का समय आधा घण्टा बढाया जाता है।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, टाईम तो आधा घंटा ही बढायें लेकिन करीब आधा घंटे बोलने के लिये मुझे भी चाहिये। बाकी जितनी माननीय सदस्यों ने बातें कहीं हैं वह लगभग सारी बातें पहले आ चुकी हैं। उसका रैपीटी ान ही है। चन्द्रावती जी के 5 मिनट बोलने के बाद मेहरबानी करके आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है!

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात तो कहनी पडैगी कि आज सूखे की हालत प्रदे ा के अंदर है। प ाुओं के लिए चारा नहीं है उनके लिए चारा चाहिए। लोगों की मदद के लिए राहत कार्य फौरन भाुरू किए जाने चाहिएं। जोहडों की खुदाई होनी चाहिए, नहरों की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नहरों की मुरम्मत होनी चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंग्ज जो लोगों ने बनाई थीं, उनकी हालत खस्ता है, उनको ठीक किया जाना चाहिए। आज खेतीहर मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि दांती डालने के लिए घास भी नहीं रही। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के बिना कुछ नहीं होगा। बिजली की

हालत यह है कि पंजाब में और हमारे पास दो दो पावर हाउस थे। हमारे पास एक थर्मल प्लांट पानीपत में है और दूसरा फरीदाबाद में है। हमारी हालत यह है कि फरीदाबाद में जो आधा थर्मल प्लांट है, उसको भी हम पूरा नहीं कर पाए। पंजाब में दो पूरे हो गए और दो और बन रहे हैं। भाायद वे भी पूरे हो गए हैं और एक और बन रहा है। इस तरह से वे पांच पर आ गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली की कंजम्प ान बढ रही है और टयूबवैल्ज की गिनती भी बढी है लेकिन बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं बढा है। यह नहीं होना चाहिए। यमुनानगर में प्रधान मंत्री जी ने रिमोट कंट्रोल से पावर हाउस की नींव तो रख दी लेकिन सचमुच में पावर हाउस बनेगा या नहीं यह ई वर जानता है। उपाध्यक्ष महोदय नकीपुर जो लोहारू में है के लिए पावर हाउस की प्रोपोजल है। बाढडी जो सतनाली के पास है के लिए भी पावर हाउस की प्रोपोजल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सतनाल का पावर हाउस 33 के0वी0 से 132 के0वी0 का किया जाए। यह बैल्ट मीठे पानी का है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस एरिया में पावर हाउसिज बनाए जाएं ताकि बिजली की समस्या हल हो सके। आज बिजली की बहुत बुरी हालते हैं आज अगर बिजली की चोरी रूक जाए तो किसानों को ज्यादा बिजली मिल सकती है। अगर करप ान रूक जाए तो सारे काम ठीक ढंग से हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। आज करप ान और इनऐफी ैंसी हैंड इन ग्लोव है। पैसा लिए वगैर आज फाइल ही नहीं निकलती। अफसर लोग इसी इंतजार मे ंरहते हैं कि पैसा

आए तो फाइल निकाली जाए। गुडगांव में अंग्रेजों के वक्त नौ बांध थे आज उनका बुरा हाल है। कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया। भी ावाल पिचापा और बादल गांवों में बांध होते थे वे सब डैमेज हो गए हैं। हमारे यहां बाढडा में बांध होते थे लेकिन वे सब खत्म हो गए। मेरा कहना यह है कि उन अफसरों के खिलाफ ऐक ान लिया जाना चाहिए जिन्होनें इन्हें खुर्दबुर्द होने दिया। उन अफसरों को सजा देनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बोरिंग टयूबवैल्ज की बुरी हालत है। पता नहीं सरकार ने कितने बौर्ड बना दिए। एम0आई0टी0सी0 बना दिया और कहीं कोई और बोर्ड बना दिया। फाइल पर बोर्ड बना हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। (ाोर एवं व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री हैं आपको दिल्ली के दौरे कम रखने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके किनारे पर और जमुना के किनारे पर सब जगह पेड लगाने चाहिए। अगर पेड लगेंगे तो पानी कम सूखेगा। जहां झील है उनके चारों तरफ पेड लगने चाहिए ताकि पानी कम सूखे। चकबन्दी के समय मुरब्बा बन्दी हुई थी, लेकिन जोहडों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। गांव में जोहड छोडने चाहिए। वहां से प ाु पानी पीते हैं लेकिन जोहड न होने के कारण अब सारा प्रै ार नहरों पर आ गया है। अगर मेरे इन सुझावों पर सरकार अमल करे तो जनता की बहुत भलाई हो सकती है।

प्रो0 राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने यह तो स्पीकार किया है कि हरियाणा के अन्दर बिजली की कमी और अकाल से गम्भीर स्थिति पैदा हुई है। 40 करोड रूपया इसके लिये एलोकेट किया है। आज एक सवाल के जवाब में यह बताया गया कि 464747 हैक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई है और पूरे चार पांच जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल सुजै ान्ज देना चाहता हूं कि इस सारी स्थिति से निपटने के लिये बिजली के जनरे ान का बढाया जाना बहुत ही जरूरी है। हम जिन इलाकों से आते हैं वहां सिंचाई की समस्या नहीं है, वहां पीने के पानी की भी समस्या है। जब तक पावर जनरे ान नहीं बढेगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। मुख्य मंत्री महोदय ने खुद माना है कि स्थिति चिन्ताजनक हैं पावर जनरे ान बढ नहीं रही और मांग ज्यादा बढ रही है। आज से तीन चार साल पहले लोगों की जितनी डिमांड थी, अब उससे ज्यादा हो गई है। प ाुओं के लिए चारा काटने वाला टोका है, वह भी आज बिजली से चलता है और भाानी बनाई जाती है। आटा बिजली पीसती है। लिफ्ट इरीगे ान सिस्टम जो हमारे तीन चार जिलों में है वह तब चलते हैं जब पूरी बिजली दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के पडौसी राज्यों में कहीं पर भी बिजली की कोई कट नहीं है। कल इस सदन में इस मसले पर चर्चा हुई थी कि किसी भी जगह पर बिजली की कटौती नहीं

है। हिमाचल में बिजली की भाार्टेज नहीं है। हिमाचल, सरप्लस इलैक्ट्रीसिटी स्टेट है और समय सयम पर प्र ाासन ने ईमानदार तरीके से पावर जनरे ान को बढाने के प्रयास किये हैं और बिजली का प्राइवेटाईजे ान किया है। जिस तरह राजस्थान में भैरां सिंह सरकार ने किया उसी तरह से हिमाचल में श्री भाान्ता कुमार की सरकार ने प्रयास किये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हरियाणा के अन्दर भी पावर जनरे ान को बढाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अभी हरियाणा के अन्दर श्री राजपाल जी को इलैकट्रीसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ठीक किया, वे टैक्नीकल आदमी हैं, उनको इसकी ज्यादा नालिज है। परन्तु अब तक जितने पावर मिनिस्टर बने हैं, उनमें सबसे बढिया चौधरी वीरेन्द्र सिंह रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी की सरकार में वे मिनिस्टर रहे हैं और लोगों ने यह माना है कि हरियाणा के अन्दर बिजली अगर सबसे ज्यादा मिली है तोउसी समय में मिली है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को यह विभाग दे दिया जाए ताकि इस समय हरियाणा जो बिजली के संकट से गुजर रहा है, वह दूर हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें आज किसान के हितों की पूरी चिन्ता है। और उनके बारे में जो कुछ हम ईमानदारी से महसूस करते हैं वहीं सुझाव हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं ए0सी0 चौधरी जी का विरोध किसी और कारण से नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनको अभी पावर जनरे ान

का अनुभव नहीं है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने यह विभाग बहुत देर तक, बहुत वर्शों तक देखा है और उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी करके दिखायीं हैं। यदि मुख्य मंत्री जी की पावर जनरे ान बढाने की सचमुच में कुछ इच्छा है, तो जो जो सुझाव यहां सदन में आए हैं उनकी तरफ अव य ध्यान देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो इलाका है वह टेल का इलाका है। वहां पर नारनौल, महेन्द्रगढ, नागंल सिरोई में 36 एम0वी0, 66 एम0वी0 ट्रांसफामर्ज था उस को उठाकर सरकार ने डबवाली भेज दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हमारे इलाके में बिजली पहले ही कम आ रही है और इसके बावजूद भी सरकार ने ऐसा कर दिया। नांगल सिरोई का जो पावर स्टे ान है, वहां लोग आते जाते हैं और कर्मचारी बेचारे डर के मारे आते जाते नहीं हैं। (ाोर)

श्री मनी राम केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, किस बात का प्वायंट आफ आर्डर ये उठा रहे हैं ? मुख्य मंत्री महोदय मेरी सारी बातों का जवाब देंगे। डबवाली मैंने कह दिया और इनको चिढ लग गई। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मनीराम जी ही सारी जानकारी रखते हैं और हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। (ाोर)

श्री मनीराम केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, पंडित जी अभी कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर एक जगह से उठा कर दूसरी जगह दे दिया। जहां से उठाया है वह भी जगह हरियाणा में है और जहां ले जाया गया है, वह भी हरियाणा में है। यहां तो ऐसा भी देखने में आया था कि जिन लोगों पर हरियाणा के लोगों ने वि वास किया था, उनहोंने हरियाणा के ट्रांसफार्मर यू0पी0 में भेज दिये थे। अब वह बात तो नहीं हो रही।

श्री पीर चन्द : ऐसी बात नहीं है कि मैं डबवाली के बारे में बुरा सोचता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि यह इलाका टेल पर है। इन सालों में जो नए लगे हैं, उनकी संख्या अलग है। तो जो भाखडा की लाइन यहां से जाती है, वह दादरी तक जाते जाते क्रिपल डाउन हो जाती है, इसलिए वहां के पावर हाउसिज को दिल्ली के साथ जोडा जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्होंने यहां पर बोलते हुए जीभ की बात कही। इनको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो जीभ है, यह बहुत बडी कीमती चीज है। इसी जीभ के कारण ही सम्पत सिंह जी ने एक बात हाउस में कही थी कि मेरी गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। लेकिन आपको पता ही है कि वह गर्दन झुकी भी ओर उन्होंने हाउस के अंदर माफी भी मांगी। (ाोर) यह फैक्टस की बात है सबके सामने की बात है। मैं फैक्टस पर आधारित बातें हाउस में कह रहा हूं, किसी पर ऐलीगे ान नहीं लगा रहा। न ही मैं किसी के बीच में किसी भी प्रकार का

इंटरफीरैंस ही करना चाहता हूं। मैं तो फैक्टस बता रहा था। (ाोर) कोई भी मांग जो एम0एल0एज0 उठाएं वह फाइनैंस डिपार्टमैंट दे दे और बजट में प्रावधान कर दे, यह बात फाइनैंस विभाग के बस की नहीं है। जो कुछ ये लोग बोलते हैं कहते हैं मैं उनकी हर बात नोट करता हूं और उनका सही सही उत्तर भी देता हूं। मैं इनको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि स्टेट के अपने नि ि चत रिसोर्सिज होते हं लेकिन मेरे जितने भी बैठने वाले माननीय व आदरणीय तजुर्बेकार सदस्य हैं, उनमें से किसी ने भी यहां पर यह नहीं कहा कि स्टेट के अंदर विकास के कार्यों के लिये फलां फलां रिसोर्सिज पैदा किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मांग की कि बिजली के रेट न बढाए जाएं, सेल्ज टैक्स और मार्किट फीस नहीं लगनी चाहिए, वह खत्म कर दी जाए। माननीय सदस्यों ने कहा कि भाराब के ठेके नहीं बिकने चाहिए, दवाईयों मुफ्त मिलनी चाहिए। और ि ाक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए तथा खाद तथा बीज पर भारी सबसिडी रखनी चाहिए। हर गांव में स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं कोई स्कूल बगैर टीचर के नहीं रहन चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी होनी चाहिएं, सडकें बढिया बढिया होनी चाहिए। हस्पताल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। काफी चर्चा है हालांकि रोहतक यूनिवर्सिटी और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का काम सदार प्रताप सिंह ने भाुरू किया था लेकिन उन्होंने थोडा ही काम किया था और चौधरी बंसी लाल ने उस काम को पूरा किया।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Deputy Speaker: Since there are other members who want to speak on the demands for grants and the Finance Minister is also yet to reply, is it the sense of the House that the time of the House be extended by one hour ?

Voices : Yes.

Mr. Deputy Speaker: The time of the House is extended by one Hour.

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री पीर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सरकार चाहे हमसे रूपया मंजूर करा ले, चाहे तो इससे भी ज्यादा रूपया मंजूर करा ले हमें कोई परे ाानी नहीं है। लेकि जैसा मैंने बताया कि रूपया इस ढंग से खर्च किया जाए, जिससे सारे हरियाणा का नाम ऊंचा हो और डिवैल्पमैंट का काम ज्यादा हो।

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला (नरवाना): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान। मुख्यमंत्री ने मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ट्रांसपोर्ट विभाग के प्र न के उत्तर में कहा कि ओम प्रका ा चौटाला ने मिनी बसें खरीदीं थीं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट विभाग को काफी घाटा हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बसें पब्लिक वेलफेयर के लिये हार्ड पावर्ड कमेटी

की सहमति से खरीदने का आदे ा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, छोटे रूट पर जो बसें चलती हैं नि चत रूप से उनमें घाटा होता है क्योंकि उनमें स्टुडैंटस भी बैठ कर जाते हैं और पास होल्डर्स की संख्या भी उनमें ज्यादा होती है। लम्बे रूट की बसें तो घाटे को कवर कर जाती हैं। लेकिन आज जो प्र न था, वह इस बात को लेकर के था कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। आज मुख्य मंत्री ने इस बात को लेकर हाउस में कहा कि इस मामले में विजीलैंस की इंक्वायरी हुई है और उस विजीलैंस की रिपोर्ट में यह आया है कि इसके लिये ओम प्रका ा चौटाला दोशी हैं। मुझे बहुत खु ाी होगी कि यह हरियाणा सरकार जो पिछले 26 महीनों से चल रही है, अगर इस सरकार में दम हो तो उस विजीलैंस की जांच के आधार पर ओम प्रका ा चौटाला पर मुकदमा दर्ज करे। हमने कई सरकारें देखीं हैं। (थम्पिंग) बडे बडे दिग्गज और आनैस्ट मुख्य मंत्री, उस चेयर पर बैठे हुए लोगों से, हम टकराये हैं। (थम्पिंग) इस प्रकार की चरित्र हनन की राजनीति वे करते हैं, जिन्होंने भ्रश्टाचार को आधार मान कर, ट्रांसपोर्ट विभाग को प्राईवेट सैक्टर में कंवर्ट करने के लिये, मन चाहे लोगों से पैसे लेकर, उनको बासों के परमिट देने के आधार पर, सारे ट्रांसपोर्ट विभाग की व्यवस्था ही बिगाड दी। स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोग तो सरकारी कारों में घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता की बीच जाकर कभी ये बसों की हालत को देखने की कोि ा ा करें तो इनको पता चलेगा। वहां लोगों को बसें

उपलब्ध नहीं हैं। कोई बस में बैठ जाए तो उसके कपडे नहीं बचते।

श्री अध्यक्षः ओम प्रका ा जी, आप तो पर्सनल एक्सप्लेने ान देने के लिये खडे हुए थे। आप बैठ जाएं, यह कोई पर्सनल एक्सप्लेने ान नहीं है। (ाोर)

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सरकार में दम हो तो वह हम पर मुकदमा चलाएं। यह कमजोर सरकार की पहचान हुआ करती है। इस प्रकार की चरित्र हनन की कार्यवाही करने वाले ये लोग हैं। क्या हम कोई विजीलैंस से डरने वाले लोग हैं ? अगर इस सरकार में दम है तो हम पर मुकदमा चलाए। आज मैं यह चैलेंज करता हूं। मेरे खिलाफ तो क्या, मेरी पार्टी के दूसरे किसी सम्माननीय सदस्य के खिलाफ भी अगर सरकार में दम हो तो मुकदमा चलाए और अगर हम दोशी पाए जाएं तो इसके लिये हम बडी से बडी सजा भुगतेंगे। स्पीकर साहब, यहां पर ग्रेवाल कमि ान की रिपोर्ट भी धरी की धरी रह गई। सरकार उसको तो इम्पलीमैंट करके देखें। ये लोग इस प्रकार की चरित्र हनन की राजनीति इसलिये करते हैं ताकि इनके भ्रश्ट कारनामों की तरफ लोगों की तवज्जो न जा सके। ये पैसे कैसे बटोरें, इस बात को ये आधार मान कर चल रहे हैं। स्पीकर साहब, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग चरित्र हनन की राजनीति कर रहे हैं।

अगर इनमें दम हो तो मुकदमा करें, हम सामना करने के लिये तैयार हैं।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला: स्पीकर साहब, इनका प्वायंट आफ आर्डर क्या है ? इनकी तो जमनतें जब्त हो गई हैं, इनके तो बोलने का यहां पर कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिये। (ाोर) चार फिगर्ज से ऊपर ये लोग वोटस नहीं ले पाए और आज यहां पर आकर सिर मुंडवा कर बात करने की कोि ा ा करते हैं ? बडी हैरानी हो रही है हमें यह देखकर। (ाोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी ने यहां पर बडे जोर खरो ा के साथ कहा कि अगर सरकार में दम हो– ऐसी बात नहीं है कि सरकार में दम नहीं। यदि आप दोशी पाए गए तो आप जेल की सरीखें में जाएंगे ही। यह कोई बात नहीं है कि सरकार में दम नहीं है। सरकार ने इंकवायरी करवाई है, विजीलैंस से करवाई है। ओम प्रका ा चौटाला हो, सम्पत सिंह हो या कोई और हो, फिर कोई कांग्रेस का ही क्यों नह हो, जो दोशी होगा, उसे अव य ही सरीखों के पीछे दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि चार फिगर में भी मैं वोट नहीं ले सका। (ाोर) आप तो उस समय मुख्य मंत्री थे और आपके पिता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। यहां हाउस में आपके 85

सदस्य थे। आपका यहां पर पूरा बहुमत था और केन्द्र में भी आपके पिता सरकार में थे। तब जाकर आप इनती वोटों से जीते थे। अब जो व्यक्ति 62 हजार वोटों से जीता है, वह मुख्य मंत्री नहीं था बल्कि मुख्य मंत्री का पुत्र था। (ाोर) आप यदि इस बात का जिक्र न करते तो मैं भी न करता, कल बात खत्म हो गई थी। (ाोर) जहां तक दडबा कलां की बात है, वहां से आप इतने हजार वोटों से जीते लेकिन उसके 6 महीने बाद आप इलैक ान लडने की हिम्मत नहीं कर सके। पहले इनके भाई रणजीत सिंह रोड़ी से इलैक ान लडने की बात कर रहे थे और ये दडबा कलां से लडने की बात कर रहे थे। (विघ्न)

एक आवाजः रणजीत सिंह तो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं।

चौधरी जगदी ा नेहराः अगर कोई घर में आ जाए तो उसको धक्के मार कर नहीं निकाला जाता। मैं तो यह कहता हूं कि ओम प्रका ा को छोड कर इनका सारा परिवार कांग्रेस की तरफ है। एक बात इन्होंने कही कि 6 महीने के बाद, जब चुनाव हुए तो हमारे बिल्कुल अनजान आदमी श्री मनीराम वहां से 6 हजार वोटों से जीते। स्पीकर साहब, ये खुद वहां से 50 हजार वोटों से जीते थे तो 6 महीने के बाद इतनी वोटें इनकी कैसे कम हो गई ? इसलिए वे वहां से दोबारा इलैक ान लडने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर इन्होंने बसों का जिक्र किया, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। जब ट्रांसपोर्ट और फाइनैंस डिपार्टमैंट, दोनों ने

यह कह दिया कि मिनी बसें खरीदना बाएबल नहीं हैं तो फिर इन्होंने वे बसें क्यों खरीदी और वे भी इतनी ज्यादा तादाद में ? आपको पता है कि उसके बाद अखबारों में क्या क्या बातें आई ? इन्होंने मजदा और टयोटा से किस ढंग से कमी ान लिया ? इसके इलावा, जो मिनी बसें हैं, वे चाहे लम्ब रूट की हों, चाहे छोटे रूट की हों, उनकी बाएबिलिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट देखता है, न कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर परचेज कमेटी का हैड होता है, तो क्या उसको डिपार्टमैंट के व्यू को ओवर लुक करना चाहिए ? क्या हर बात में कमि ान खाना चाहिए ? आपने तो गरीब लोागें को सौ रूपए देख कर उसमें से भी दस रूपए खा लिए। इसलिए आपको बोलने की कैसे हिम्मत हुई ? (ाोर) स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि छोटे रूटस के परमिट प्राईवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि छोटे रूट अनवाएबल हैं, उनके परमिट प्राइवेट लोगों को दिए जाएं। क्योंकि वहां सवारियों की पूरी सुविधा नही ंहै, वे अपने टैम्पो या मिनी बसें चला कर लोगों को सुविधा दे सकें। इसके साथ साथ ऐसा करने से अन एम्पलायड को भी एम्पलायमैंट मिलेगी। इसमें सिर्फ मिनि बसों के परमिट अनएम्पलायड नौजवानों को देने की बात है। स्पीकर साहब, सबसे बडी बात इनके समय में जो हुई, वह 1200 बसेां की जलाने की हुई। इन श्रीमान जी के ला एण्ड आर्डर में 1200 बसें सोनीपत और रोहतक में जलाई गई। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के बारे में यह स्थिति थी कि चौधरी देवी लाल चाहते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट

लागू करवाने के बारे में, यदि हमारी पूछ नहीं हुई तो कया होगा ? इसलिए इन्होंने यह तरीका अपनाया और बसें जलाईं। स्टेट गवर्नमैंट का कोई ऐसा औफिस नहीं रहा जिसको इन्होंने नहीं जलाया हो। फिर आज ये कानून व्यवस्था की बात कैसे करते हैं ?

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः स्पीकर साहब, इस हाउस के सम्मानित सदस्य दुर्भाग्य से मंत्री के पद पर विराजमान हैं, इन्होंने बगैर जरूरत के इस प्रकार की बात को उठाने का प्रयास किया, जिसका कोई मतलब नहीं है। केवल इनकी एक सोच है कि ओम प्रका ा चौटाला के खिलाफ कीचड उछाला जाए। इनको इसका भी ज्ञान नहीं कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी की सहमति से जो निर्णय लिये जाते हैं, वे निर्णय सामूहिक होते हैं। अगर मुख्य मंत्री मौजूद हों तो वह चेयर पर होता है। अगर न हो तो उस मीटिंग को कमेटी का दूसरा सदस्य प्रिजाइड करता है, कोई दूसरा नहीं करता। कमेटी की मीटिंग के आधार पर ये निर्णय लिए गए थे और उस निर्णय के खिलाफ अगर मौजूदा सरकार यह समझती है कि कोई बेकायदगी हुई है तो विजिलैंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्कवायरी कराएं, उसकी सजा भुगतने के लिए हर आदमी पूरी तरह से तैयार है। इस सदन का एक सम्मानित सदस्य कहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह से बिगड गई। जो लोग टैरेरीस्टस को प्रोटैक ान दिया करते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर दिखाते ? अभी रीसैंटली, चार दिन पहले पन्नी वाला मोटा गांव में मंत्री के परिवार के सदस्यों ने किसी के

घर पर जा करके उन लोगों की मारपीट की, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए ? ये बात को निराधार बढाने की कोि ा ा करते हैं लेकिन इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस बात को ले करके, इस बेकायदगी के खिलाफ किस ढंग की आवाज उठाई जाती है। ये प्वायंट आफ आर्डर लेकर बैठ जाते हैं, इनको प्वायंट आफ आर्डर की परिभाशा का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार देने के लिए प्राईवेट सैक्टर में बसों के रूट परमिट देने का काम किया है। क्या ट्रेजरी बैंचिज के लोग यह बताएंगे कि अगर प्राईवेट सैक्टर में लोगों को रूट परमिट दिए जाएंगे, तो जो मौजूदा एम्पलाइज हैं, जो बसों पर काम कर रहे हैं क्या उनकी छंटनी हो जाएगी ? अगर वहीं लोग काम करेंगे तो फिर दूसरे लोगों को कैसे रोजगार दिए जाएंगे ? रोजगार देने की बात को ले करके ये अनेक प्रकार की ऊल–जलूल की बातें करने की कोि ा ा करते हैं। चरित्र हनन की राजनीति अपनाने का एक ध्येय अपना कर चलते हैं। ऐसे लोग, इस बात को केवल मुख्य मंत्री कैसे राजी हो सके, इस बात के प्रयास में लगे रहते हैं जनता को राजी करने से काम चलेगा लेकिन मुख्य मंत्री को राजी करने से तो कुछ अर्सा ही बीत सकता है। इस प्रकार से चरित्र हनन का इल्जाम लगाने की बजाये, जो असलियत हो, वह लोगों के समक्ष पे ा करनी चाहिए।

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। चौधरी ओम प्रका ा चौटाला ने

इस ढंग से बात कही कि मुझे हाई पावर्ड परचेज कमेटी के बारे में कुछ पता नही नही है। इन्होंने कह दिया कि उसके चेयरमैन मुख्य मंत्री होते हैं। श्रीमान जी आप तो साढे 6 महीने ही मुख्य मंत्री रहे हैं और आपकी सरकार में सम्पत सिंह और धीरपाल जैसे आदमी थी, इसलिए आपने साढे 6 महीने राज चला लिया, वरना साढे 6 महीने भी नहीं चलता। मेरा एक्सपीरियंस साढे 6 साल का है, साढे 6 महीने का नहीं है। स्पीकर साहब, एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। (विघ्न) (इस समय श्री राम कुमार कटवाल बोलने के लिए खडे हो गये)

श्री अध्यक्षः कटवाल साहब, आप बिना परमि ान के न बोलें, बोलने से पहले आप परमि ान लें। आपको बोलने की परमि ान नहीं है इसलिए आप अभी बैठिये।

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, चौधरी ओम प्रका ा जी ने बडे ही नफीस ढंग से अपनी बात कही परन्तु उनके अपने घर के आदमियों मे ंभी झगडा हुआ। हमारे घर का जो झगडा हुआ उसका बाकायदा पर्चा दर्ज हुआ है। अगर हमारे घर के आदमी गलत काम करेंगे तो सजा होगी। मैं आपके घर की बात करता हूं। (विघ्न) इनके लडके और उनके भाई प्रताप सिंह के बीच गोलियां चलीं और पर्चा दर्ज हुआ। (विघ्न) अगर आप ऐलिगे ान्ज लगाएंगे तो आप पर भी ऐलिगे ांज लगेंगे। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला: स्पीकर साहब, ये बिल्कुल निराधार बोल रहे हैं, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ है।

चौधरी जगदी ा नेहरा: आपके भाई चौधरी प्रताप सिंह और उनके साथियों तथा आपके समर्थकों में झगडा हुआ। भाई भाई का झगडा है, हमारा तो इसमें कोई झगडा नहीं है, पर्चा दर्ज है। रवी सिंह सरपंच है, उसने पर्जा दर्ज करवाया है, उस सरपंच की डैथ हो गई है, परन्तु डबवाली सदर में पर्चा दर्ज हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी सरकार होते हुए भी हमारे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही न हो। (विघ्न) वह सारी बातें आपकी हैं। यह सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और तीन साल तक आपकी छाती पर हम यूं ही मूंग दलेंगे। केन्द्रीय सरकार से हमें इस संबंध में सहायता मिलनी थी, वह नहीं आई है। इसके लिए 1992–93 के बजट में हमने पहले से कहीं ज्यादा प्रावधान रखा है, जिसकी की वजह से पुलिस का मनोबल काफी बढा है। बजट से अलग, हमने इस काम के लिए 15.36 लाख रूपयों की रा ि ा का पुलिस के कामों के लिए प्रावधान किया हैं बार्डर एरियाज में हमने अलग से पुलिस चौकियां स्थापित की हैं ताकि हरियाणा के अंदर उग्रवाद न पनप सके। इसके साथ साथ हमने यह भी प्रावधान किया है कि उग्रवाद के कारण जिस सिपाही, हवलदार या थानेदार की अचानक मृत्यु हो जाती है तो सरकार सिपाही के परिवार को 1 लाख, हवलदार के परिवार को 2 लाख

और थानेदार के परिवार को 3 लाख रूपए की रा ि ा देगी ताकि पुलिस वालों का मनोबल ऊंचा हो और अपने प्रदे ा के हर व्यक्ति की जानमाल की रक्षा खु ी से कर सकें। इसी इरत राज पत्रित अधिकारी के परिवार को पांच लाख रूपया दिया जाता है। इसके अलावा उसके परिवार को उसकी रिटायरमैंट तक पूरी तनखाह दी जाती है। हम किसी कीमत पर हरियाणा में ला एंड आर्डर की पोजी ान खराब नहीं होने देंगे। हमने अपनी पुलिस का मौरल ऊंचा रखा है और इसी वजह से हमारी पुलिस हरियाणा की सेवा कर रही है। यहां पर माननीय सदस्यों ने जो भी भावनउएं प्रस्तुत की, सरकार उनकी कद्र करती है। हम उनकी भावनाओं पर पूरी सहानुभूति से विचार करेंगे। अब मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक से पच्चीस तक की जो डिमांडज हैं, उनको युनानी मसली पास कर दिया जाए ताकि अगले साल की मांगें पूरी हो सकें। स्पीकर साहब, एक बात चुंगी के बारे में कहना चाहता हूं जो मुझे अभी राम भजन जी ने याद दिलाई है। हमने चुंगी खत्क करने के लिए एक सब कमेटी बनाई है। वह कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी इसमें जहां कमेटियों को पांच करोड रूपए सालना नुकसान का सवाल है, वहां पांच हजार मुलाजिमों का भी सवाल है। इस बारे में हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं। चेयरमैन साहब, गवर्नमैंट कालेज के जो लैक्चररज 3700–5700 के स्केल में हैं वे तो क्लास टू में आते हैं। और दूसरे जो अफसर 2200–4000 के स्केल में हैं वे तो क्लास वन में हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चाहे गवर्नमैंट कालेज के लैक्चररज हों चाहे प्राइवेट

कालेज के हों अथवा जे0बी0टी0 टीचर्ज हों, इनकी जो जैनुयन डिमांडज हैं उनको जरूर माना जाए। चेयरमैन साहब, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि भिवानी में ....

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Chairman: Is it the sense of the House that the sitting of the House be extended by half an hour ?

Voices : Yes.

Mr. Chairman: The Sitting of the House is extended by half an hour. Chauhan Sahib, please wind up within a minute.

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, भिवानी एजूके ान बोर्ड की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले साल नकल हुई और पर्चे लीक हुए। मुख्य मंत्री जी ने आ वासन दिया था कि चाहे कोई भी आदमी हो, जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ इन्क्वायरी करवाई जाएगी। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक एस0डी0 स्कूल है, वही आदमी जो एक साल पहले बोर्ड का अध्यक्ष था, उसको सरकार ने हटा दिया। यह तो सरकार की मर्जी है जिसको चाहे हटा सकती है लेकिन

उस आदमी ने उस स्कूल को अपने घर की सम्पत्ति बना ली है। उस स्कूल की कोई लीगल मैनेजिंग कमेटी नहीं है और कोर्ट ने भी इल्लीगल करार दे दिया है। स्कूल वालों ने सरकार को यह लिख कर भेजा है कि उन्हें सरकार से कोई ग्रांट नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा स्टेट में ऐसा कोई और स्कूल है जो इस तरह का है ? चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि भिवानी में एजूके ान को एक तरह का अखाडा बनाया हुआ है। ऐसे लोगों ने एजूके ान को कमर्ि ायलाइज्ड कर दिया है। इन लोगौं ने इन संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। मेरी सरकार से अर्ज है कि उसके अगेंस्ट एक ान लिया जाए। इसी डिमांड पर बोलते हुए मैं मैडीकल कालेज के बारे में एक बहुत ही आ चर्यजनक बात बताना चाहूंगा। हरियाणा प्रदे ा में एक ही मैडीकल कालेज है। चेयरमैन साहब, 1992 में मैडीकल कालेज में, जिस तरह से 10 लडकों का दाखिला हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले तो उन 10 लडकों को डाक्टर ने कलरविजन के बेसिज पर अनफिट डिक्लेयर कर दिया लेकिन उन लडकों ने एक अलग से बोर्ड बनवा लिया जिस का वही डाक्टर अध्यक्ष बनाया गया। अब इस बारे में वही डाक्टर जाने या बोर्ड जाने। उस डाक्टर ने उन लडकों से एक एक लाख रूपए रि वत लेकर दोबारा मैडीकल कालेज में एडमिट करवा दिया। चेयरमैन साहब, कलरविजन एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। जो लडके पहले रिजैक्ट किए हुए थे, उनसे उस डाक्टर ने एक एक लाख रूपए लेकर दोबारा

दाखिला दिला दिया। मैं कहना चाहूंगा कि हैल्थ मिनिस्टर साहिबा इस प्रकार की गडबड जो कमि र्यिलाइजे ान ऑफ मैडीकल एजुके ान के आधार पर हुई है, उसको तुरन्त बंद किया जाए।

इसके अलावा, अब मैं डिमांड नंबर 13 के बार में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने एक बात कही थी, इन्होंने बुढापा पैं ान के लिए उम्र पहले 55 साल की रखी थी, लेकिन बाद में 60 साल कर दी। लेकिन आज किसी को भी सही तरीके से पैं ान नहीं मिल रही है। पैं ान पाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। बहन करतार देवी भिवानी गई थीं। इनसे हमने कहा था कि 40 साल का आदमी बुढापा पैं ान ले रहा है और उसका बडा भाई बगैर पैं ान के बैठा है। उस समय इन्होंने आ वासन दिया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम इस बारे में दोबारा सर्वे करवाएंगे और जो पें ान से वंचित रह गए हैं उनको 60 साल की उम्र के हिसाब से पैं ान देंगे। चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदे ा के अंदर जो व्यक्ति बुढापा पैं ान के हकदार हैं, उनको पैं ान अव य मिलनी चाहिए। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि विधवा औरत को पैं ान देने का सरकार ने प्रोविजन किया हुआ है। मैं एक अर्ज यह भी कर देना चाहता हूं कि कोई गरीब आदमी तो पैं ान लेने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई विधवा औरत पैं ान लेने के लिए यह झूठ नहीं बोल सकती कि वह विधवा है, उसको

पैं ान मिलनी चाहिए। मैंने अपनी कांस्टीच्यूएंसी के ऐसे बहुत से केजिस डी0सी0 को बताए लेकिन डी0सी0 साहब उन औरतों को विधवा होने के बावजूद भी पैं ान नहीं देते हैं। इससे बडा सबूत और क्या हो सकता है जब कोई नारी यह कहे कि वह विधवा है, इसलिए उसको पैं ान मिलनी चाहिए ? कोई नारी यह झूठ नहीं बोल सकती कि वह विधवा है। हमारे वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी की व्यक्तिगत राय तो यह है कि पैं ान का देना बिल्कुल खत्म ही होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर हरियाणा सरकार पैं ान नहीं देना चाहती तो अलग बात है, लेकिन हरियाणा सरकार बुढापा पैं ान, विधवा पैं ान और विकलांग पैं ान देने का ढोंग न बनाए, यदि उनको पैं ान देनी है तो सही ढंग से दे।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नंबर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। पिछली बार चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो सडक से न जुडा हो। मेरे हल्के में जो बौन्द खुर्द गांव है, उसकी वोट भी 1691 है, लेकिन उसको आज तक सडक से नहीं जोडा गया है जबकि मुख्य मंत्री ने 31–5–92 तक सडक से जोडने के बारे में कहा था। अब 31–5–93 आने को है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से मांग है कि उस गांव को जल्दी से जल्दी सडक से जोडा जाये।

Mr. Chairman: No repetition please. All these things have already come on record. Please take your seat. Shri Rajinder Singh Bisla, Shri Zakir Hussain and Shri Azmat Khan will speak on the Appropriation Bill. Now Shri Ram Bilas Sharma will speak.

श्री अमर सिंहः चेयरमैन साहब, मैंने डिमांड पर कट मो ान दिया हुआ है। मैं 2–3 डिमांडों पर सिर्फ 5–7 मिनट बोलना चाहूंगा, कृपया मुझे समय दिया जाये।

श्री सभापतिः आप कल 10 मिनट बोल लेना।

प्रो0 राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): चेयरमैन साहब, इस समय सदन में मांगौं पर चर्चा चल रही है, इसलिए मैं 2–3 मांगों पर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मांग संख्या 3, जो गृह विभाग से संबंधित है। उस पर अपनी बात कहना चाहता हूं। हरियाणा और पंजाब के लोगौं ने 8–10 साल से आतंकवादियों के साये में काली रातें गुजारी हैं। आतंकवादियों ने न जाने कितने निर्दोश लोगों की जानें लीं। इन उग्रवादियों के खिलाफ न केवल पंजाब की पुलिस लडी, बल्कि हरियाणा की पुलिस भी लडी और अपनी भाहादत दी। चेयरमैन साहब, राजनेता की 'विल' लडती है और नौजवान की छाती लडती है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पडता है कि पिछले दिनों खन्नौरी गांव में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुलिस के चार नौजवान गए, उनके पीछे उनकी सुरक्षा के लिए कोई फालो अप ऐक ान नहीं लिया; उनको बचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। आतंकवादी तो अपनी योजनानुसार

एक कमरे में थे और उन्होंने उन चारों जवानों को भाहीद कर दिया। वे चारों जवान वहां पर भाहीद हो गए। उनके भाहीद होने पर उनके परिवार वालों से किसी ने जाकर हाल तक नहीं पूछा, जबकि उनके परिवार वालों ने कहा कि वे तो भाहीद हुए हैं। इन चार नौजवानों में मरने वाला एक मेरे नारनौल का रघुनंदन भी था। मैं उसके घर पर गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से उनकी भाहादत के बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं की गई। चेयरमैन साहब, पुलिस में चाहे किसी अधिकारी/कर्मचारी की परमो ान की बात हो, बिरादरी के नाम पर कभी परमो ान नहीं की जाती। यह जाट है, यह ब्राह्मण है या और किसी बिरादरी का है, इस आधार पर उसकी परमो ान की जाए, तो अच्छी बात नहीं है। मेरी मांग है कि सी0एम0 साहब को इन सब बातों की तरफ गौर करना चाहिए और जिसका जो हक बनता है, उसको दिया जाना चाहिए ताकि पुलिस के जवानों की 'विल' न टूटे। चेयरमैन साहब, हमारे वहां पर भूशण सोभापुर के एक प्राइमरी स्कूल में पढने वाले बच्चे को बुला कर मार दिया गया। हमारी पार्टी बडी जागरूक पार्टी है। जब हमारे एक एक्स एम0एल0ए0 श्री कैला ा चन्द्र भार्मा ने इस बात को उठाया तो उस पुलिस अधिकारी ने श्री कैला ा चन्द्र भार्मा के लडकों की भाादी नहीं होने दी। इतना ही नहीं, पालम में जो लडकी वालों का घर था, वहां पर एक वि ोश पुलिस अधिकारी भेज कर जो भाादी के तम्बू आदि लगे हुए थे, उखडवा दिए। चेयरमैन साहब, मैं भी उस बारात में गया था। वहां के पुलिस कम्तान ने बारात

नहीं जाने दी। चेयरमैन साहब, राजकुमार नाम का एक सिपाही भुशण सोभापुर गांव का रहने वाला है और जीन्द पुलिस में सर्विस करता है। उसने सच्ची बात कह दी। उसने लडके के अपहरण का कारण यह बताया कि सेना के एक बडे अधिकारी के बारे में 4–5 गांवों की पंचायत ने कह दिय कि इसमें वे भाामिल थे। वह अफसर एस0पी0 का मित्र था। उसने जीन्द जिले के एस0पी0 से कह कर राज कुमार सिपाही को सस्पैंड करवा दिया। उस एस0पी0 ने अपनी जुरिस्डिक ान में उसके खिलाफ 6 झूठे मुकददमें दर्ज करवा दिए। एक केस दांगडा जाट गांव में दर्ज हुआ। चेयरमैन साहब, किसी पुलिस अधिकारी के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हमने कभी मुख्य मंत्री जी से यह नहीं कहा कि इस अफसर को यहां लगाओ या उस अफसर को वहां लगाओ, लेकिन किसी अफसर को सूबेदार बना दिया जाये और जो कुछ वह चाहे करे ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को कम से कम ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उस सिपाही ने स्कूल में पढने वाले बच्चे के बारे में सच्च बोला था।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं नगर विकास संबंधित मांग पर बोलना चाहता हूं नगरों में नगरपालिकाओं की क्या हालत है, यह सबको मालूम है। चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने नगरपालिकाओं के चुनाव करवाए। ये भी पार्टी से चुनाव लडे और हम लोग भी लडे। इन्होंने पार्टी के टिकट पर ये चुनाव नहीं लडे, लेकिन हमने अपनी पार्टी के सिम्बल पर चुनाव लडे। यमुनानगर

की नगरपालिका में हमारी पार्टी का आदमी चेयरमैन बन गया। रोहतक में हमारी पार्टी का चेयरमैन बन गया। इनकी पार्टी के लोग भी कई जगहों पर चेयरमैन बने। पहले चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि जो भी चुन कर आ जाएंगे, उनको बना देंगे। अपनी कांग्रेस पार्टी की हालत को देखकर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने चुनाव नि ाान पर चुनाव लड सकें। फिर यमुना नगर के चेयरमैन को दो दो मंत्रियों ने जाकर काम नहीं करने दिया। भोर सिंह जी यहां पर इस वक्त बैठे हुए नहीं हैं। चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं जीन्द की घटना की रिपीट नहीं करना चाहता। अम्बाला के अन्दर देख लीजिए। अम्बाला के बारे में अखबारों मे आ रहा है। वहां पर वाईस प्रेजीडैंट बी0जे0पी0 का चुना गया। उसको वोट के माध्यम से चुना गया। इनकी पार्टी के लोग, लोगों को हरिद्वार सौगन्ध दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। बी0जे0पी0 म्युनिसिपल कमि नर की संख्या 12 है लेकिन उनको 16 वोट मिले तो चार वोट किसने दिये ? वे लोग वहां की नगरपालिका की प्रोसीडिगंज चलने नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन सर, नगरपालिकाओं के जो जन प्रतिनिधि हैं, उनको कोई ग्रान्ट और विकास का काम नहीं दिया जा रहा। रोहतक की नगरपालिका में किस तरह से खून खराबा हुआ, किस तरह से लोगों को सैर सपाटे करवाये गये और किस तरह से हमारी पार्टी के वहां के चेयरमैन रमे ा सहगल ने हाई कोर्ट में जाकर अपनी जान बचाई, यह आप सभी को पता है। चेयरमैन सर, जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनको काम करने की इजाजत होनी चाहिए। उनको यूं दबा कर, उनके गले में अंगूठा

देकर अगर इस तरह से करेंगे तो प्रजातन्त्र से लोगौं का वि वास उठ जाएगा।

Chief Parliamentary Secretary (Sh. Subhash Batra): On a point of order, Sir.

Prof. Ram Bilas Sharma: Mr. Chairman Sir, what is his point of order ?

Mr. Chairman: Ram Bilas Ji, he has a right to put a point of order.

Prof. Ram Bilas Sharma: What type of point of order, he wants to raise ? यानि कि जिस जगह की चर्चा मैं करूंगा, वहां के आदमी खडे हो कर प्वायंट आफ आर्डर करने लग जाएंगे ? चेयरमैन सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने रोहतक नगरपालिका की चर्चा की है।

Mr. Chairman: Sharma Ji, let him say, whatever he wants to say.

श्री सुभाश बत्राः चेयरमैन सर, अभी माननीय सदस्य ने रोहतक नगरपालिका की चर्चा की। रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी में हमारे साथ क्या हुआ, मैं इनको बताना चाहता हूं (विघ्न) चेयरमैन साहब, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, यह किस टाईप का प्वायंट आफ आर्डर है ? ये मेरे खिलाफ प्रिविलेज मो ान ला सकते हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाश बत्राः चेयरमैन साहब, हाईकोर्ट में एस0एल0पी0 के अन्दर इन लोगों के साथ क्या हुआ ? डबल बैंच ने इनके खिलाफ फैसला दिया, दोबारा चुनाव हुए और हमारी म्यूनिसिपल कमेटी बाकायदा वोट से बनी।

Prof. Ram Bilas Sharma: Is it the point of order, Sir ?

Mr. Chairman: He has just clarified the position, what you had stated about Rohtak Municipal Committee. Now you speak.

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, यह प्वायंट आर्डर की बात ही नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी हो गई है कि इस इलाके से एम0ए0ए0 बन गए तो खुदा बन गये। यह त्यौहार तो हर तीसरे साल होना है, अब तो यह 6 महीने बाद ही होने वाला है। जिस का जैसा आचरण है, जनता उसको देख रही है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, नगरपालिका का मामला है। एक आदमी जो दारू का ठेकेदार है, उसने नगरपालिका, की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उसके बारे में डिप्टी कमि ानर ने जो लिखा है, वह मैं आपको बताता हूं :–

"I also direct the MC Mahendergarh to re-verify the dimensions of the plot of Sh. Leela Dhar to ascertain whether the construcdtion is within his own limits or not. In case the construction is found outside his ownership, the Committee

shall be at liberty to demolish the portion of the building which has been encroached by the applicant."

चेयरमैन साहब, कंस्ट्रक ान के बारे में नगरपालिका के सामने गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये हरिजनों के बारे में बडी बडी बातें करते हैं कि उनको सरप्लस की जमीन दी जाएगी। कल कृश्ण लाल जी ने बात कहीं तो कहने लगे कि कुछ फैक्टस की बात होती है। चेयरमैन साहब, यमुना नगर जिले में खदरी गांव है, दादुपुर गांव है। वहां पर दौ सौ एकड जमीन सरप्लस पाई गई है। वह जमीन हरिजनों को अलाट हो गई थी परन्तु वे गरीब हरिजन, उस जमीन का कब्जा लेने की स्थिति में नहीं थे वह जमीन उनको नहीं मिली क्योंकि उस जमीन पर जिस आदमी का कब्जा था, उसका किसी कांग्रेस के आदमी से ताल्लुक है। चेयरमैन साहब, या तो ये कानून न बनाएं या हरिजनों को यह न कहें कि हम आपको जमीन देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो इन्हें हरिजन भाई याद आएंगे। चैयरमैन साहब, आज हरिजनों की आबादी बढ रही है, पिछडे हुए लोगों की आबादी बढ रही है। उनकी बढती हुई आबादी के अनुसर, उनको कहीं पर भी प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। एक ही कमरे में बेटा है, बाप है, वहीं पर बकरी है और वही पर चूल्हा हैं बारि ा के दिनों में गरीब की झुग्गी चूएगी और सावन में उसकी झुग्गी भी जाएगी। चेयरमैन साहब, मध्यप्रदे ा में हमारी सरकार बनी तो बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर का जन्म दिन मनाया उस समय वहां की हमारी पार्टी की सरकार ने 4 लाख एकड जमीन पिछडे हुए लोगों को दे दी।

उसका इन्तकाल भी उनके नाम करवा दिया। यहां पर जो सरप्लस जमीन है, पंचायत की जमीन है उसके लिए चौ0 भजन लाल जी और इनके मंत्री लोगों का आपस में डुक बज रहा है। चेयरमैन साहब, या तो ये हरिजनों की बात न कहें, अगर कहें तो उनको थोडा बहुत देना चाहिए। कुछ बातों की तरफ इनको देखना चाहिए और कुछ बातों को सिरे चढाना चाहिए वरना जो हरिजन कमजोर हैं, उसको न्याय नहीं मिलेगा। संगरेहेड़ी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु उस हरजिन को दबा कर उनका आपस में राजीनामा करवा लिया। चेयरमैन साहब, इनको याद रखना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतिहास में काला दाग छोड जाती हैं। हरिजनों की बातें, खुद मुख्य मंत्री जी नोट भी करते हैं, परन्तु नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको सीरियसली नहीं लेती। संगरेहेड़ी में संतोश के साथ बलात्कार हुआ। उसका घरवाला गया तो उसको जान से मार दिया गया। बाद में उसका बाप गया तो उसको भी डराया धमकाया कि तेरा जीना दूभर कर देंगे और बाद में उसके साथ राजीनामा करवा दिया। चेयरमैन साहब, यह कैसा इन्साफ है यह कोन सा राज है ? अगर गरीब को न्याय नहीं मिलेगा और केस दबा दिया जाएगा तो उसका क्या होगा ? यह जमीन किसी को माफ नहीं करेगी।

श्री सभापतिः आप जल्दी खत्म करें।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, मैं सामुदायिक विभाग के बारे में भी बोलना चाहता हूं। सरकार के पास कुछ

फण्ड होता है, कुछ पैसा होता है। राव बंसी सिंह जी बहुत ही भोले आदमी हैं। मेरे इलाके के हैं परन्तु ये जहां जाते हैं, वहां पर ये सिक्कों में तोले जाते हैं। कोई प्लीज कह दे तो ये उस पर मेहरबान हो जाते हैं, चाहे वहां पर किसी को जरूरत हो या न हो। चेयरमैन साहब, यह जो सिस्टम है, यह जो पैसा है, यह देख कर इस्तेमाल करना चाहिए। राव बंसी सिंह जी गांव की भूमिका से आए हैं, इन्हें गांव की जरूरत को देख कर पैसा देना चाहिए। यह नहीं है कि एक आदमी को जहां चाहा, वहां लगा दिया और दूसरा आदमी कहीं औंर लगा दिया। यह ठीक है कि ये महेन्द्रगढ में पैर जमाना चाहते हैं किन्तु इनको यह नहीं पता कि मेरे सामने तो चौटाला जैसे भी चले गए। चेयरमैन साहब, ये वहां पर अन्याय न करें जिस गांव में जितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से पैसा दें। यह नहीं होना चाहिए कि जहां जहां इनको सिक्कों से तोला जाये, वहां ये पांच लाख रूपये दे दें। इसके अलावा, चेयरमैन साहब, सरकार कर्मचारी गरीब होता है, उसकी अगर कोई पिटाई करे तो अच्छी बात नहीं है। वहां पर एक डी0ई0टी0सी0 ने नगरपालिका के एक कर्मचारी की पिटाई की। पीटने वाले के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

विकास मंत्री (राव बंसी सिंह): चेयरमैन साहब, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान है। मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझ पाया कि पंडित जी को मेरी तरफ से गिला क्यों है इनके पेट में क्यों दर्द है ? मेरा हल्का तो अटेली

पडता है। मेरे दिमाग में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है लेकिन इनको पता नहीं क्यों सिरदर्द हो रहा है? यह दर्द भाायद इनको इसलिए हो रहा है कि जब ये स्वयं मिनिस्टर थे, तो इन्हौंने महेन्द्रगढ मैं तो क्या, अपने हल्के में भी कोई विकास के कार्य नहीं किए थे, लेकिन जब से चौ0 भजन लाल जी की सरकार बनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ में ही नहीं, बल्कि सारे हरियाणा के जितने भी गांव हैं, उन सभी का कायाकल्प किया है। चेयरमैन साहब, हम सभी गांवों को वास्तव में कायाकल्प करना चाहते हैं। विकास के कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री जी की इजाजत है कि जिन जिन गांवों में अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया, उन सभी गांवों को पैसा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जहां तक सिक्कों से तोलने की बात का ताल्लुक है मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर मुझे इन्होंने कहीं पर सिक्कों से तुलवाया हो तो बता दें। अगर कोई व्यक्ति मान सम्मान से मुझे सिक्कों से तोलता है तो इससे इनको क्यों दर्द हो रहा है, इसमें मुझे तो कोई लालच नहीं है ? मुझे लगता है कि उस मान सम्मान को देखकर ही इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक दर्द का नतीजा तो यह देख ही चुके हैं। ये वहां पर पंचायत समिति का चेयरमैन बनाना चाहते थे ..... (विघ्न)

श्री सभापतिः यह पर्सनल एक्सप्लेने ान नहीं है। आप कृपया बैठिए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये चाहे पचास बार सिक्कों से तुले, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। जो मेरा दर्द है वह मैं इन तक नहीं पहुंचा रहा हूं। यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

राव बंसी सिंहः चेयरमैन साहब, मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने चौटाला को देख लिया। अगर इनकी ऐसी ही भावनाएं हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे इनका चैलेंज स्वीकार है। (**इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**)

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आप इनसे यह पूछ लें कि यह चुनौती इनको अभी स्वीकार है या जब मौसम आएगा, तभी स्वीकार होगी ? मैं तो इस चैलेंज के लिए आज भी तैयार हूं।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं0 14 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। यह डिमांड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित है। चीनी के दाम बढा दिये गये हैं। इनके आर्थिक सुधारों के कारण गरीब आदमियों की जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं जबकि ये कहते हैं कि ये दे ा में आर्थिक सुधार करके क्रान्ति लाना चाहते हैं। आज मिटटी का तेल, डीजल सभी चीजें महंगी हो गयी हैं। गांव में रहने वाली आबादी को जो गेहूं और रा ान की जरूरत के हिसाब से गेहूं पैदा कर लेता है लेकिन जब गेहूं का

ऐंड का सीजन आता है, उस समय छोटे छोटे किसानों को गेहूं की जरूरत पडती है। इसलिए मेरा कहना है कि इन दिनों में इनको देखना चाहिए कि रा ान का ठीक प्रकार से वितरण होता है या नहीं। स्पीकर साहब, इसके अलावा, मैंने कल भी एक बात कही थी कि रिवाडी, महेन्द्रगढ, लोहारू, कौसली आदि सब डिवीजन बना दिये थे, लेकिन फिर तोड दिये। महेन्द्रगढ में तीन गांव ऐसे हैं जिनका जिला हैड क्वार्टर कहीं पर कर दिया और तहसील कहीं पर कर दी।

श्री अध्यक्षः राम बिलास जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः भजन लाल जी ने डिस्ट्रिक्ट री–आर्गेनाइजे ान कमेटी बनाई। मेरे हल्के के दौंगडाजाट, कलवाडी, मुडियाखेडा और गुलावला गांव ऐसे हैं, जहां की पंचायतों ने कहा कि उन्हें बडी असुविधा है। स्पीकर सर, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे इलाके की जो सिंचाई की समस्या है, पानी तो जब उपलब्ध होगा, तब ये देंगे, परन्तु हमारे दो जिले ऐसे हैं जिनको किसी भी रैगुलर स्कीम, पैरिनियल स्कीम से जोड देना चाहिए। जो नियंत्रण योजनाएं हें जैसे अन्टा ग्रुप, भलोट ग्रुप, बुटाना ग्रुप एव सुन्दरवन ग्रुप– इनमें से किसी भी योजना के अन्तर्गत हम नहीं आते। जहां तक पीने के पानी का ताल्लुक है उस इलाके में जमीन के नीचे का पानी बहुत नीचे चला गया है, कहीं चार सौ फुट कहीं साढे तीन सौ फुट और कहीं पांच

सौ फुट नीचे चला गया। यह वाटर गांव के लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। अतः मुख्य मंत्री जी इस को देखें और प्रायरिटी के आधार पर पानी उपलब्ध कराएं क्योंकि हरियाणा में केवल यही इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की एक्यूट समस्या है, इसके लिए कोई न कोई पक्की व्यवस्था करें। स्पीकर सर, बातें तो बहुत हैं, दर्द इतने हैं मगर .....

श्री अध्यक्षः इन भाब्दों के रिकार्ड न किया जाए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः पानी की जो समस्या है। उसको रैगुलराइज किया जाए। कम से कम पीने के पानी की कोई पक्की स्कीम बना दी जाए और उसे इन चार ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जोडा जाए।

श्री अमर सिंह (एस0सी0– बवानी खेडा): स्पीकर सर, डिमांड नंबर 9, 13 एवं 17 पर मैंने कट मो ान दिया हुआ है। पहले मैं डिमांड नंबर 13 पर अपनी बात सदन में कहना चाहता हूं। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज एक मसला है, जैसे बढती आबादी, अनएम्पलायमैंट और महंगाई की प्रोब्लम है वैसे ही चौथी बैकलोग पूराकरने की कोि ाश की है। मेरा यह दावा है कि अगर बैकवर्ड क्लासिज और हरिजन बैकलोग पूरा कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से और आंकडें के मुताबिक कोई भी हरिजन पढा लिखा बेरोजगार नहीं रह सकता। स्पीकर सर, 4218 कांस्टेब्ल्ज में से इन्हौंने ि ाडयूल्ड कास्टस 718 भर्ती किए। इन्होंने जो रीजन

बताया उस पर मुझे बडी भारी आपत्ति है। इन्होंने कहा है कि ि ाडयूल्ड कास्ट के कम्पीटैंट और सूटेबल कैंडीडेटस नहीं मिले। अगर मुख्य मंत्री जी इस बात का सर्व कराएं तो पाएंगे कि ि ाडयूल्ड कास्ट के दो लाख कैंडीडेटस के नाम एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज में दर्ज हैं और वे सब मैट्रिक पास हैं। यह जो रीजन दिया है यह बडा आपत्तिजमन है –

"candidates who were found suitable were enlisted form reserved category. Every effort will be made to fill up the backlog in the reserved category in the next recruitmen drive. Instructions have been issued to the concerned authorities to make good the shortfall in the Commando Force during the next recruitment proposed to be made during March, 1993".

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सहमतित हो तो हाउस का समय बीस मिनट और बढा दिया जाए।

15.00 बजे।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय बीस मिनट और बढाया जाता है।

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि पहली नवम्बर 1966 को पुलिस डिपार्टमैंट में भाोर्टफाल क्या थी, यह कैटेगरीवाइज बता दें। स्पीकर साहब, अगर हर डिपार्टमैंट में रोस्टर रजिस्टर मेनटेन कर दिया जाए, इसके बार में एक पौलिसी बना दी जाए कि हर हालत में रोस्टर मैनटेन किया जाए। स्पीकर साहब, ि ाडयूल्ड कास्ट को इग्नोर करने के लिए एडहौक बेसिज पर रिक्रूटमैंट करनी भाुरू कर दी। पिछले दिनों पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर ने बताया कि भाोर्टफल है और हम एस0एस0एस0 बोर्ड का इन्तजार कर रहे हैं। जब उसकी लिस्ट आएगी तो हम भाौर्टफाल पूरा करेंगे। कोई टाईम बाउन्ड पौलिसी बना दी जाए कि इतने समय के अंदर जो भाोर्टफाल है वह पूरी कर दी जायेगी। स्पीकर साहब, एक बार ज्वायंट पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने देखा कि ि ाडयूल्ड कास्टस की भाौर्टुाल पचास परसैंट है तो उन्होंने आदे ा दिए कि भविश्य में पचास परसैंट ि ाडयूल्ड कास्ट की भर्ती होगी और इस तरह से भाोर्टफाल को पूरा किया। स्पीकर साहब, यहां पर नारनौल की बात आई। मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इस बात की वेरिफिके ान करा लें कि नारनौल में केवल हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती के लिए एलान किया गया था। वहां पर पचार हजार लडके चले गए। वहां पर कई ऐक्सीडैंट हुए। दो चार आदमी वहां पर सीरयसली जख्मी हुए लेकिन यह वजह देना कि सूटेबल कैंडीडेटस नहीं थे, यह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, सभी डिपार्टमैंटस का यही हाल है। यह तो हुई

सर्विसिज की बात। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों को जो दो लाख रिहाय ी प्लाट दिए गए थे उन पर तो एक दौर ऐसा आया कि दूसरे लोगों ने ही कब्जा कर लिया। उनको वे प्लाट मिले ही नहीं और हरिजनों की पापुले ान बढने के बाद जो उनको नए प्लाट दिए जाने थे वे रूक गए। स्पीकर साहब, तीस परसैंट प्लाटों पर नाजायज कब्जा है। हर जिले में यही हालत है। मुख्यमंत्री जी आप इस बारे में हर जिले के डिप्टी कमि नर से रिपोर्ट मंगवा लें। स्पीकर साहब, सरप्लस जमीन की भी एक कहानी बन गई है। सरदार प्रताप सिंह जब मुख्य मंत्री होते थे तो उस समय मैंने कहा था कि कंसोलिडे ान का सिस्टम गलत है। जब कंसोलिडे ान हो तो सरप्लस जमीन का एक कुर्रा बनाया जाता है। एक कुर्रा अगर बनाया जाए तो उन हरिजन लोगों को एक जगह अलौटमैंट हो सकती है। कहीं दो एकड है, कहीं चार एकड है। अगर वह कब्जा भी ले ले तो कैसे उसको पानी मिलेगा और कैसे रास्ता मिलेगा ? इसलिए सरप्लस की कहानी बिलकुल गलत है। स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल था जिसकी सरकार ने ऐक्सटैं ान मांगी है। वह सवाल था–

(a) “The districtwise total acreage of surplus land as on 1-11-1966; in the State;

(b) the land out of that as mentioned in part (a) above in the villages of the State together with the details thereof; and

(c) whether the land referred to in part (b) above has been allotted among the persons belonging to Scheduled Castes tenants; if so, the districtwise details thereof ?"

इसमें ऐक्सटैं ान मांग ली है और ऐक्सटैं ान इसलिए मांग ली कि सरकार का खाता ठीक नहीं है। हरिजनों को सरप्लस जमीन देने की बात तो दूर रही आज हालत यह है कि हरिजनों को अपने प ा जगहों पर इनक्रोचमैंट हो रही है। स्पीकर साहब, यह बहुत बडा मामला है और सरकार इस तरफ ध्यान दे और औन दि फलोर आफ दि हाउस यह ऐन ायोर करे कि कस्टोडियन की जमीन से जो रूरल एरिया में हरिजनों को प्लाट दिए गए हैं। वे उनके मिलें और उन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, वह छुडाया जाए। (घंटी)

स्पीकर साहब, अभी तो एक ही डिमांड पर बोला हूं। मेरी दो आईटमज और बाकी है। इसके अलावा, मकान बनाने की बात है। सरकार ने हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की ओर से 3033 मकान बनाये हैं। उनमें से 1983 तक, केवल 1797 हरिजनों को अलाट हुए हैं और 1236 अलाट होने अभी रहते हैं, खाली पडे हुए हैं और उनकी आखिर में आक ान हुई। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय यह नोट करें कि केवल 13 लाख 70 हजार रूपये में वे मकान आक ान हुए, जबकि उनके बनाने के ऊपर 7 लाख 70000 रूपये व्यय किया गया। फिर ये कहते हैं कि हरिजनों की तरफ उनका पूरा ध्यान है ? स्पीकर साहब, मैं बताता हूं कि पिछले दिनों हरिजनों की कितनी तरक्की

हुई है।। सरकार बताएगी कि पिछले दिनों कितने असिसटैंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल कितने ि ाडयूल्ड कास्टज के और कितने बैकवर्ड क्लासिज के लगाये गये हैं ? जो 64 कारपोरे ांज के लीगल एडवाईजर्ज बनाए गए, उनमें से कितने बैकवर्ड क्लासिज के और कितने ि ाडयूल्ड कास्टस बनाए गए ? 18 नायब तहसीलदार प्रोमोट किये गये, उनमें से कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड क्लासिज के हैं ? जिस भर्ती का मैंने जिकर किया है उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आज खेतों के अंदर केवल हरिजन लडके ही तो काम कर रहे हैं वे 6–6 फुट लम्बे कद के तगडे जवान लडके हैं। उनके सिवाये खेतों में और कौन काम करता है ? वही लोग उद्योगों में भी काम करते हैं लेकिन ऐसे नौजवानों को दूसरी जगहों से यानी भर्ती से क्यों इग्नोर किया जा रहा है ? यह सारा काम हरिजनों के कन्धों पर ही तो है। स्पीकर साहब, ये जो इधर बराबर में एस0जे0पी0 के हमारे भाई बैठे हैं, बार बार यह कहते हैं कि सरकार ने हरिजनों के लिये यह कर दिया, वह कर दिया। स्पीकर साहब, जनता जनार्दन है जनता भी ाा है। अच्छे काम ये सरकार करेगी तो लोग भााबासी देंगे। अगर यह गलत रास्ते पर चलेगी तो कल को इन्हीं की जगह पर दूसरी सरकार आ जायेगी। इसलिये सब तरह की रिस्पान्सीबिलिटी सरकार को ओन भी करनी चाहिये। इसलिये सब तरह की रिस्पान्सीबिलिटी सरकार को ओन भी करनी चाहिए। किसी की बात को टालना नहीं चाहिये क्योंकि

यह सत्ता पक्षा की डयूटी है। जिसकी गलती हो, उसको सजा दे ताकि आगे से अच्छे काम हो।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं कृशि से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, कुछ सल पहले रेवेन्यू पास बुक्स किसानों के लिये बनीं। इनके लिये पांच पांच रूपये किसानों से लिये गये। मैं कहता हूं कि करप ान में कम से कम 30 परसैंट राहत मिल सकती है। यदि किसानों की पास बुक्स को बैंक पास बुक्स की तरह बना दिया जाए। ऐसा करने से जमींदारों को किसी वकील के पास नहीं जाना पडेगा। इसके अलावा, एक और मुसीबत की बात किसानों के साथ जुडी हुई है। अगर उसके खेत में हजार मन कपास पैदा हो जाए, उसकी लिमिट नहीं बढेगी ओर अगर वही कपास किसी फैक्टरी में चली जाए तो उसकी 10 लाख 5लाख की लिमिट बन जाएगी। मेरा कहना यह है कि होलडिंग के हिसाब से लिमिट बननी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर किसान की रेवेन्यू पास बुक को, बैंक पास बुक की तरह से बना दिया जाए तो जो पटवारी किसान की खाल नोचता है, उससे छुटकारा हो सकता है किसान लीगल ऐडवाईजर से भी बच जाएगा और उसे राहत भी मिल जाएगी। अगर रेवन्यू पास बुक, बैंक पास बुक्स की तरह हो जाएगी तो किसान जो चीज बेचेगा, उसमें दर्ज हो जाएगी, जो चीज खरीदेगा उसमें दर्ज हो जाएगी इससे उसे तरह तरह की मुसीबातें से छुटकारा मिल जाएगा और बाकायदा किसान को राहत मिलेगी। इसके इलावा, खेती की जमीन पर बहुत

जयादा भार आ गया है, कृशि पर सारा बोझ टिक गया है। अब कृशि की 18 एकड की लिमिट है। पिछले दिनों यह होड लग गई कि कहीं यह लिमिट और न घट जाए। ताऊ के राज में यह नारा लग गया कि केवल 5 एकड जमीन होगी। वकीलों की चांदी बना दी और सबने बेनामी ट्रांजैक ान करवा लिये। दो–दो, तीन तीन एकड की होलडिंग बन गई। अब आप बताओ कि हरिजन काम करने के लिये कहां जाएगा ? हरिजन के रोजगार का तो किसान के कन्धों पर दारोमदार है। अगर किसान सुखी तो हरिजन दुखी। अगर किसान दुखी है तो हरिजन दुखी। दोनों का आपस में बहुत तालमेल है। हरिजन तो किसान के खेतों में ही काम करता है। अगर किसान की औलाद ही उसके अपने खेतों में काम करने की लिये काफी है तो हरिजन कहां समाएगा ? इसलिये मैं कहता हूं कि ऐग्रोबेसड इंडस्ट्रीज जो आप लगाएं, इससे जमीन पर बोझ कम होगा, जमीन की तरफ लोग कम दौडेंगे और दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ लोगों का आकर्शण हो जाएगा और उद्योग धन्धों में वे अपना मन लगाएंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक लाख रूपया नै ानल ि ाडयूल्ड कास्टस कार्पोरे ान से लोन लेकर, जिसमें 60 प्रति ात लोन कार्पोरे ान देती है, 35 प्रति ात हरिजन कल्याण निगम देती है और 5 प्रति ात मार्जिन मनी होती है। स्पीकर साहब, मेरे हिसाब से हमारे पास सैंटर का भोयर आ जाता है लेकिन स्टेट का भोयर कन्ट्रीब्यूट नहीं होता। मुख्य मंत्री जी ने क्वै चन आवर में स्वयं माना कि जमीन के भाव बहुत बढ गए हैं,

एक लाख या डेढ लाख रूपए किल्ले से कम भाव नहीं है। 70000 रूपए किल्ला तो टिब्बों की जमीन का रेट हो गया है। तो कार्पोरे ान से कह कर यह भोयर ज्यादा बढाएं। आप कार्पोरे ान से ज्यादा पैसा लें। हरिजनों को आपने का तकारी करने के लिए जमीन जोतने के लिए और पानी देने के लिए तथा भैंस पालने के लिए 27000 रूपया दिया है। स्पीकर साहब, 27000 रूपए में दो तीन भैंसें तो आ जाएंगी लेकिन उनका रख रखाव कहां से होगा। मैं चाहता हूं कि इसको वाएबल यूनिट बनाएं ताकि ि ाडयूल्ड कास्टस जमीन पर टिक सकें। एजूके ान के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि नकल रूकी है लेकिन उस हद तक नहीं रूकी जितनी रूकनी चाहिए थी। मैं यह कहता हूं कि ऐसा होने से जो हार्ड वर्किंगे स्टूडैंटस हैं वे क्या करेंगे। नकल करने वालों को तो बाहर से पर्ची भेज दी जाती है और वे अंदर नकल कर लेते हैं तथा 98 प्रति ात मार्कस उनको मिल जाते हैं। ऐसा होने से हार्ड वर्किंग स्टूडैंअस को आपत्ति है। मैं मानता हूं कि एजूके ान कन्क्रैंट सब्जैक्ट है लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कार्यवाही करने के लिए राश्ट्रपति जी से इजाजत लेनी चाहिए। वैसे ऐसा बिल इस सै ान में आना चाहिए था जैसा यू0पी0 सरकार ने पास किया है। इस सै ान में अगर किसी वजह से नहीं लाया जा सकता तो अगले सै ान में लाना चाहिए। वर्श 1986–87 में ि ाक्षा मंत्री जी ने माना कि कंवारी गांव में 10 लाख 41 हजार रूपया लगा करके वहां पर हाई स्कूल तो पहले से ही था, दस जमा दो का स्कूल बनाने के लिए बिल्डिंग बनायी थी। इसी तरह से जमालपुर में।

इन दोनों स्कूलों को बिल्डिंगों को 10+2 नहीं किया गया। मैं सरकार से यह उम्मीद रखता हूं कि उस एरिया की स्थिति को समझते हुए यह भीघ्र करवाया जाए। अब बच्चों को पढने के लिए भिवानी या हिसार जाना पडता है। मुख्य मंत्री जी आपने सिवानी सब डिवीजन को हिसार में मिला लिया है लेकिन इलैक्ट्रिसिटी के हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल भिवानी मे ंहै। उसकी कंसोलीडे ान भी आज तक नहीं हुई। वहां पर टिब्बे हैं और जमींदारों की आपस में लडाई होती है। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कंसोलीडे ान जल्दी करवानी चाहिए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातों का मैं जवाब दूंगा और बाकी की बातों का जवाब वित्त मंत्री जी देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे बहुत अफसोस के साथ कहनी पडी है कि सजपा के भाई जान बूझ कर हाउस में नहीं बैठते हैं। इसलिए नहीं बैठते हैं कि उनके कारनामें ही ऐसे हैं जिनको अपने सामने वे सुन नहीं सकते। हम उनको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि उनके राज में क्या हालात थे, किस तरह का माहौल था और क्या तरीका था उनके काम करने का। जो बात वे खुद करते थे, वे समझते हैं कि यह सरकार भी वैसे ही करती होगी। अध्यक्ष महोदय, जो इन्सान जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। यहांपर दूसरी पार्टियां हैं, हरियाणा विकास पार्टी है, जनता दल है, बी0जे0पी0 है, सभी हैं।

श्री धर्मपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम भी नहीं दिया गया। जब मैं बोलने के लिए खडा हुआ तो आपने कह दिया कि बैठ जाओ।

श्री अध्यक्षः कल आपको बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि बाकी सभी पार्टियों के माननीय सदस्य यहां हाउस में बैठे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि क्रिटिसिजम होना चाहिए लेकिन वह क्रिटिसिजम हैल्दी होना चाहिए। सरकार में यदि कोई कमी है तो उसके बारे में कहना चाहिए और यदि कहीं पर कोई नुक्स हो तो वह बताना चाहिए। उन्होंने अपने इलाके की कोई बात नहीं कही। न उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर पे ा हुए धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने इलाके की कोई बात कही और न बजट पर बोलते हुए कोई बात कही। उनको लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। लोगों को उनसे बडी भारी उम्मीद हैं लेकिन उन्होंने अपने इलाके के लोगों की कोई बात यहां नहीं रखी। सिवाय उन्होंने बेबुनियाद और गलत बातें कहने के कोई दूसरी बात नहीं कही। यदि उनकी कोई बात ठोस होती तो वह समझ में आ सकती थी लेकिन बडे दु:ख के साथ कहना पडता है और मैं परम पिता परमात्मा से कहना चाहूंगा कि परमात्मा उनको सदबुद्धि दे नहीं तो उनको आगे के लिए बडी

मुि कल हो जाएगी। इस समय जितने चुनकर आए हैं उतने भी नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने कुछ बातें कहीं। इन्होंने एक बात तो यह कही कि फाइनैंि ायल कमि नर्ज ओर कमि ानर्ज बहुज ज्याद बैठाए हुए हैं और उनके काम का वितरण ठीक नहीं। उनसे जो काम लिया जाता है उसका बंटवारा ठीक नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी डयूटी यहां भी लगा रखी है और दिल्ली में भी लगा रखी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदे ा में 233 आई0ए0एस0 का काडर था जो घट कर 211 रह गया है। हमने भारत सरकार से बातचीत करके आई0ए0एस0 अधिकारियों का काडर कम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय 211 आई0ए0एस0 अधिकारी हरियाणा प्रदे ा में हैं और 215 आई0ए0एस0 के अधिकारियों में से 40 आई0ए0एस0 अधिकारी सैंटर में आप डैपुटे ान होने चाहिए जबकि केवल 33 हैं। हमने सैंटर गवर्नमैंट से यह कहा कि 7 आई0ए0एस0 अधिकारी और सैंटर में डैपुटे ान पर होने चाहिएं जो कि जरूरी था। हमने 17 आई0ए0एस0 अधिकारियों के नाम भेज भी रखे हैं। ज्यों ही भारत सरकार फैसला करेगी हम उसको अमल करेंगे। जहां तक दोनों जगह एक ही अधिकारी को काम देने का सवाल है। यह बात उस अधिकारी के काम करने की कैपेसिटी पर डिपैंड करती है। जो भी अधिकारी अपेन काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से जितना काम कर सकता है उसके हिसाब से उस अधिकारी को काम दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात चौधरी बंसी लाल जी ने कह दी

कि एक मेज से दूसरी मेज पर फाईल बगैर पैसे दिए नहीं जाती। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह बात पिछली सरकार के चार साल में हुआ करती थी, कहीं आपको उस सरकार की बात तो याद नहीं आ गई है। आप इस सरकार की एक भी ऐसी कोई ठोस बात बता दें लेकिन कोई बात ऐसे ही हवा में कहने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप समुद्र में मधानी चलाओ तो कोइ कात जमती नहीं है। आप हमें एक ही ऐसी बात बता दें कि फलां टेबल पर फलां आफिसर, फलां एम0एल0ए0 फलां मुत्री या मुख्यमंत्री ने किसी काम के लिए किसी से पैसे लिए हों तो हम मान जाएंगे और बात समझ में आ जाएगी लेकिन आप वह बात कहें जो बात मानने वाली हो। आपको पिछली सरकार की बातें याद आ गई होंगी। यह बात हमारी समझ में आ सकती है लेकिन इस सरकार के समय में ऐसे गलत काम नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने ला एण्ड आर्डर के बारे में कह दी कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ला एण्ड आर्डर जितना भाानदार आज हरियाणा प्रदे ा का है उतना भाानदारी किसी भी प्रदे ा का नहीं है। मैं पंजाब के बारे में बता देता हूं। मैं पंजाब के मुख्य मंत्री, पंजाब के एडमिनिस्ट्रे ान और खास करके के0पी0एस0 गिल को मुबारिकवाद देता हूं कि उन्होंने आज पंजाब के हालत बहुत बेहतर किए हैं और पंजाब के माहौल को ठीक किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बहादुरी और मजबूती के साथ पंजाब के 10 साल से जो हालात बिगडे हुएथे उनको ठीक किया।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर पडोसी के घर में आग लगी हो तो उसकी गर्म हवा पडोस के घर में भी जरूर आएगी। लेकिन कितनी भयंकर आग थी उस आग से भी हमारे एडमिनिस्ट्रे ान ने, हमारी पुलिस फोर्स ने सबको बचा कर रखा। इसके लिए हमारी फोर्स भी बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, यू0पी0 और उससे आगे भी कोई ऐसा प्रदे ा नहीं है जहां पर उग्रवादियों ने ज्यादा से ज्यादा वारदात न की हो।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय 20 मिनट के लिए बढा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 20 मिनट और बढाया जाता है।

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः मेरे कहने का मतलब यह है कि बडा भाानदार ला एण्ड आर्डर हरियाणा का रहा है। एक बात इन्होंने यह कही कि डी0जी0पी0 पर पुलिस का वि वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे डी0जी0पी0 बडे भाानदार अधिकारी हैं। वे निहायत ईमानदार और मजबूत आदमी हैं। हमारी पुलिस फोर्स ने

डट कर काम किया है। जब चौधरी बंसी लाल जी ने उनको हिसार में एस0पी0 लगा रखा था तो उस समय इनकी बडी तारीफ किया करते थे।

श्री बंसी लालः आप क्या करते थे, वह भी बता दें ?

चौधरी भजन लालः मेरे जिले में लगा रखा था आपको भी याद होगा और मैं उस समय भी बहुत तारीफ किया करता था कि इससे बढिया कोई आदमी नहीं है। ये भी बडी तारीफ किया करते थे। पता नहीं इनकी थोडी से कोई नाराजगी हो जाये तो उसका ये पूरा ईलाज करते हैं। (विघ्न) मैं भी कहता था कि बढिया आदमी हैं, मैंने कभी बुरा नहीं कहा। मेरे जिले में लगा हुआ था। अगर ये बुरे होते तो वह दोनों के लिए एक ही बात हुआ करती थी। (हंसी) फिर उनको वहां रखते कैसे, अगर बुरे होते ? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने कभी बुरा नहीं कहा। (विघ्न) सारी ऐडमिनिस्ट्रे ान और सारी पुलिस फोर्स का पूरा फेथ डी0जी0पी0 पर है और अगर फेथ न हो तो कोई कैसे कमान्ड कर सकता है और अगर कमांड ठीक नहीं हो तो प्रदे ा में कैसे अमन हो सकता है ? इन्होंने बहुत भाानदार कमांड की है। हमारी सारी पुलिस फोर्स बडी भाानदार है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी एक बात दोहरा देते हैं कि पुलिस की ऐसोसिए ान बननी चाहिए। मेहरबानी करके कभी तो इस बात को भूलो और अपने जमाने को भी याद करो।

श्री बंसी लालः 14 स्टेटों में पुलिस वालों की ऐसोसिए ान है।

चौधरी भजन लालः जब आप चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त भी 12 स्टेटों में पुलिस ऐसोसिए ान हुआ करती थी, तब आपने क्यों नहीं बनाई ? आपने पुलिस की तो क्या, टीचरों की एसोसिए ान नहीं बनने दी, आज पुलिस की बात करते हो। पुलिस और फौज में अगर यूनियनें होंगी तो इस मुल्क की कभी एकता कायम नहीं रहेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दे ा के हित में होती हैं और जिनको ठीक रखना होता है। हमारा पुलिस पर पूरा फेथ है। सिपाहियों को या किन्हीं अधिकारियों की कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो उनके लिए हर समय सरकार के दरवाजे खुले हैं। एक सिपाही तक भी भजन लाल से मिल सकता है। यह बंसी लाल नहीं है कि अगर डी0सी0 भी मिलने आ जाये तो कहे कि मेरी इजाजत के बगैर कैसे आया है, सस्पैंड कर दो। भजन लाल ऐसा नहीं कहता। यह आपके जमाने की बात है। मुझे तो सिपाही भी मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने फरीदाबाद की माईन्ज में लीकेज के बारे में कही है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि यदि वहां पर कोई लीकेज है और किसी का कसूर है तो हम उसको पूरा चैक करेंगे और सख्ती करेंगे तथा दोशी के खिलाफ एक ान लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक चौधरी बंसी लाल जी ने यह कहा कि भजन लाल के साहबजादे पुलिस के काम में दखल देते हैं और पुलिस की भर्ती के लिए घर पर ही नाप तोल करते हैं। चौधरी बंसी लाल जी इस बारे में मैं आपको और क्या कहूं, साहबजादा तो इस हरियाणा में एक ही है और वह है सुरेन्द्र सिंह, चौधरी बंसीलाल का लडका। (विघ्न) और कोई साहबजादा है ही नहीं। इस बारे में मुझे ज्यादा कहने की आव यकता नहीं, इसी बात से सारे लोग समझ जाएंगे। मेरे लडकों का कही ंपर कोई दखल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सियासी आदमी हैं। चौधरी बंसी लाल जी आपको तो कभी कभी सप्पा लग जाता है, कभी कभी लोग आपकी नाक भी रगडवा देते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से हमारा हिसाब किताब हमेशा ही ठीक रहा है। मैं आज तक किसी इलैक ान में हारा नहीं हूं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि पुलिस की भर्ती में कोई दखल मेरे लडकों का नहीं है। स्पीकर साहब, जब पुलिस की भर्ती होती है तो सियासी आदमी के घर पर सैंकडों आदमी जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के यूथ, कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी हैं। अगर किसी के पास कोई आ जाए और हरेक आदमी को सियासी आदमी नौकरी दे नहीं सकता, वह उसको कैसे कहेगा कि तू फिट नहीं है। (विघ्न) जब लगा नहीं सकता तो वह यही कहेगा कि फीता पडा है, नाप ले। अगर कोई नाप भी दे तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई जिला ऐसा नहीं जिस हल्के से कोई पुलिस की भर्ती न हो, यह कोई बात नहीं। (विघ्न) चौधरी साहब,

आप अपने जमाने की सारी बातें भूल जाते हैं। एक आपने पुलिस में बी–1 ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया। (विघ्न)

साथी लहरी सिंहः यमुना नगर, कुरूक्षेत्र, अम्बाला और करनाल जिलों में भी भर्ती का ख्याल रखिए।

चौधरी भजन लालः आपको भी कल बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि डी0आई0जी0, एस0पी0, आई0जी0 के साथ पुलिस के जो अर्दली हैं, उनको बी–1 में नम्बर दिये जाते हैं, बाकियों को नहीं दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अर्दली को भी अधिकार है और दूसरों को भी अधिकार है, बाकायदा उनका टैस्ट होता है।

श्री बंसी लालः एस0पी0 अगर एक साल का सर्टिफिकेट दे दे कि उसने बहुत अच्छा काम किय है तो टैस्ट का एक नम्बर काउंट होता है। डी0आई0जी0 का सर्टिफिकेट हो तो दो नम्बर काउंट होते हैं और यदि आई0जी0 का सर्टिफिकेट हो तो 3 नम्बर काउंट होते हैं। स्पीकर साहब, ये नम्बर बिल्कुल काट देने चाहिएं क्योंकि जो व्यक्ति फील्ड में सम्मनों की तामील करवाता फिरता है, वह कहां जाएगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ हदि तक ठीक हो सकती है। मैं मानता हूं हो सकता है जो साथ रहेगा और ठीक काम करेगा, थोडा बहुत एक आध नम्बर उसको मिल सकता है, लेकिन आप अपने जमाने को क्यों भूल जाते हैं ? जो

आपके साथ थे, आपने तो क्लर्क से सीधे एच0सी0एस0 बना रखे हैं। डी0आई0जी0, आई0जी0 और एस0पी0 का क्या दोश है, आप जरा अपने मामले को भी देखें, उस बारे में आप क्या कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे इन्होंने कहा था कि 35 करोड रूपए उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार से आ गया है, वह पैसा अभी केन्द्र सरकार से आया नहीं है, हमने पैसा मांग रखा है, जब मिलेगा तो इनको बता देंगे। यह पैसा उसी काम में लगाएंगे जिस काम के लिए लेंगे। (विघ्न)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि मैंने सुना है कि 35 करोड रूपया आया है। ये यह न कहें कि मैंने यह कहा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने यह पैसा मांगा है। पुलिस फोर्स को पूरी जीपें हथियार और दूसरा सामान दिया हुआ है ताकि वे अपने काम में किसी तरह की कमी न आने दें और काम में कोई कोताही न होने दें। पुलिस का मनोबल हम किसी भी तरह से कम नहीं होने देना चाहते। इन्होंने नीमड़ी गांव और रिवासा गांव का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि रिवासा गांव में लडकी के साथ बलात्कार के संबंध में मुकद्दमा नंबर 46 दिनांक 15–2–1993 जेरे दफा 376 दर्ज हो चुका है। नरे ा, पुत्र उग्रसेन राजपूत को सुनीता, पुत्री चन्द्र भान धाणक, उम्र 12 साल के साथ बलात्कार करने पर तिथि 17–2–1993 को गिरफतार किया जा चुका है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि यह बलात्कार किस दिन हुआ और मैडिकल किस दिन हुआ ?

चौधरी भजन लालः मैंने बताया है कि 15 तारीख को केस दर्ज हुआ और दो दिन के बाद ही 17 तारीख को उसको गिरफतार कर लिया गया।

श्री अमर सिंहः प्लेस औफ अक्रैंस कहां हुआ और उसके बाद पुलिस ने पर्चा कब दर्ज किया ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास ज्यों ही कोई ऐप्लीके ान आती है, एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाती है, देरी का सवाल नहीं है। ज्यों ही उनके पास ऐप्लीके ान आई, 15 तारीख को केस दर्ज हो गया। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि रेप कौन सी डेट को हुआ। यह डेट इस समय मेरे पास नहीं है अगर आप जानना चाहेंगे तो हम कल आपको बता देंगे।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हमारा प्र न यह था कि डाक्टर और पुलिस ने उसको एवायड किया। ऐसे मामलों में टाईम का बडा खयाल होता है, क्योंकि केस जूडीि ायरी में जाता है। इसमें टाईम का पूरा ध्यान होना चाहिए। 2–3 घण्टे बाद ही मैडीकल हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट में ऐसे फैसले हुए हैं कि अगर 5 घण्टे डिले हो गई तो फिर कानून में फर्क पड जाता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप भी काबिल और पढे लिखे हैं और भाई अमर सिंह भी वकील हैं। यह टाईम

बाउंड प्रोग्राम कैसे हो सकता है ? यह प्रोग्राम रोज थोडे ही चलता है ? इत्तफाक से कोई वाकया हो जाए, उसके ऊपर ऐक ान लेने की बात है। (विघ्न) ऐक ान लेने में सरकार किसी तरह की डिले नहीं करती, कार्यवाही तो बाद में ही होगी। बाकायदा डाक्टरी मुआयना करवाया जाता है, फिर उसकी ऐप्लीके ान होती है कि इस लडकी के साथ कहां तक कौन सी बात हुई है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि दफा 376 के केस में डायरैक्ट मैडीकल नहीं होता। पहले पुलिस रिपोर्ट लिखती है, फिर पुलिस उसको मैडीकल के लिए लेकर जाती है। एम0एल0ए0 की इन्टरफियरेंस से यह पर्चा दर्ज हुआ।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ और दो दिन के अन्दर अन्दर 17 तारीख को गिरफतारी हो गई। दूसरे, इन्होंने नीमड़ी गांव की लडकी के बारे में कहा। नीमडी गांव की औरत ने अपनी बच्ची को पहले कुंए में डाल दिया और फिर बाद में खुद कुंए में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस बारे जहां तक पुलिस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से वह आत्महत्या का केस पाया गया है। इसके अलावा, और कोई ि ाकायत नहीं आई है। अगर कोई ि ाकायत होगी तो जांच करवा ली जाएगी।

श्री बंसी लालः आज से करीब 7–8 दिन पहले, यहांपर मुझे भी कुछ लोग मिले थे और बाद में वे आपके डी0जी0पी0 को भी मिले थे। उन्होंने कहा कि या तो हमें इन्साफ दो, वरना हम धरना देंगे।

चौधरी भजन लालः बंसी लाल जी, आपके पास चाहे उन्होंने कुछ भी लिख कर दिया हो, वे हमें दे दें और कल ही हम केस दर्ज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं।

श्री धर्मपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जैसे ही लडकी के मां बाप को खबर मिली तो वे सालावास थाने में गए। उन्होंने वहां के एस0एच0ओ0 को इस बारे में कहा परन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की। दो दिन बाद आठ गांवों की पंचायत बैठी और लोगों के 15 ट्रैक्टर भरकर पुलिस स्टे ान गए और उन्होंने थाने का घेराव किया। उसके बाद एस0एच0ओ0 ने एफ0आई0आर0 दर्ज करी है। उसकी ला ा उसके घर से 15 कदम की दूरी पर मिली। दो दिन तक उसको कुंए से निकाला नहीं गया। साल्हावास के एम0ए0ए0 जिले सिंह ने जब इन्टरफियर किया तब जाकर ला ा निकलवाई गई। रोहतक में पोस्टमार्टम करवाया गया। ऐसा कहते हैं कि उस एस0एच0ओ0 ने 65 हजार रूपए लेकर उस केस को खराब कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, साल्हावास के पास ढाना गांव है। वह उसके पास के गांव चिडिया की लडकी थी। उसके ससुर और साडु ने उसके साथ रेप

किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। एस0एच0ओ0 ने उस केस को रफा दफा कर दिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, धर्मपाल जी ने जो बात कही है, ऐसी बात नहीं है। वह बात आत्म हत्या की थी, मां बेटी ने आत्महत्या की है। पहले तो उसने अपनी बेटी को कुंए में फैंक दिया और बाद में अपने आप छलांग लगा दी।

श्री धर्मपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या भी कोई राजी खु ाी नहीं करता।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारे पास किसी की ि ाकातय नहीं है। अब आप ि ाकायत कर रहे हैं तो कार्यवाही हो जाएगी। आप माननीय सदस्य हैं, हम आपके इतना कहने पर ही जांच करवाएंगे। साथ ही चौधरी बंसी लाल जी ने, हवलदार तारा चन्द के बारे में बडी चिन्ता व्यक्त की है कि उसके बारे में क्या किया गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि तारा चन्द के पुत्र राजे वर कुमार को रोजगार विभाग में क्लर्क भर्ती कर दिया गया है क्योंकि वह पुलिस विभाग में भर्ती नहीं होना चाहता था। उसकी भर्ती 8–11–1991 को गुहलाचिका रोजगार कार्यालय में हुई है।

श्री बंसी लालः उसको कोई एवार्ड दिया है कि उसने इतनी बहादुरी का काम किया है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले इस बारे में नहीं पूछा था। उसके बारे में जो कुछ भी हुआ है वह हम इनको कल बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए, अगर कोई मारा जाता है तो उसको एवार्ड बगैरह देने के लिए हमने बाकायदा नार्म्ज बनाए हुए हैं। एक इन्हौंने भिवानी के एस0डी0 हाई स्कूल को जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, उस सनातन धर्म हाई स्कूल में 1300 से 1350 के करीब छात्र पढते हैं, जिसे कलकत्ता के एक ट्रस्ट ने बनवाया था और उस पर कुछ व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। उस स्कूल की प्रबंध समिति ने पुराने अध्यापकों को सेवा से निकाल कर नए अध्यापक कम वेतन पर रख लिये हैं। उन्होंने ि ाक्षा विभाग को लिख कर दिया है कि उन्हें सरकारी ग्रांट की आव यकता नहीं है। बंसी लाल जी ने यह कहा है। इस विद्यालय के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस स्कूल का कब्जा ट्रस्ट वालों से समिति को दिलवाया जाए। इसमें टिप्पणी यह है कि सनातन धर्म हाई स्कूल भिवानी की प्रबन्ध समिति का झगडा जिला स्तर के न्यायालय में विचारधीन है। इस संबंध में 3 विभिन्न मुकद्दमें भिवानी की कोर्ट में चल रहे हैं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जानी उचित नहीं है क्योंकि यह मामला सबजुडिस है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो पुराने टीचर्ज वहां पर 15–15, 20–20 साल

से दो दो, तीन तीन हजार रूपए तनख्वाह ले रहे थे, वे कोर्ट में गए हुए हैं। There is no dispute between two managements. वहां पर मनेजमैंट का कोई झगडा नहीं है, कोई मामला सबजुडिस नहीं है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वह प्राईवेट कालेज है, सरकारी कालेज नहीं है। हम प्राईवेट कालेज को 95 परसैंट ग्रांट देते हैं लेकिन वह ग्रांट हमने इसलिए बंद कर रखी है क्योंकि वहां पर नाजायज आदमी ने उस पर कब्जा किया हुआ था, कोर्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं ?

श्री अमर सिंहः वह स्कूल मैनेजमैंट को हैंड ओवर करने के लिए सै ान जज ने फैसला दिया हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो हम कोर्ट के फैसले के अनुसार दे देंगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, अगर ये कोर्ट का फैसला ही इम्पलीमैंट कर दें तो वही काफी है।

चौधरी भजन लालः ठीक है, हम इम्पलीमैंट करा देंगे। इसके अलावा, इन्होंने हवलदार का जिक्र किया कि उसकी मृत्यु हमारे समय में हुई है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु हमारे समय में नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत 1989 में

हुई। अध्यक्ष महोदय, कल ओम प्रका ा चौटाला ने भिवानी में क्या कहा भाायद इनका पता नहीं हें ये पता कर लें कि क्या कहा ?

श्री बंसी लालः उन्होंने जो भी कहा है, लेकिन आप दोनों तो एक ही हो।

चौधरी भजन लालः आप उनके साथ हैं या मैं उनके साथ हूं, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। (विघ्न) ठीक है, कल बता देंगें कि उन्होंने क्या कहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे समय में उस हवलदार की मौत नहीं हुई। हमारे समय में तो उसके लडकी की नौकरी लगी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इन्होंने ला एण्ड आर्डर के बारे में कहा। इसके बारे में तो गुप्ता जी बता चुके हैं। इसी तरह से राम रतन जी ने नहरों के बारे में कहा। इसी तरह से नारनौल में अनाज मंडी की बात है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि ि ाडयूल्ड कास्टस का जो बैकलाग है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं इसी तरह से एच0सी0एस0 की भी ि ाडयूल्ड कास्टस के लोगों में से भर्ती होनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः ठीक है, यह भी अभी बता देंगे। इसके अलावा, राम बिलास भार्मा जी ने पुलिस के बारे में कहा कि पुलिस का मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने हमे ाा पुलिस का मनोबल ऊंचा रखा है। अगर

पुलिस के खिलाफ कहीं पर कार्यवाही कर दी गयी है तो हम उसका पता लगायेंगे। इसी तरह से इन्होंने नगरपालिका के बारे में जिक्र किया कि यमुना नगर और रोहतक में यह हो रहा है, वह हो रहा है। यह बात तो ये भी जानते हैं कि यह प्रजातंत्र है, जिसका बहुमत होगा और जिसको लोग चाहेंगे, वही रहेंगा। अगर बहुमत नहीं होगा तो हटना ही पडेगा। सरकार कोई भी गलत काम नहीं करती जिससे आपकी पार्टी को कोई ि ाकायत हो। इसके अलावा, इन्होंने कहा कि यह गांव उस ब्लाक में कर दिया, उस तहसील में कर दिया, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम भी यही चाहते हैं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट एक ही होना चाहिए। इसके लिए अब फैसला भी हो चुका है लेकिन फिर भी इनको कहीं पर ऐसी ि ाकायत है तो हमें यह लिख कर दे दें, हम ठीक करा देंगे। (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी अभी फरमाया कि लोग जिसे चाहते हैं और जो बहुमत में है, वही रहेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके एम0एल0ए0 और मंत्री ही उनके काम को ठीक तरह से नहीं चलने दे रहे हैं। जैसे मैंने अम्बाला छावनी का जिक्र किया, अम्बाला सिटी का जिक्र किया, वहां की नगरपालिका में कांग्रेस के प्रधान हैं और हमारी पार्टी के उप प्रधान हैं। वहां पर भी ये लोग उसकी प्रोसिडिंग को चलने नहीं दे रहे हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसको हम देख लेंगे। हम आपको ऐसा कहने का मौका नहीं लगने देंगें।

श्री पीर चन्दः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा वह सवाल मैंने कल भी पूछा था लेकिन कल ये हाउस में नहीं थे, अपने औफिस में बैठे होंगे तो भी सुनते रहे होंगे। मैंने सवाल किया था कि रतिया का थानेदार और फतेहाबाद के डी0एस0पी0 दोनौं ने लूट मचा रखी है। हमने ग्रिवेसिजि कमेटी को भी उस बारे में इतलाह दी है। बबैनपुर के एक आदमी को रतिया थाने के थानेदार उठा कर ले गए, उसको रतिया में रखा और फतेहाबाद सी0आई0ए0 में भी रखा। (ाोर) सी0एम0 साहब आप जवाब दो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। उसको फतेहाबाद में भी 5–6 दिन तक रखा, वहां पर सी0आई0ए0 स्टाफ में भी रहा, वहां से एक औरत उसको छुडा कर ले आई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की करप ान करने के लिए वहां पर हाकिम बैठे हैं ?

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः क्या हाउस का टाइम चार बजे तक बढा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है, ठीक है

श्री अध्यक्षः हाउस का टाइम चार बजे तक बढाया जाता है।

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी ने कुछ बातें और भी कहीं हैं। भार्मा जी बहुत बढिया आदमी हैं। कल मेरी समझ में नहीं आया कि इनके एक हाथ में पटटी बंधी थी और आज दूसरे हाथ में है। पता नहीं कौन सा हाथ ठीक है, कौन सा गलत है।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, ये मेरे जख्मों का मजाक न करैं। यह गुमानी, लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसा कर ब्रिटि ार्स ने भी की थी। मैंने कभी अपने जख्मों का कंपनसे ान नहीं मांगा और न ही मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। भगवान करे, आपको इस तरह का मौका न आए। वैसे तो आप इस तरह की बात की नौबत हीं नहीं आने देंगे, भगवान आप पर राजी रहें, ये लाठियां हमको ही मुबारक हों। न मैंने आपसे सर्टिफिकेट मांगा न आपकी कांग्रेस से सर्टिफिकेट मांगा। (ाोर एवं व्यवधान) यह जो बात है उसकी आपने कारगुजारी की, उसकी हमने कभी सदन में चर्चा नहीं की। स्पीकर सर, मैंने इनसे प्रमाण नहीं मांगा था। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी, आप मजाक की बात को सीरियस न लें।

प्रो0 राम बिलास भार्माः यह मजाक की बात नहीं है, क्या इसको भी आप मजाक कहते हैं ? मजाक के लिए और विशय बहुत हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप बैठिए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, दिल्ली की जो वारदात हुई है, इस पर हिन्दुस्तान के लोगों का सर झुका है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी, आप इतने सीरियस क्यों हो गए ? (ाोर) मैंने तो थोडा सा माहौल ठीक करने के लिए कहा था। आप लाठियों की बात कहते हैं, लाठियां खाकर, गोलियां खाकर, फांसी के फंदे को जिन लोगों ने चूमा था, उन्होंने दे ा को आजाद कराने के लिए चूमा था, दे ा को बरबाद करने के लिए नहीं चूमा था। वे दे ा के बरबाद नहीं करना चाहते थे। मैंने इस नजरिए से बात कही थी कि आप टैंस न हों। अगर आपको मेरी बात महसूस हुई है तो मैं वापिस ले लेता हूं, लेकिन थोडी बहुत बात तो हंसी की भी कहनी चाहिए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः आप मार का मजाब उडा लें, आप हमारे ऊपर लाठियों का मजाब उडा लें और आप हमारे जख्मों का मजाक उठा लें, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

चौधरी भजन लालः ये जख्म दे ा को बचाने के लिए नहीं हुए हैं, ये तो दे ा को तोडने के लिए हुए हैं। सरदार भगत

सिंह ने जो लाठियां खाईं थीं, या लाला लाजपत राय ने लाठिया खाईं थीं, वे दे ा की आजादी के लिए खाईं थी। स्पीकर साहब, अमर सिंह ने हरिजनों का बैकलोग पूरा करने के लिए कहा है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी बैकलोग पूरा करेंगे। एक बात इन्होंने प्लाटों के बारे में कही। हम इस बारे में दुबारा सर्वे करवा रहे हैं और जिनको प्लाट नहीं मिले हैं, उनको प्लाट देंगे। स्पीकर साहब, पास बुक की बात इन्होंने कही। एग्रीकल्चर पालिसी पर दिल्ली में मीटिंग हुई थी। श्री हरपाल सिंह ने वहां पर बहुत जोरदार भाब्दों में इस बात की वकालत की। स्पीकर साहब, जब मैं सैंटर में ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने यह बात चलाई थी और उस समय एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के तीन मैम्बर थे। एक मैं था, एक प्राईम मिनिस्टर और तीसरे फाईनैंस मिनिस्टर थे। फसल बीमा योजना के बारे में भी प्राईम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जिक्र किया और कहा कि चौधरी भजनलाल के समय यह स्कीम चालू की गई थी। हमने इसके लिए जिले को यूनिट नहीं माना, ब्लौक को भी यूनिट नहीं माना। मैंने कहा था कि गांव यूनिट होना चाहिए। पासबुक का भी वहां पर जिक्र आया था। उस पास बुक में जमीनों का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें जमीनों के खरीदने बेचने, कर्जा लेने और कर्जा उतारने आदि का जिक्र होगा ताकि लोगों को बार बार पटवार के दरवाजे पर न जाना पड़े।

स्पीकर साहब, चौधरी पीर चन्द ने रतिया का जिक्र किया। इनको रतिया की बहुत चिन्ता है। ठीक है यइ इनका हल्का है, लेकिन रतिया मेरी ससुराल भी है। इन्होंने फतेहाबाद के एस0एच0ओ0 का जिक्र किया। पीरचन्द जी, हमने उसको बदल दिया है। रतिया के एस0एच0ओ0 के बारे में कहा कि वह करप्ट है। हम जांच करवा लेंगे, इस बात में कोई सच्चाई मिलेगी तो उसको लाइन हाजिर कर देंगे, उसके खिलाफ ऐक ान लेंगे और कार्यवाही करेंगे।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक क्वै चन था कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाढर पर एस0पी0 और डी0सी0 हरिजन नहीं लगाए हुए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः हरिजन मैम्बर हैं, इनको तो दूसरों की बात करनी चाहिए। आप लोग केवल हरिजनों की वोट से बनकर नहीं आते, सब लोगों को साथ लेकर चलना पडेगा।

साथी लहरी सिंहः हरियाणा के अन्दर एक भी हरिजन एस0पी0 नहीं है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, गरीब आदमी के साथ और हरिजन के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। आपको जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, यह कहना चाहिए कि अच्छे आदमी लगने चाहिए। सारे हरिजन भी अच्छे नहीं हैं और नौन हरिजन भी सब बुरे नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले बजट पर चर्चा हुई और हमारे सारे विरोधी पक्ष और ट्रेजरी बैंचिज के भाईयों ने उस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट पर चर्चा भुरू हुई थी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने खुल कर तथा विस्तार से अपने अपने विचार रखे। बहुत सारी बातों के संबंध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए उनकी तसल्ली करवाने की पूरी पूरी कोि ा ा की है। आज सिर्फ इस बजट में अलग अलग विभागों की मांगें 1 से 25 तक को पास करवाने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। आज जो चर्चा हुई है, उनमें काफी बातों का मुख्य मंत्री महोदय ने खुल कर जवाब देते हुए सभी की तसल्ली करवाने की कोि ा ा की है। लेकिन इनके साथ साथ मैं इस सदन में एक वि वास दिलाऊंगा कि जब से हमारी कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनी है, उसके बनने के बाद हरियाणा के हर व्यक्ति को राहत महसूस होने लगी है। हर व्यक्ति आजादी और सुख का सांस लेने लगा है। चाहे ला एण्ड आर्डर का मसला हो, चाहे प्रदे ा के विकास का मसला हो, चाहे टैक्स का मसला हो, वैसे हमने कोई नया टैक्स तो लगाया ही नहीं बल्कि घटाया ही है। इन सब बातों को देख कर हर व्यक्ति खु ा है। विकास के काम चारों ओर हो रहे हैं। इसलिए हर विधायक, चाहे वह पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, ये सभी अपने अपने हल्कों से संबंधित हैं चाहे कोई विकास का मसला है, चाहे माईनर्ज का मसला हो, चाहे हस्पतालों का मसला

हो, सभी खुलकर यहां पर कह रहे हैं और कहेंगे क्योंकि उनकोइस सरकार के राजय में विकास कर्य होते दिखायी दे रहे हैं आज विपक्षी सदस्य भी स्कूलों को अपग्रेड कने की बात बात यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सरकार से इन्हें इंसाफ अव य मिलेगा और स्कूल्ज भी अपग्रेड होंगे। सामने वाली पार्टी की पहली वाली सरकार से और न ही विकास पार्टी के नेता जो बैठे हैं, इन लोगों की सरकार से लोग स्कूलों को अपग्रेड नहीं करवा सके। आज विकास के जितने कार्य हो रहे हैं, यह सब इसी मौजूदा सरकार की ही देन है। आज सारे प्रदे ा के लोग इसी कारण से इस सरकार से खु ा हैं हम यह वि वास दिलाते हैं कि सभी हल्कों में, चाहे किसी विपक्षी विधायक का हल्का हो, सभी में बराबर के तरक्की के काम करवाए जाएंगे और करवाए भी जा रहे हैं। यह सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, स्कूल्ज अप ग्रेडे ान का मसला हो, माईनर्ज का मसला हो, हस्पतालों का मसला हो, हमारी सरकार इस मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं बरतेगी। कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं और यह मानना भी होगा कि स्टेट के पास जितने अपने साधन हैं, उन्हीं के अनुसार धीरे धीर हर हल्के में विकास कार्य होते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई भाईयों ने एस0वाई0एल0 नहर बनाने व उसका पानी हरियाणा तक पहुंचाने की बात भी कह दी और साथ में 20 करोड रूपए का भी जिक्र कर दिया। हमारी सरकार ने आते ही यह वि वास दिलाया था कि हम एस0वाई0एल0 नहर का पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचाएंगे

जिसके लिए हम कृत संकल्प भी हैं। इनकी सरकार काफी देर तक रही, ये एस0वाई0एल0 का पानी नहीं ला सके लेकिन हमारी सरकार अपनी निर्धारित अवधि तक, इस एस0वाई0एल0 का पानी किसानों को लाकर देगी।

इससे आगे मैं पुलिस के बारे में कुछ कहूंगा। वैसे पुलिस के बारे में पहले ही मुख्य मंत्री महोदय ने काफी बातें कह दी हैं, मैं एक दो बात कहना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार से हमें इस संबंध में सहायता मिलनी थी, वह नहीं आई है। इसके लिए 1992–93 के बजट में हमने पहले से कहीं ज्यादा प्रावधान रखा है, जिसकी की वजह से पुलिस का मनोबल काफी बढा है। बजट से अलग, हमने इस काम के लिए 15.36 लाख रूपयों की रा ि ा का पुलिस के कामों के लिए प्रावधान किया हैं बार्डर एरियाज में हमने अलग से पुलिस चौकियां स्थापित की हैं ताकि हरियाणा के अंदर उग्रवाद न पनप सके। इसके साथ साथ हमने यह भी प्रावधान किया है कि उग्रवाद के कारण जिस सिपाही, हवलदार या थानेदार की अचानक मृत्यु हो जाती है तो सरकार सिपाही के परिवार को 1 लाख, हवलदार के परिवार को 2 लाख और थानेदार के परिवार को 3 लाख रूपए की रा ि ा देगी ताकि पुलिस वालों का मनोबल ऊंचा हो और अपने प्रदे ा के हर व्यक्ति की जानमाल की रक्षा खु ी से कर सकें। इसी इरत राज पत्रित अधिकारी के परिवार को पांच लाख रूपया दिया जाता है। इसके अलावा उसके परिवार को उसकी रिटायरमैंट तक पूरी तनखाह दी

जाती है। हम किसी कीमत पर हरियाणा में ला एंड आर्डर की पोजी ान खराब नहीं होने देंगे। हमने अपनी पुलिस का मौरल ऊंचा रखा है और इसी वजह से हमारी पुलिस हरियाणा की सेवा कर रही है। यहां पर माननीय सदस्यों ने जो भी भावनउएं प्रस्तुत की, सरकार उनकी कद्र करती है। हम उनकी भावनाओं पर पूरी सहानुभूति से विचार करेंगे। अब मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक से पच्चीस तक की जो डिमांडज हैं, उनको युनानी मसली पास कर दिया जाए ताकि अगले साल की मांगें पूरी हो सकें। स्पीकर साहब, एक बात चुंगी के बारे में कहना चाहता हूं जो मुझे अभी राम भजन जी ने याद दिलाई है। हमने चुंगी खत्क करने के लिए एक सब कमेटी बनाई है। वह कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी इसमें जहां कमेटियों को पांच करोड रूपए सालना नुकसान का सवाल है, वहां पांच हजार मुलाजिमों का भी सवाल है। इस बारे में हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं। व्यापारियों को टैक्स रिलीफ देने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, उसका भी हम बहुत जल्दी रिपोर्ट आने पर फैसला करेंगे। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Hon. Members, now voting on demands on the Budget for the year 1993-94 will take place.

First I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demand to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 22588000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 1 on demand No. 2 given by Shri Bansi Lal to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 523465000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 2- General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 2 on demand No. 3 given by Shri Bansi Lal to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1521798000 for revenue expenditure and Rs. 40000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 3- Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 400438000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 4- Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 3 on demand No. 5 given by Shri Ram Bhajan to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 134096000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1993-94 in respect of charges under Demand No. 5- Excise & Taxation.

The motion was carried.

Demand Nos. 6 to 8

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1098652000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 6- Finance.

That a sum not exceeding Rs. 2047584000 for revenue expenditure and Rs. 800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 735452000 for revenue expenditure and Rs. 753718000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 8- buildings and Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 4 on demand No. 9 given by Sarvshri Bani Lal, Amar Singh and Chhattar Singh Chauhan to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 467545000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 5 मिनट और बढाया जाता है।

वर्श 1993–94 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

16.00 बजे।

Demand No. 10

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No.5 on demand No. 10 given by Shri Chhattar Singh Chauhan to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 2009310000 for revenue expenditure and Rs. 426200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 10- Medical and Public Health.

The motion was carried.

Demand Nos. 11 & 12

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 132697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 11- Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 289969000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 12- Labour and Employment.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 6 on demand No. 13 given by Shri Amar Singh to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1922615000 for revenue expenditure and Rs. 35431000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.

The motion was carried.

Demand No. 14

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 66902000 for revenue expenditure and Rs. 1965166000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 14- Food and Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 7 on demand No. 15 given by Shri Chhattar Singh Chauhan to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 3022060000 for revenue expenditure and Rs. 886840000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 265901000 for revenue expenditure and Rs. 93240000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 16- Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker: Now I put the cut motion No. 8 on demand No. 17 given by Shri Amar Singh to the vote of the House.

That the demand be redeuced Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1062710000 for revenue expenditure and Rs. 2000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 17- Agriculture.

The motion was carried.

Demand Nos. 18 to 25

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 346402000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 48497000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 19- Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 537524000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 20- Forest.

That a sum not exceeding Rs. 763476000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 21- Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 129182000 for revenue expenditure and Rs. 89187000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 22- Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 2304828000 for revenue expenditure and Rs. 355400000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 23- Transport.

That a sum not exceeding Rs. 8423000 for revenue expenditure and Rs. 24000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 24- Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2765836000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1993-94 in respect of charges under Demand No. 25- Loans & Advances of State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 12th March, 1993.

16.39 P.M.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.ma. on Friday, the 12th March, 1993.)